चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

22 जुलाई–28 जुलाई 2013

फिर एक बार कछुआ और खरगोश

कौन कछुआ कौन खरगोश

अगर आप यह समझते हैं कि राजनाथ सिंह ने बड़ी उदारता से नरेंद्र मोदी को भाजपा की चुनाव प्रचार समिति का प्रभारी बनाकर उनके लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की राह आसान कर दी है, तो यह आपकी भूल है. दरअसल, राजनाथ सिंह की यह चाल, अपनी राह से सभी रोड़े हटाने की थी. राजनाथ सिंह ने बड़ी ही चालाकी से अपनी बिसात बिछाई और उस पर मोदी के बहाने लालकृष्ण आडवाणी को कुर्बान कर दिया. ऐसे में सुषमा स्वराज एवं अरुण जेटली खुद-ब-खुद पीछे खड़े हो गए. नरेंद्र मोदी के नाम पर मची ग़दर में राजग बिखर गया, लेकिन राजनाथ ने चुप्पी साधे रखी. और अब, जबकि सब कुछ राजनाथ सिंह की नीयत केहिसाब से हो रहा है, तब वह बेहद होशियारी के साथ नरेंद्र मोदी की काट में लग चुके हैं.

रूबी अरुण

राजनाथ सिंह दरअसल, खुद को अटल बिहारी वाजपेयी की जगह स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोलने में माहिर हैं और पार्टी में सबको स्वीकार्य भी हैं. स्वीकार्यता के इसी खेल में वह बड़ी ही सफाई से नरेंद्र मोदी को मात देना चाहते हैं. लखनऊ से चुनाव लड़ने की उनकी सोच इसी रणनीति का हिस्सा है. अपनी योजना को सफल बनाने के लिए राजनाथ सिंह न सिर्फ़ कुशल सियासी दांव-पेंच चल रहे हैं, बल्कि वह पंडितों एवं ज्योतिषियों की मदद भी ले रहे हैं. पूजा-पाठ और तंत्र-मंत्र के ज़रिए देश के सियासी हालात अपने पक्ष में करने की कोशिशें भी हो रही हैं. ग्रह-नक्षत्रों की चाल की गणना बैठाकर यह जुगत भी लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव अपने तय वक़्त से पहले, यानी इसी साल नवंबर में ही हो जाए. इसके लिए किसी ऐसे मुद्दे की तलाश की जा रही है, जिसे हवा देकर संसद के शीतकालीन सत्र में इतना उबाल पैदा कर दिया जाए कि या तो संसद भंग कर दी जाए, या फिर दबाव में आकर यूपीए सरकार चुनाव की घोषणा कर दे.

और यह सब कुछ इसलिए, ताकि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखे जाने वाले नरेंद्र मोदी के पास इतना समय ही न रहे कि वह अपने नाम पर लोगों को एकमत कर सकें या अपनी जीत पक्की करने की खातिर टीम की रणनीति बना सकें. अगर राजनाथ सिंह के मंसूबों के मुताबिक़ आम चुनाव नवंबर में हो जाते हैं, तो यकीनन नरेंद्र मोदी वक़्त की कमी के कारण गुजरात दंगों के चलते बनी अपनी विभाजनकारी नेता की छवि बदल पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे. और तब ऐसेअगर

“राजनाथ सिंह यह बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ही तय करेगा और उन्हें यह भी मुगालता है कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश से उनसे बेहतर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता. हालांकि नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश भी लखनऊ से ही चुनाव लड़ने की थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने उन्हें हिंदुत्व और धर्म नगरी का हवाला देते हुए बनारस की लोकसभा सीट से लड़ने को तैयार कर लिया.”

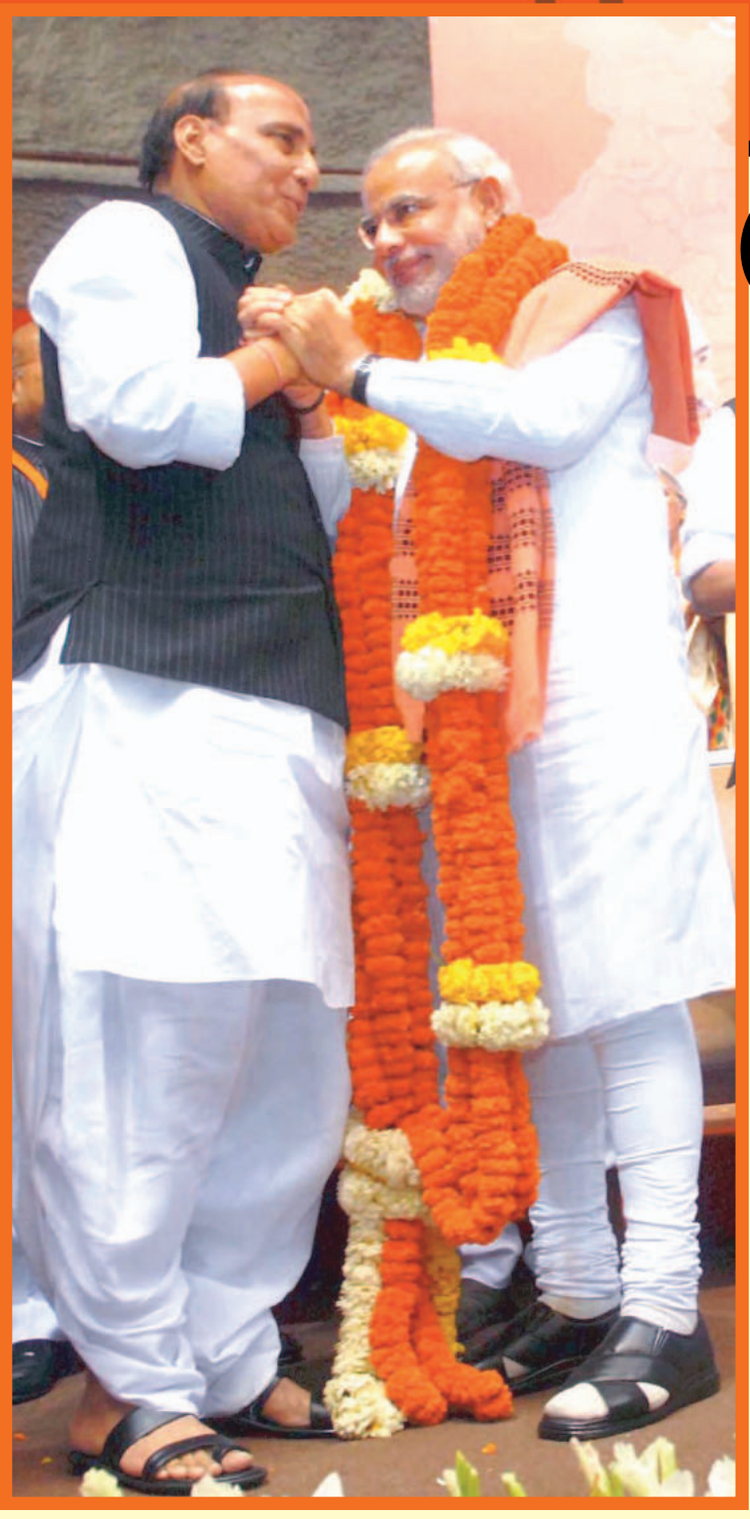

“नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहकर भी राजनाथ सिंह किस सफाई से उनकी जड़ें काट रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि राजनाथ सिंह के मोदी नाम के जाप से भाजपा की प्रचार समिति के प्रभारी मोदी का कद अचानक पार्टी से बड़ा हो चुका है, जबकि भाजपा में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था. भाजपा के इतिहास में पहले कभी इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी में चुनाव केसाल भर पहले किसी भी नेता को चुनाव प्रचार समिति की कमान नहीं दी गई थी!”

राजग किसी तरह सत्ता के नज़दीक पहुंच भी जाता है, तब भी शायद नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों में एक राय न बन सके. ऐसी आनन-फानन और रस्साकशी की स्थिति में राजनाथ सिंह के लिए बेहद आसान यही होगा कि वह अचानक अपना सिर ताजपोशी के लिए आगे कर दें. इस बात से इत्तेफाक न रखने वालों के लिए, इस संदर्भ में यहां यह याद रखना बेहद मौजूं और मुनासिब होगा कि कैसे, ऐसे ही तिकड़मों के बूते राजनाथ सिंह अचानक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे.

नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहकर भी राजनाथ सिंह किस सफाई से उनकी जड़ें काट रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि राजनाथ सिंह के मोदी नाम के जाप से भाजपा की प्रचार समिति के प्रभारी मोदी का कद अचानक पार्टी से बड़ा हो चुका है, जबकि भाजपा में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था. भाजपा के इतिहास में पहले कभी इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी में चुनाव के साल भर पहले किसी भी नेता को चुनाव प्रचार समिति की कमान नहीं दी गई थी! न ही पहले कभी इस मसले पर पार्टी के किसी अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड ने इतनी ज़द्दोज़हद की थी, क्योंकि अमूमन चुनाव होने के चार-पांच महीने पहले भाजपा में यह ज़िम्मेदारी तय करने की परंपरा-सी रही है. वैसे, अब पार्टी के ज़्यादातर लोग राजनाथ सिंह के मकसद के पीछे के निहितार्थ जानने और समझने लगे हैं. इतनी बात तो भाजपा के शीर्ष नेताओं की समझ में आ चुकी है कि राजनाथ सिंह अब खुद को अटल बिहारी वाजपेयी समझने लगे हैं. जिस लखनऊ से अटल जी ने सात बार चुनाव लड़ा और पांच बार विजय हासिल की, उस जगह को वह अपने नाम करना चाहते हैं. हालांकि ज्योतिषों एवं पंडितों की सलाह

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा?

03

...लेकिन किधर जाएंगे मुसलमान

05

सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे : अन्ना

07

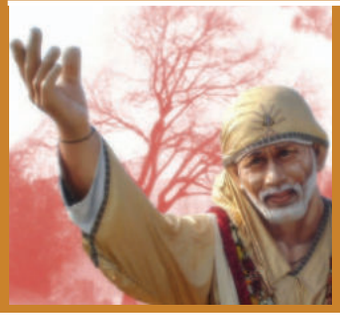

साई की महिमा

12

कौन कछुआ, कौन खरगोश

पृष्ठ एक का शेष

पर उनका मन कुछ डगमगा भी रहा है, क्योंकि उनके ज्योतिषों की गणना यह कहती है कि अगर वह लखनऊ की बजाय अंबेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी भारी जीत पक्की है.

राजनाथ सिंह यह बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ही तय करेगा और उन्हें यह भी मुगालता है कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता. हालांकि नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश भी लखनऊ से ही चुनाव लड़ने की थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने उन्हें हिंदुत्व और धर्म नगरी का हवाला देते हुए बनारस की लोकसभा सीट से लड़ने को तैयार कर लिया. जो लोग राजनाथ सिंह को जानते हैं, उन्हें यह बात अच्छी तरह मालूम है कि राजनाथ सिंह को कांटे से कांटा निकालना खूब आता है. जब राजनाथ सिंह केंद्र में भूतल परिवहन मंत्री थे, तब भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने केशरीनाथ त्रिपाठी, कलराज मिश्र एवं लालजी टंडन को दरकिनार कर मुख्यमंत्री का पद हथिया लिया था. राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कल्याण सिंह के ख़िलाफ़ ऐसा माहौल बना दिया कि वह सीधे-सीधे अटल बिहारी वाजपेयी से बगावत कर पार्टी से बाहर हो गए.

इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फिलहाल राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी को सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. इन दिनों खुद को उदारवादी नेता के रूप में पेश कर रहे राजनाथ सिंह को मालूम है कि नरेंद्र मोदी को भाजपा की चुनावी रणनीति के केंद्र में रखने से देश की राजनीति में ज़बरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा. खासकर, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में, जहां अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी है और जो लोकसभा सीटों के नतीजे तय करती है. वहां यह ध्रुवीकरण निर्णायक साबित होगा और तब देश का अगला लोकसभा चुनाव सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और तब ऐसी स्थिति में, भाजपा में जो सेक्युलर चेहरा नज़र आएगा, वह राजनाथ सिंह का ही होगा. हालांकि तब मोदी को उनकी विकास पुरुष वाली छवि का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा. और ये हालात कांग्रेस को भी बहुत

भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता कहते हैं कि दरअसल, राजनाथ सिंह ने यह सारा गुणा-भाग करने के बाद ही मोदी का नाम आगे किया है, क्योंकि वह कतई यह नहीं चाहते कि भाजपा की असफलता का ठीकरा उनके माथे फूटे. अगर भाजपा की हार होती है, तो यह कलंक मोदी के ही नाम लगे. इन्हीं आशंकाओं से त्रस्त होकर पहली बार संघ ने भाजपा की चुनावी राजनीति में सीधा दखल दिया है और इस बात के साफ़ संकेत भी दिए कि कोई भी कार्यकर्ता या नेता संघ या पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, भले ही वह नरेंद्र मोदी ही क्यों न हों.

रास आएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार, महंगाई और घोटालों के आरोपों से जूझ रही कांग्रेस भी सेक्युलरिज्म की ओट में अपने सारे गुनाह छिपाने की कोशिश करेगी. दूसरी संभावना यह भी बनती है कि इस ध्रुवीकरण और बनारस की गंगा-जमुनी तहजीब के समीकरणों की वजह से अगर नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हार जाते हैं, तब राजनाथ सिंह के लिए उनकी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर दावेदारी और भी आसान हो जाएगी. दरअसल, राजनाथ सिंह इन दिनों मोदी के नाम की माला जपकर उनका भला नहीं कर रहे, बल्कि वह ऐसा करके मोदी विरोधियों को और हवा दे रहे हैं. राजनाथ सिंह इन दिनों न तो राम मंदिर के मसले पर कुछ बोल रहे हैं और न ही कट्टर हिंदूवाद का समर्थन कर रहे हैं. अल्पसंख्यकों से जुड़े मसलों पर भी राजनाथ सिंह का रुख लचीला ही नज़र आ रहा है, जिसकी बानगी हालिया दिनों में खूब दिखी. मतलब यह कि राजनाथ सिंह बड़े सधे और नपे-तुले अंदाज़ में अपनी महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ा रहे हैं.

जब नरेंद्र मोदी के खासमखास अमित शाह उत्तर प्रदेश जाकर राम मंदिर का मसला उछालते हैं, तो राजनाथ चुप रहते हैं. वहीं जयपुर में अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर आयोजित सेमिनार में जाकर वह मुसलमानों के प्रति अपने लचीले रुख का भी प्रदर्शन कर आते हैं. राजनाथ सिंह जानते हैं कि भाजपा का जनाधार लगातार खिसक रहा है, जिसे थामे रखना उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है. लिहाज़ा, खुद को बचाते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही एनडीए का दायरा बढ़ाने की अग्नि परीक्षा में झोंक दिया है. नरेंद्र मोदी की वाहवाही करके, उन्हें पार्टी का सबसे दमदार नेता बताकर राजनाथ सिंह ने किस चालाकी से उन्हें दुरुह स्थितियों में फंसाया है, इसका अंदाजा फिलहाल नरेंद्र मोदी को भी नहीं है.

गौर कीजिए. अभी तक भाजपा तीन बार केंद्र की सत्ता पर काबिज़ हो चुकी है, लेकिन उसे लोकसभा में कभी बहुमत नहीं मिल सका. वह दो सौ सीटों से ऊपर कभी नहीं जा पाई. उस पर तुर्रा यह कि 2004 के बाद से एनडीए का कुनबा लगभग बिखरता जा रहा है. सहयोगी दल एक-एक कर गठबंधन से अलग होते जा रहे हैं. अभी एनडीए में शिवसेना, हरियाणा जनहित कांग्रेस, असम गण परिषद और अकाली दल ही भाजपा के साथ हैं. ज़ाहिर है, मोदी को पुराने साथियों को अपने साथ बनाए रखने के अलावा, नए साथियों की तलाश करने की भारी मशक्कत करनी पड़ेगी. पुराने साथी रहे नवीन पटनायक एवं ममता बनर्जी की वापसी के कोई संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं. उस पर भाजपा ने हिमाचल, उत्तराखंड एवं कर्नाटक में अपनी सत्ता गंवाई ही है. अगर हम लोकसभा सीटों के आधार पर भी आकलन करें, तो हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 42, उड़ीसा की 21, आंध्र प्रदेश की 42, केरल की 20 और तमिलनाडु की 39, यानी कुल 174 सीटों पर भाजपा की मौजूदगी शून्य है. पूर्वोत्तर राज्यों और असम में भी पार्टी की उपस्थिति नाममात्र है. ये सारे हालात मोदी के लिए ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं, जिनसे पार पाना असंभव नहीं है, लेकिन बेहद मुश्किल ज़रूर होगा. बात यहीं ख़त्म नहीं होती. नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपा कर उनके साथ हमक़दम होकर भी राजनाथ सिंह उनके लिए किस क़दर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, इसकी बानगी राजनाथ सिंह के बयान से देखिए. राजनाथ सिंह फरमाते हैं कि चुनाव से पहले गठबंधन करने की भाजपा की कोई योजना नहीं है. अब बिना गठबंधन किए भला मोदी के नेतृत्व में क्या भाजपा आंकड़ा छू पाएगी?

संघ भी कमोबेश इस बात से परिचित है, लिहाज़ा वह अभी भी मोदी के पक्ष में खुलकर सामने नहीं आ रहा. केंद्र में भाजपा की पहली सरकार महज़ तेरह दिन ही चल पाई थी. वह बहुमत के जादुई आंकड़े नहीं जुटा पाई थी, जबकि उसके पास अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उदारवादी चेहरा था. दूसरी बार भी भाजपा सरकार का कार्यकाल सिर्फ़ तेरह महीने चल सका. तीसरी बार भाजपा सरकार ने पूरे कार्यकाल तक राज तो किया, लेकिन उसके पास अपनी केवल 183 सीटें थीं. 2009 में जब भाजपा लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरी, तब उसके पास 2004 में मिली कुल 137 सीटें थीं, फिर भी भाजपा के हिस्से में लोकसभा की सिर्फ़ 116 सीटें आ सकीं. ज़ाहिर है, इस लिहाज़ से नरेंद्र मोदी के सामने इस बार चुनौतियां बहुत बड़ी हैं. उस स्थिति में भी, जब भाजपा अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े और उसे पिछली बार की तरह 543 में से 365 सीटों पर ही संतोष करना पड़े और बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ देनी पड़ें. अगर गठबंधन का विस्तार भी किया जाता है, तो भी ऐसे में 200 के आंकड़े को 272 के जादुई आंकड़े तक ले जाना बेहद मुश्किल ही होगा.

ऐसे में यह सवाल सहज उठता है कि पार्टी को भला कैसे सीटें प्राप्त होंगी, कैसे कोई शेष सांसदों का प्रबंध करेगा और कैसे मोदी के नाम पर आवश्यक सहमति बनेगी? अगर यह मान भी लिया जाए कि मोदी की अगुवाई में 180 सीटें आ भी जाती हैं, तो क्या ऐसे में गठबंधन की सरकार बन पाएगी? मुस्लिम वोट के लालच में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी एवं नवीन पटनायक मोदी से जो दूर चले गए, क्या वे वापस आएंगे? राजनाथ सिंह इस चुनावी जोड़-गणित का पूरा हिसाब लगाकर ही अपनी बाज़ी मोदी के नाम से खेल रहे हैं. दो दिनों पहले ही अपने एक बेहद क़रीबी ज्योतिषी मित्र से मंत्रणा करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत में भाजपा कोई बड़ी ताक़त तो है नहीं. नरेंद्र मोदी ने अपने जिस खास आदमी अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा है, वह इतने कम समय में सपा और बसपा की पकड़ वाले इलाकों की ज़मीनी हकीक़त भला कैसे बदल पाएंगे. ऐसे में मोदी की लड़ाई बेहद कठिन हो जाएगी.

भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता कहते हैं कि दरअसल, राजनाथ सिंह ने यह सारा गुणा-भाग करने के बाद ही मोदी का नाम आगे किया है, क्योंकि वह कतई नहीं चाहते कि भाजपा की असफलता का ठीकरा उनके माथे फूटे. अगर भाजपा की हार होती है, तो यह कलंक मोदी के नाम ही लगे. इन्हीं आशंकाओं से त्रस्त होकर पहली बार संघ ने भाजपा की चुनावी राजनीति में सीधा दखल दिया है और इस बात के साफ़ संकेत भी दिए कि कोई भी कार्यकर्ता या नेता संघ या पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, भले ही वह नरेंद्र मोदी ही क्यों न हों. संघ आज की तारीख में भाजपा को अपने हिसाब से चलाना चाहता है. राजनाथ सिंह को संघ का भरोसा हासिल है, क्योंकि भाजपा के बड़े नेताओं में से एक सिर्फ़ वही हैं, जिन्होंने कभी संघ का साथ नहीं छोड़ा.

ऐसा भी नहीं है कि मोदी इन सारी बातों से पूरी तरह अनजान हैं. उन्हें अंदाजा है अपनी चुनौतियों का. लिहाज़ा, उन्होंने भी बगैर किसी शोर-शराबे के अपनी छवि बदलना शुरू कर दिया है. अब मोदी के भाषणों में कॉमन सिविल कोड, अयोध्या और अनुच्छेद 370 जैसे विवादास्पद मुद्दे नहीं होते. वह गुजरात में सद्भावना यात्रा पर निकले हैं. मुस्लिम विज़न डॉक्युमेंट्री बना रहे हैं. मुस्लिम सम्मेलन भी कर रहे हैं. वह हिंदूवाद और उदारवाद का मिला-जुला चेहरा बनाना चाहते हैं. मोदी के बारे में चाहे जितनी आशंकाएं ज़ाहिर की जाएं, पर वह खुद को लेकर बड़े आश्वस्त दिखते हैं. वह हर तरह से राजनीतिक लहर पैदा करने की कोशिश में हैं, जबकि दूसरी ओर राजनाथ सिंह बड़े इत्मीनान से मोदी के नाम को हवा देने में लगे हैं. राजनाथ सिंह को मालूम है कि गणित भाजपा के पक्ष में नहीं है. भाजपा अगर हार जाती है तब, या फिर बमुश्किल सहयोगी दलों के सहारे वह सरकार बनाने की स्थिति में आती है तब, दोनों ही सूरतों में मोदी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल दिख रहा है. और दोनों ही स्थितियों में राजनाथ सिंह के लिए प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान हो जाएगा.

इस तरह राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच एक बार फिर कछुआ और खरगोश वाली कहानी दोहराई जाएगी. अब देखना यह है कि कौन कछुआ साबित होगा और कौन खरगोश? ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 20
दिल्ली, 22 जुलाई-28 जुलाई 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
6452888
011-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

ट्राई प्रमुख के पद पर आईएएस नहीं!

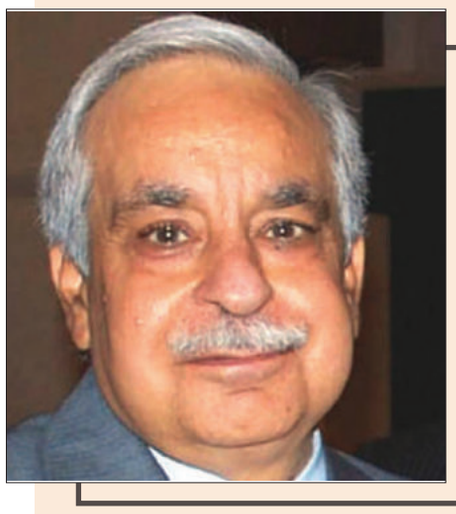

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के प्रमुख राहुल खुल्लर ने सलाह दी है कि उनके बाद इस पद को जो अधिकारी संभाले, वह आईएएस लॉबी से न हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा. खुल्लर की इस सलाह से आईएएस अधिकारियों की भौहें तन गई हैं. उनमें इस बात को लेकर अंदर ही अंदर बहस भी छिड़ गई है. खुल्लर की तरह ट्राई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप बैजल, नृपेंद्र मिश्रा एवं जे एस सरना आईएएस पृष्ठभूमि के थे. उक्त सभी अधिकारी ट्राई में नियुक्ति से पूर्व दूरसंचार सचिव के रूप में काम कर चुके थे.

ग़ौरतलब है कि आईएएस की तुलना में भारतीय राजस्व सेवा एवं दूरसंचार सेवा के अधिकारियों को ट्राई में सेवाएं देने के अवसर बहुत ही कम मिले हैं. फिलहाल खुल्लर के बयान को ट्राई में आईएएस पृष्ठभूमि वाले लोगों के मुकाबले अन्य पृष्ठभूमि वाले लोगों की नियुक्ति के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है. ■

बदले की कार्रवाई

मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी राजेश राजोरा को उस समय संकट का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने एक आयकर अधिकारी को नज़रअंदाज कर दिया था. ग़ौरतलब है 2008 में राजोरा गृह सचिव थे. साथ ही उन्हें केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए आवास आवंटन का ज़िम्मा भी दिया गया था. कहा जाता है कि उसी समय आयकर निदेशक एस एस राणा ने खुद के लिए सरकारी आवास आवंटन करने को राजोरा से कहा था, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था. सूत्रों का कहना है कि राणा को सरकारी आवास मुख्यमंत्री की पैरवी के बाद ही मिला. यहीं से राणा एवं राजोरा में विवाद गहरा होता गया. इसके बाद राणा ने राजोरा के ख़िलाफ़ आयकर छापे का आदेश दे दिया, फलस्वरूप राजोरा 33 माह तक निलंबित रहे. उच्च न्यायालय ने अब राजोरा को दोषमुक्त कर दिया है और कहा कि राजोरा के ख़िलाफ़ आयकर छापे की कार्रवाई आयकर अधिकारी को सरकारी आवास आवंटित न करने के कारण की गई थी. छापे की कार्रवाई के पीछे न तो कोई ठोस कारण था और न ही पर्याप्त आधार. न्यायालय के फ़ैसले पर राजोरा ने खुशी जताई है. ■

अधिकारियों की आपसी जंग

पिछले दिनों बिहार के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को रंगदारी मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था. उक्त अधिकारी का दावा है कि उन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फंसाया गया है. 1997 बैच एवं जम्मू-कश्मीर कैडर के आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीआईजी आलोक कुमार ने राज्य पुलिस प्रमुख अभयानंद सहित दो इंस्पेक्टर जनरल अमित कुमार एवं प्रवीण वशिष्ठ के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया है. उन्होंने इन अधिकारियों पर जांच के दौरान जातिवाद का आरोप लगाया है. इस निलंबित अधिकारी ने पटना के कुछ नौकरशाहों को भी अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उनके द्वारा दर्ज कराया गया मुकदमा खारिज हो गया है. अब आलोक कुमार पर ही दबाव बनाने के लिए मुकदमा दायर कराने के प्रयास का मामला बन गया है. हालांकि आलोक कुमार का कहना है कि वह अपना संघर्ष जारी रखेंगे. आलोक कुमार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर राज्य पुलिस प्रमुख अभयानंद ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है. ऐसे में, जब तक उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, अधिकारियों के इस मामले के सुलझने की कोई संभावना नहीं दिखती. ■

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

कृष्णनन अतिरिक्त सचिव
1983 बैच एवं कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी के पी कृष्णनन आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग के अतिरिक्त सचिव होंगे. वह इस समय नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं.

संजय संयुक्त सचिव बनेंगे
1994 बैच के आईएएस अधिकारी संजय लोहिया कृषि एवं सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव बनाए जाएंगे. वह इस समय पीएमओ में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. संजय
1985 बैच एवं हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी संजीव गुप्ता का स्थान लेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था विभाग में मिशन निदेशक बनाया गया है.

श्रीवास्तव पीएमआई (डब्ल्यूटीओ) के पहले सचिव
1992 बैच के आईआरएस वी के श्रीवास्तव जेनेवा स्थित परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के पहले सचिव हो सकते हैं.

अभिषेक बनेंगे उप-निदेशक
अभिषेक स्वामी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी, मसूरी का उप-निदेशक बनाया जा सकता है.

प्रदीप निदेशक बने
1990 बैच के आईओएफएस अधिकारी प्रदीप कुमार दास को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का निदेशक बनाया गया है. उन्होंने 1992 बैच एवं केरल कैडर के आईएफएस राजन सहगल का स्थान लिया. ■

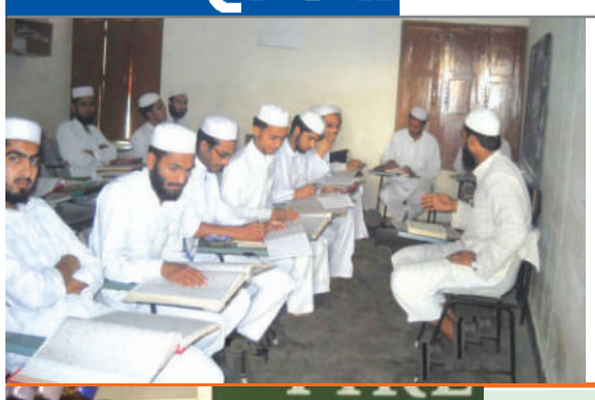

> वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य देखकर यह बात साफ़ होने लगी है कि सभी कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी है. दूसरी ओर, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत भाजपा के सभी सहयोगी कट्टर हिंदूवादी संगठनों ने यह घोषणा कर दी है कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में ही होगा.

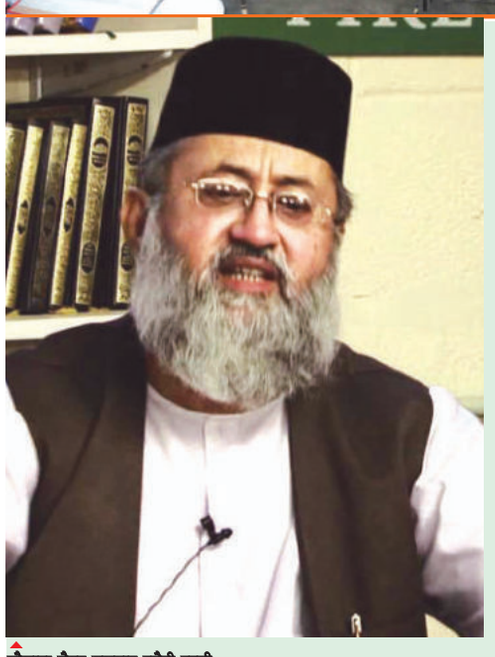

मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी

हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राज्य या धर्मनिरपेक्ष देश

भारत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा?

एक ओर जहां संघ और उसके सहयोगी संगठनों का ख्वाब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के एक वर्ग में देश को मुस्लिम रियासत बनाने की मानसिकता भी पनप रही है. मुसलमानों में इस बात को लेकर गहरी निराशा है कि देश को आज़ाद हुए 65 साल बीत गए, लेकिन अब तक कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बना. यह संभव कैसे हो? मुसलमानों में न तो कोई मज़बूत राजनीतिक नेतृत्व मौजूद है और न ही उनकी ऐसी कोई पार्टी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव रखती हो, सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है. ऐसे में मुसलमानों की ओर से एक नया राजनीतिक मोर्चा खड़ा करने की तैयारी चल रही है. दिलचस्प बात यह है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखने वालों ने जैसी योजना बनाई है, लगभग वैसी ही योजना मुस्लिम राज्य बनाने का ख्वाब देखने वालों की भी है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना रहेगा?

नरेंद्र मोदी

डॉ. क़मर तबरेज़

लोकसभा चुनाव आने वाला है. देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है. लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए कट्टर हिंदुओं एवं मुसलमानों ने देश की सत्ता पर काबिज़ होने के लिए उत्तर प्रदेश को अपना राजनीतिक रणक्षेत्र बना लिया है. एक ओर जहां देश में सांप्रदायिकता के अग्रदूत नरेंद्र मोदी ने अपने सिपहसालार अमित शाह को उत्तर प्रदेश भेजकर हिंदुओं को मानसिक रूप से तैयार करने में लगा दिया है, वहीं दूसरी ओर नदवातुल उलेमा के मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी एक बार फिर मुसलमानों का राजनीतिक मोर्चा खड़ा करने की जुगत में लगे हुए हैं. मोदी के काम में जहां एक ओर देश का पूरा नेशनल मीडिया सहयोग दे रहा है, वहीं दूसरी ओर सलमान नदवी के मीडिया विंग की ज़िम्मेदारी अज़ीज़ बर्नी ने संभाल ली है. मोदी की सियासी चालों का ज़िक्र तो हर ओर हो रहा है, लेकिन सलमान नदवी की तैयारियों की जानकारी अभी देश के अधिकतर लोगों को नहीं है. दरअसल, चौथी दुनिया देश की जनता को इस सच्चाई से रू-ब-रू कराना चाहता है.

लखनऊ के मशहूर धार्मिक संस्थान नदवातुल उलेमा के स्कॉलर एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने बीते 8 मई को दक्षिणी दिल्ली में निर्दलीय राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब के निवास पर मुस्लिम नेताओं एवं उलेमाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई. इस बैठक में जमीअत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव एवं पूर्व सांसद मौलाना सैयद मुहमद मदनी, असम यूडीएफ के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल के अफ़ज़ाल अंसारी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. मुजतुबा फ़ारूक़, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य एवं वेलफेयर पार्टी के उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुशावरत (सैयद शहाबुद्दीन) के अध्यक्ष डॉ. ज़फ़रुल इस्लाम, तंज़ीम उलेमा-ए-हक़ के अध्यक्ष डॉ. एजाज़ उफी, मुस्लिम मजलिस मुशावरत (मौलाना सालिम क़ासमी) के इलियास मलिक, राहत महमूद चौधरी, ज़ेड के फैज़ान, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव डॉ. तस्लीम रहमानी, मौलाना याक़ूब बुलंदशहरी और अज़ीज़ बर्नी के अलावा, लगभग सौ महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए. बैठक में इस बात पर गंभीरता से विचार किया गया कि क्या देश के मुस्लिम नेतृत्व में कोई राजनीतिक मोर्चा (इसे हम तीसरा मोर्चा भी कह सकते हैं) खड़ा किया जा सकता है या नहीं.

मौलाना सलमान नदवी ने मोहम्मद अदीब के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, जिसमें मौलाना मुहमद मदनी एवं बदरुद्दीन अजमल के अलावा, दूसरे प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, ताकि वे धार्मिक प्रतिनिधियों के अलावा, मुस्लिम विचारकों के साथ इस बात पर विचार करें. अंतिम निर्णय यह लिया गया कि पूरे देश में न सही, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ज़रूर करनी चाहिए और फिर बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम में यह काम आगे बढ़ाना चाहिए. इसके लिए इन मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अपना एक राजनीतिक घोषणापत्र तैयार करने पर भी चर्चा की, जिसके शीघ्र ही सार्वजनिक होने की उम्मीद है. दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में अज़ीज़ बर्नी ने अपने भावनात्मक भाषण में कहा कि 65 सालों से हम मशविरा ही करते रहे और कोई निर्णय नहीं ले सके, जिसके चलते बड़ी-बड़ी सियासी पार्टियों ने हमारा शोषण किया है. वक्त का तक़ाज़ा है कि हम इस दिशा में क़दम बढ़ाएं और आगे बढ़ें. मुसलमानों के इन तथाकथित रहनुमाओं ने यह निर्णय भी लिया कि बाद में अगर माहौल शांतिपूर्ण रहा, तो कांग्रेस, भाजपा, बसपा एवं सपा को छोड़कर देश के बाकी छोटे-छोटे, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को भी अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी. यही वजह थी कि मोहम्मद अदीब के घर पर यह बैठक बुलाने से पहले अजित सिंह, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ए बी वर्धन एवं शरद यादव से भी संपर्क किया गया था.

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य देखकर यह बात साफ़ होने लगी है कि सभी कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी है. दूसरी ओर, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत भाजपा के सभी सहयोगी कट्टर हिंदूवादी संगठनों ने यह घोषणा कर दी है कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में ही होगा. मोदी ने अपने क़रीबी साथी अमित शाह को उत्तर प्रदेश भेजकर इस पूरी योजना की कमान संभालने के काम में पहले ही लगा दिया है. राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाकर भाजपा एक बार फिर देश में दंगे कराना चाहती है. दूसरी ओर कांग्रेस है, जिसे सब कुछ पका-पकाया मिल रहा है. दंगे होंगे, तो मुसलमान बेचारा भीख मांगने के लिए कांग्रेस के पास ही जाएगा कि हमारी जान बचाओ. यह सब देखते हुए देश के मुस्लिम नेताओं, ख़ासकर वे, जो न तो भाजपा में हैं और न कांग्रेस में, के अंदर यह इच्छा जाग उठी है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा राजनीतिक मोर्चा बनना चाहिए, जिसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बड़ी संख्या में तो हो ही, साथ ही उसके नेतृत्व का अवसर भी किसी मुस्लिम को ही मिले. मुसलमानों का राजनीतिक मोर्चा देश में बने, यह सोच किसकी थी, इसे जानने के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा.

मोहम्मद अदीब

मौलाना बदरुद्दीन अजमल

मौलाना मुहमद मदनी

अज़ीज़ बर्नी

मुज्तबा फ़ारूक़

अफजाल अंसारी

डॉ. ज़फ़रूल इस्लाम ख़ान

तसलीम रहमानी

दारूल उलूम नदवातुल उलेमा के मोहद्दिस एवं इस्लामी स्कॉलर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने एक साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जमीअतुल उलेमा हिंद से एक अपील शीर्षक से एक पंफलेट प्रकाशित किया था, जिस पर उन्होंने विभिन्न उलेमाओं एवं इमामों से हस्ताक्षर कराए थे और फिर उसे मस्जिदों एवं मदरसों समेत सूबे के मुसलमानों के बीच बंटवाया भी था. इस पंफलेट में एक जगह लिखा है कि हज़रत मौलाना असद मदनी के जीवनकाल में रामलीला ग्राउंड में दस लाख लोगों की मौजूदगी में मौलाना मुहमद मदनी ने मौलाना सलमान हुसैनी द्वारा हज़रत मौलाना असद मदनी एवं मौलाना अरशद मदनी के इशारे पर और सहमति से अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि के रूप में एक नई सियासी पार्टी का प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर मुसलमानों के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं रामलीला ग्राउंड में मौजूद लोगों ने जोश और जज़्बे के साथ सहमति भी जताई थी. आज मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी उस प्रस्ताव को लागू करने के दायरे में लाकर हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच एक मज़बूत एकता स्थापित कर चुके हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वह सभी मुसलमानों, खासकर जमीअतुल उलेमा पर जोर नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब, नदवी जमीअत उलेमा से अपील कर रहे हैं कि वह इत्तेहाद फ्रंट (एकता मंच) को खुले शब्दों में समर्थन देते हुए हिंदू-मुस्लिम एकता द्वारा मुसलमानों के विचारशील और नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा दे?

लगता है कि यही वह सूत्र है, जो मौलाना सलमान नदवी को बार-बार मुसलमानों को लेकर एक राजनीतिक मोर्चा खड़ा करने की प्रेरणा देता है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान असफलता हाथ लगने के बाद भी वह हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं. शायद इसीलिए वह देश में अगले लोकसभा चुनाव से पूर्व एक बार फिर यह राजनीतिक मोर्चा खड़ा करने के लिए प्रयासरत हैं. एक साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय मुस्लिम वोट पाने के लिए कई छोटी-छोटी पार्टियां वजूद में आई थीं, जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था. इन सभी पार्टियों में कोई न कोई मुस्लिम चेहरा ज़रूर था, लिहाज़ा, इस बात की आशंका थी कि मुस्लिम वोट बुरी तरह बंटेगा. इसका फ़ायदा किसी सांप्रदायिक पार्टी, खासकर भाजपा को न हो, यह सोचकर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने 14 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश में 26 पार्टियों का एक राजनीतिक मोर्चा इत्तेहाद फ्रंट (एकता मंच) बनाया. हैरानी की बात यह है कि इस फ्रंट में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी शामिल थी, जो इस समय पश्चिम बंगाल में सत्ता पर क़ाबिज़ है. यही नहीं, ममता स्वयं पहले केंद्र की यूपीए सरकार का हिस्सा रह चुकी हैं.

दरअसल, यह पहल नदवातुल उलेमा की रिवायत के ख़िलाफ़ थी. नदवा की चौखट पर बड़े-बड़े सियासी नेताओं की हाजिरी की एक लंबी सूची है, लेकिन नदवा ने खुद सियासत में कभी क़दम नहीं रखा. लिहाज़ा, मौलाना सलमान नदवी द्वारा 26 राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व का फ़ैसला लेने से नदवा के एक वर्ग में थोड़ी बेचैनी भी पैदा हुई. उन्हें यह डर लगने लगा कि कहीं उनके इस फ़ैसले से देश की सांप्रदायिक ताकतों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बार फिर ज़हर उगलने का मौक़ा न मिल जाए. कहीं किसी कोने से यह आवाज़ न उठने लगे कि देश के एक मदरसे का आलिम भी पाकिस्तान एवं अफ़ग़ानिस्तान की तर्ज़ पर देश के अंदर न केवल तालिबान की फ़ौज बनाने की तैयारी कर रहा है, बल्कि सत्ता भी हथियाना चाहता है. हालांकि इत्तेहाद फ्रंट ने अपने एक प्रेस नोट में साफ़ तौर पर लिखा कि छोटी-छोटी पार्टियों के नेता आज एकता मंच पर इसलिए जमा हुए हैं कि उन्हें तब्दीली लाना है. एक चोर की जगह दूसरे चोर और एक ज़ालिम की जगह दूसरे ज़ालिम की तब्दीली नहीं, बल्कि ज़ालिम की जगह मुंसिफ और हाकिम की जगह सेवक की तब्दीली लाना है.

लेकिन दूसरी तरफ़ मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के ख़िलाफ़ जैसी भाषा प्रयोग की है, उससे यह बात साफ़ हो जाती है कि अगर वह मुसलमानों का कोई राजनीतिक मोर्चा खड़ा करेंगे, तो सवाल यह भी उठता है कि उसकी सूरत और शक्ल क्या होगी? देश की इन बड़ी सियासी पार्टियों के बारे में मौलाना की राय कुछ इस तरह है: कांग्रेस, जो मुल्क की सबसे पुरानी एवं बड़ी पार्टी है और जिसे सबसे ज़्यादा हुकूमत करने का मौक़ा मिला, अपनी कोई बुनियाद वोटों की नहीं रखती. वह मुसलमानों एवं अल्पसंख्यकों के वोटों से जीतती है और ब्राह्मणों की झोली भरती है. मुसलमानों को और कमज़ोर करना उसका मिशन रहा है. समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, जिनके वोट केवल 6-7 प्रतिशत हैं. मुसलमानों के वोटों से वह सफलता प्राप्त करती है और फिर उन्हें कुछ टुकड़े फेंककर खुश करना चाहती है. बसपा के अपने वोट जाटव बिरादरी के 11 प्रतिशत हैं. वह हिंदुओं के अत्याचार के ख़िलाफ़ खड़ी हुई. 1984 के चुनाव में उसे कुछ नहीं मिला, 1989 में उसके 13 उम्मीदवार कामयाब हुए. फिर मुसलमानों को रिझाकर 1993 में उसे 63 और 1996 में 67 सीटें मिलीं, लेकिन उसने मुसलमानों से गद्दारी करके भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई और मायावती मुख्यमंत्री बन गईं. 2009 में बसपा के 98 उम्मीदवार कामयाब हुए और फिर भाजपा की मदद से मायावती ने सरकार बनाई. 11 प्रतिशत होते हुए और कुछ बेज़मीर मुसलमानों को खरीद कर और मुसलमानों के 25 प्रतिशत वोट लेकर यह पार्टी मुसलमानों की पीठ में छुरा घोपती रही. इन तीनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना लगाने के बाद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का राजनीतिक मोर्चा तलाशने वाली सोच आगे बढ़ाते हुए मौलाना सलमान हुसैनी नदवी अपना मकसद बयान करते हैं कि 1989 से 2007 तक मुसलमान 80 से 90 सीटों पर सीधे मुकाबले में रहे हैं और 40 से 56 सीटों पर कामयाब भी रहे. उक्त आंकड़े बताते हैं कि अगर मुसलमान एक पार्टी और एक झंडे के नीचे इकट्ठा होकर सत्ता पाने का प्रयास करें, तो 100 से 125 सीटों पर कामयाबी हासिल की जा सकती है. इस प्रकार मुसलमानों का राजनीतिक मोर्चा बनाने की तैयारी पूरे जोर-शोर से चल रही है. दूसरी ओर, मुसलमानों के इस राजनीतिक मोर्चे के मीडिया विंग की ज़िम्मेदारी अज़ीज़ बर्नी को दे दी गई है, जो आजकल अपने अख़बार अजीजुल हिंद द्वारा मुसलमानों का ब्रेनवाश करने में लगे हुए हैं.

पिछले कुछ सालों के दौरान भारतीय मुसलमानों की सोच पर अगर नज़र डालें, तो पता चलता है कि देश में बाटला हाउस कांड क्या हुआ, मुसलमान अपनी-अपनी सियासी दुकान चमकाने में लग गए. आतंकवाद और बेक़सूर मुसलमानों की गिरफ़्तारी पर बात करना इस कौम के लिए आज एक फैशन-सा बन गया है. दूसरी तरफ़ हेमंत करकरे ने शहीद होने से पहले आतंकवादी घटनाओं में हिंदुओं के शामिल होने की बात भी क्या कह दी, ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में पिछले 65 वर्षों से बेबसी एवं लाचारी का जीवन व्यतीत करने वाले मुसलमानों को संजीवनी मिल गई. ऐसा लगता है कि यह मुद्दा जैसे ही हल होगा, मुसलमानों की सारी तकलीफें एवं परेशानियां दूर हो जाएंगी. सच्चाई यह है कि मुसलमानों को न तो अपना हक मांगना आता है और न ही उन्हें सियासत आती है. गांधी जी ने पूरे भारत को एक सबक दिया था कि जैसे ही कोई तुम्हारे ख़िलाफ़ अत्याचार करे, तुम धरने पर बैठ जाओ, विरोध करो, हड़ताल करो और अगर उससे भी काम न चले, तो भूख हड़ताल पर बैठ जाओ. गांधी जी ने कभी बंदूक नहीं चलाई, लाठी-डंडे का प्रयोग नहीं किया और न कभी अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ कोई पत्थर उछाला, लेकिन मुसलमानों पर जब भी ज़ुल्म हुआ, उन्होंने गांधी जी का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि कई बार सरहद पार करके आतंकवाद की ट्रेनिंग ली और बंदूक के सहारे अपने मसले हल करने की कोशिश की. नतीजतन, सारे मुसलमानों पर आतंकवादी होने का धब्बा लग गया. और तो और, किसी ने रामलीला मैदान या जंतर-मंतर पर अपनी मांग मनवाने के लिए भूख हड़ताल नहीं की.

दूसरी तरफ़ जब अन्ना हज़ारे भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए रामलीला मैदान में अनशन कर रहे थे, तब भी कोई मुसलमान उनसे यह कहने नहीं गया कि हम भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और अब हम भी आपके साथ अनशन पर बैठना चाहते हैं. इसके बिल्कुल उलट मुस्लिम रहनुमा एक बार फिर इस मुल्क में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं. उनमें से कोई भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वे सब मोहम्मद अली जिन्ना बनना चाहते हैं. डर इस बात का है कि अगर मुसलमान इस मुल्क में अपनी अलग सियासी पार्टी बनाने की कोशिश करेगा, तो एक बार फिर वह पाकिस्तान बनने जैसी सूरतेहाल पैदा करेगा. एक बार फिर उस पर गद्दार होने का आरोप लगेगा और आम मुसलमानों की समस्याएं हल होने के बजाय आतंकवाद की तरह कोई दूसरा बड़ा आरोप लगेगा. ■

qamartabrez@gmail.com

झारखंड

> कांग्रेस ने 2006 में भाजपा की सरकार गिरवा कर कोड़ा एंड कंपनी को कुर्सी पर बैठाया था. लगभग वही नजारा है, लेकिन इस बार कोड़ा एंड कंपनी का सहारा लेकर कांग्रेस खुद कुर्सी पर बैठी है. तब कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी और आज निर्दलीय कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे हैं. इसी बिना पर कांग्रेस कोड़ा एंड कंपनी के भ्रष्टाचार से खुद को अलग मानती रही है और इसी बिना पर एक बार फिर उनका समर्थन लिया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश

झारखंड

कांग्रेस का हाथ, दागियों के साथ

मनोज श्रीवास्तव

झारखंड की सरकार के लिए निर्दलियों का समर्थन जुटाने का ज़िम्मा जेएमएम (झारखंड मुक्ति मोर्चा) पर डालकर कांग्रेस ने कौन सी गंगा नहा ली, यह समझना मुश्किल नहीं है. दरअसल, सच बर्दाश्त करने की क्षमता न हो, तो उसे ग्रंथि की तरह ढोना मजबूरी हो जाता है. झारखंड में भ्रष्टाचार का दलदल इस हद तक फैल चुका है कि कोई बिरला की बेदाग रहा. कांग्रेस ने भी बिना ज़िम्मेदारी लिए मलाई मारने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ा है. दो बार मधु कोड़ा एवं शिबू सोरेन की सरकारों को समर्थन देकर और दो बार राष्ट्रपति शासन के बहाने झारखंड की सत्ता का स्वाद चख चुके कांग्रेसी आला दरबार के घाघ मैनेजर एक बार फिर शुतुर्मुर्गी झांसा देने में लगे हुए हैं.

इस बार कांग्रेसी मैनेजरों की चाल को हलका सा झटका दिया भी है, तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं एवं विधायकों ने. पिछली सरकारों को बाहर से समर्थन देने के चलते कांग्रेस के विधायक काठ के उल्लुओं की तरह तमाशा देखते रहे, जबकि समन्वय एवं मार्गदर्शन के नाम पर केंद्रीय एजेंटों की बल्ले-बल्ले होती रही. प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इस बार हेमंत सोरेन को समझाया कि सरकार की अच्छी सेहत एवं लंबी आयु के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस को सरकार में शामिल किया जाए. हेमंत को यह तर्क रास आया और उन्होंने कांग्रेस के सामने यह शर्त रख दी. दूसरी तरफ़ आलाकमान के सामने पेशी के दौरान ज़्यादातर विधायकों ने सरकार में शामिल रहने की इच्छा जताई.

दरअसल, मौजूदा हालात में कांग्रेस झारखंड में चुनाव कराने से डरती है और लोकसभा चुनाव में जेएमएम से गठबंधन किए बिना झारखंड में उसकी दाल नहीं गलने वाली. लिहाजा जेएमएम की मांग के आगे झुकते हुए सरकार बनाने की मंजूरी दे दी गई. अंदर-बाहर का रुख देखते हुए सरकार में शामिल रहने का निर्णय भी हुआ, लेकिन आकंठ भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबे निर्दलियों को गले लगाने में हिचकिचाहट हो रही है. इसलिए यह काम हेमंत सोरेन पर छोड़ दिया गया. हकीकत यह है कि लाइफ फुल सर्किल की तर्ज पर एक बार फिर कांग्रेस कोड़ा एंड कंपनी के साथ आ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, पूर्व सहयोगी एनोस एक्का, हरि नारायण राय एवं बंधु तिर्की झारखंड की सरकार को समर्थन दे रहे हैं.

निर्दलियों ने जिस तरह अपनी शर्तों पर समर्थन देना स्वीकार किया, वह सरकार के भविष्य का सीधा संकेत है. मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने कोल्हान के विकास को सरकार के एजेंडे में शामिल कराया, तो एनोस एक्का ने पंद्रह सूत्रीय मांग पत्र के रूप में जैसे राज्य की तमाम समस्याओं का निदान मांग लिया. बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम (झारखंड विकास मोर्चा) इसे ढोंग मानती है. पार्टी के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने बड़े पैमाने पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया है.

कांग्रेस ने 2006 में भाजपा की सरकार गिरवा कर कोड़ा एंड कंपनी को कुर्सी पर बैठाया था. लगभग वही नजारा है, लेकिन इस बार कोड़ा एंड कंपनी का सहारा लेकर कांग्रेस खुद कुर्सी पर बैठी है. तब कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी और आज निर्दलीय कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे हैं. इसी बिना पर कांग्रेस कोड़ा एंड कंपनी के भ्रष्टाचार से खुद को अलग मानती रही है और इसी बिना पर एक बार फिर उनका समर्थन लिया जा रहा है. भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का दोमुंहापन 2012 के राज्यसभा चुनावों के वक्त भी उजागर हुआ था, जब निर्दलियों से वोट मांगने के लिए कांग्रेस के नेता होटवार जेल के चक्कर लगा रहे थे.

दरअसल, सच यह है कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों का खुलासा होने के बाद से कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों से एक निश्चित दूरी बनाए रखने का स्वांग रचती आई है. कांग्रेस ने कोड़ा एंड कंपनी के भ्रष्टाचार में अपनी भूमिका भी स्वीकार नहीं की, जबकि सितंबर 2006 में भाजपा की सरकार गिरवाने से लेकर अगस्त 2008 तक मधु कोड़ा के पूरे कार्यकाल में कांग्रेस ने न सिर्फ़ उनका समर्थन किया, बल्कि वह उन पर हावी भी रही.

तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अजय माकन जब झारखंड के दौरे पर आते, तो मीडिया में सरकार के ख़िलाफ़ कठोर बयान देते, लेकिन दिल्ली लौटने के वक्त तक मामला ठंडे बस्ते में चला जाता. कोड़ा कांड के खुलासे के बाद कांग्रेस ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि पार्टी निर्दलियों की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी. आज भी जब सार्वजनिक बहस में विपक्ष के लोग उस हीलिंग-डीलिंग की याद दिलाते हैं, तो कांग्रेसी आपा खोने लगते हैं. 2009 के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस-जेवीएम का चुनाव पूर्व गठबंधन 25 सीटें जीतकर सबसे आगे था. राजद, आजसू एवं निर्दलियों के सहयोग से सरकार बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस में अनिर्णय की स्थिति के चलते भाजपा ने बाजी मार ली. तब खिसियानी बिल्ली की तरह कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपी विधायकों से परहेज का तर्क देकर अपनी झेंप मिटाई थी.

इस सरकार के दाग-धब्बों की दास्तान निर्दलियों तक सीमित नहीं है. इसकी अगुवाई कर रही जेएमएम के दो विधायक सीता सोरेन एवं नलिन सोरेन फरार चल रहे हैं. सीता सोरेन पर अपने सचिव एवं कैश फॉर वोट मामले में गवाह संतोष पांडेय को अगवा करने का आरोप है, जबकि नलिन सोरेन बीज घोटाले में आरोपी हैं. खुद कांग्रेस का एक निलंबित विधायक सावना लकड़ा ऑनर किलिंग के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. 2010 और 2012 के राज्यसभा चुनावों में कैश फॉर वोट मामलों की जांच सीबीआई कर रही है. सरकार में शामिल दर्जन भर से ज़्यादा विधायक सीबीआई जांच की जद में हैं. इसमें पांच कांग्रेसी विधायक भी शामिल हैं.

राज्य में अब तक कांग्रेस के पास अपने बचाव के लिए सबसे बड़ा तर्क यह रहा है कि वह कभी सत्ता में नहीं रही. यह पहली सरकार है, जिसमें कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से शामिल है. सबको पता है कि यह सरकार लोकसभा चुनावों की बिसात सजाने के लिए बनाई गई है, इसलिए अगर आम चुनाव तक सरकार चल पाई, तो वह आगे की उम्र भी पूरी कर पाएगी. इस बीच जो जितना वसूल सके, वसूलने की कोशिश करेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

धृतराष्ट्र बन गए हैं लालची अफसर

ज़हर उगलते ईंट भट्ठे

अगर आपकी जेब में बतौर रिश्वत देने के लिए मोटी रकम हो, तो सारे नियम-क़ानून मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. शायद यही साबित कर रहे हैं लखनऊ-इलाहाबाद राजमार्ग पर स्थित दर्जनों ईंट भट्ठे, जो न केवल जनस्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, बल्कि पर्यावरण को भी खासा नुक़सान पहुंचा रहे हैं.

शिवाशंकर पांडेय

पर्यावरण प्रदूषण रोक पाने में सरकारी अमले की नाकामी और मनमानी का असर देखने वालों के लिए इलाहाबाद का गंगापार इलाका शायद सबसे मुफीद साबित हो सकता है, जहां सारे कायदे-क़ानून बौने नज़र आ रहे हैं. आम, महुआ, आंवला, कटहल आदि फलदार वृक्षों के घने बगीचों के बीचोबीच काला धुआं उगलती चिमनियों वाले ईंट भट्ठों की लंबी कतार न सिर्फ़ चौंकाती है, बल्कि यह सोचने के लिए मजबूर भी करती है कि रिश्वत की काली कमाई लालची अफसरों को किस कदर धृतराष्ट्र बना देती है. तकरीबन बीस किलोमीटर का इलाका पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर संकट का शिकार है. बीते पांच-सात सालों से अचानक गहराए इस संकट के शिकार टाउन एरिया लालगोपालगंज एवं आसपास स्थित क़रीब तीस से ज़्यादा गांवों के लोग बन चुके हैं. लेकिन अफसोस! शासन, प्रशासन एवं सामाजिक संगठन इस गंभीर समस्या के प्रति उदासीन बने हुए हैं.

इलाहाबाद जिला मुख्यालय से क़रीब 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर लखनऊ-इलाहाबाद राजमार्ग से गुजरिए, तो अगल-बगल स्थित बाग-बगीचों की हरियाली तबियत खुश करने लगती है, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती. वजह है, ईंट भट्ठों की एक लंबी कतार. इलाहाबाद से नवाबगंज के आगे लखनऊ की तरफ़ थोड़ा आगे बढ़ते ही जो दृश्य सामने आता है, वह किसी भी पर्यावरण प्रेमी का मन खट्टा कर देने के लिए काफी है. ईंट भट्ठों की चिमनियों से दिन-रात निकलने वाला काला ज़हरीला धुआं यहां के लोगों की ज़िंदगी को ग्रहण लगा रहा है. घने बाग-बगीचों के फलदार वृक्ष सूखने लगे हैं. आम के फल काले पड़ने लगे हैं. कृषि बाहुल्य इस क्षेत्र में उपज भी तेजी से घट रही है. उक्त ईंट भट्ठे लालगोपालगंज, भगौतीपुर, मंसूराबाद, श्रृंगवेरपुर इलाके में मौजूद हैं. सवाल यह है कि घनी अमराइयों के बीचोबीच धड़ल्ले से चल रहे इन दर्जनों ईंट भट्ठों के संचालन का लाइसेंस आख़िर किन अधिकारियों ने और कैसे दे दिया?

29 गांव, 58 भट्ठे

घनी आबादी वाले 29 गांवों से सटे और आसपास स्थित 58 से ज़्यादा ईंट भट्ठों का संचालन प्रशासन की भूमिका पर सवालिया निशान लगा रहा है. स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इन ईंट भट्ठों की जांच-पड़ताल के लिए कभी कोई अफसर यहां आया ही नहीं.

ख़तरनाक बीमारियों का प्रकोप

ईंट भट्ठों की चिमनियों से निकलने वाला काला ज़हरीला धुआं कई तरह की बीमारियां फैला रहा है. यही नहीं, धूल के महीन कण फेफड़ों में पहुंच कर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. चिकित्सा जगत से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, पेट दर्द के अलावा, न्यू माकोनिओसिस, सिलकोसिस, बिसनोसिस, एस्बेस्टॉसिस, एंलुएंजा आदि कई ख़तरनाक बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. बड़ी तादाद में लोगों के फेफड़े, किडनी एवं गुर्दे बेकार हो रहे हैं. इलाके में विकलांगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है.

आमरण अनशन भी नाकाम

सोरांव तहसील का इलाका कृषि बाहुल्य माना जाता है. 90 फ़ीसद से ज़्यादा लोगों के जीवनयापन का प्रमुख आधार खेती-बाड़ी और फलोत्पादन है. ईंट भट्ठों के अंधाधुंध संचालन से होने वाले नुक़सान को रोकने के लिए लाई निवासी एवं अधिवक्ता अबरार अहमद ने जिला प्रशासन एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर अबरार अहमद ने बीते वर्ष 17 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया. तीन दिनों के बाद प्रशासन की नींद टूटी और जांच का आश्वासन देकर अबरार का अनशन ख़त्म करा दिया गया. तत्कालीन उपजिलाधिकारी शत्रुघ्न वैश्य ने 23 मई, 2012 को अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि उक्त ईंट भट्ठों की वजह से जनस्वास्थ्य और पर्यावरण को काफी नुक़सान पहुंच रहा है. अबरार अहमद ने बताया कि लाई ग्राम पंचायत में उनका पांच एकड़ ज़मीन में दशहरी आम का बाग है. इस बाग के बगल में तीन-चार ईंट भट्ठे शुरू कर दिए गए. कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, लेकिन आश्वासन के अलावा, कुछ भी हाथ नहीं लगा.

> मानक के विपरीत यहां ईंट भट्ठों का संचालन बेहद ख़तरनाक है. खेत ऊसर बनते जा रहे हैं, कृषि उपज लगातार घट रही है और फलदार वृक्ष भी तेजी से नष्ट हो रहे हैं.
>
> *-डॉ. बृजेशकांत द्विवेदी, कृषि वैज्ञानिक, निदेशक बायोवेद रिसर्च संस्थान, इलाहाबाद.*

यह है ईंट भट्ठा जोन

मलाक बलऊ, कुढ़ा, ककरहिया, उल्दा, महेशगंज, भवानीपुर, रेरूआ, सम्हई, लाई, खंशा का पूरा, श्रृंगवेरपुर, भगौतीपुर, अंधियारी, मंसूराबाद, आनापुर, पाठक का पूरा, पठान का पूरा, भांट का पूरा, लीला का पूरा, उमेदन का पूरा, खुदा बख्श का पूरा, पियरी, मिरजहांपुर, कासिमपुर झरहा, मटियारा, कोराली, सरखेलपुर, रानीगंज, मोहद्दीपुर.

निर्धारित मानक

- रिहायशी क्षेत्र (आबादी) में उत्तर एवं दक्षिण दिशा में 300 मीटर, पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 1500 मीटर तक ईंट भट्ठे स्थापित नहीं हो सकते.
- नोटिफाइड म्यूनिसिपल क्षेत्र से ईंट भट्ठे की दूरी कम से कम पांच किलोमीटर अनिवार्य.
- अस्पताल, स्कूल, सार्वजनिक इमारत से एक किलोमीटर से कम दूरी पर ईंट भट्ठे स्थापित नहीं हो सकते.
- फलदार वृक्षों के बाग से डेढ़ किलोमीटर पूरब और आधा किलोमीटर पश्चिम तक ईंट भट्ठे स्थापित नहीं हो सकते.

उक्त सारे मानक पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने तय कर रखे हैं, जिनका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> पारंपरिक रूप से मुसलमानों का समर्थन पाने वाला राष्ट्रीय जनता दल इस मामले में कोई स्पष्ट बयान देने से बच रहा है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जदयू का भाजपा से अलग होना उसके लिए भी चिंता एवं चुनौती की बात है. राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद इस घटनाक्रम पर लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके किसी वक्तव्य में यह बात सामने नहीं आई है कि इससे राजद को नुक़सान होगा.

बिहार

इर्शादुल हक

मुसलमानों को खुश करने में व्यस्त हैं सभी पार्टियां

...लेकिन किधर जाएंगे मुसलमान

राजनीति और अंकगणित में एक बुनियादी फ़र्क़ है. अंकगणित में दो और दो का जोड़ हर हाल में चार ही होता है, जबकि राजनीति में यह योग पांच भी हो सकता है. भाजपा से अलग होने के जदयू के फ़ैसले का सार यही है, क्योंकि अब आम आदमी भी इसे दो और दो बराबर पांच से जुड़ी राजनीति ही समझ रहा है, पर जदयू नेतृत्व इसे सिद्धांत की लड़ाई बताकर अलग रंग देना चाहता है.

नीतीश कुमार

अली अनवर

नरेंद्र मोदी

लालू प्रसाद यादव

जदयू भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए से ख़ुद को अलग करके यह साबित करने में लगा है कि वह शहीद होने के लिए तैयार है, पर देश को थियोक्रेटिक स्टेट में बदलने की भाजपा की कोशिश कामयाब नहीं होने देगा. वहीं आमजन की समझ यह है कि जदयू का भाजपा से अलग होने का मकसद बिहार के 17 प्रतिशत, यानी लगभग एक करोड़ चालीस लाख मुसलमानों के दिलों में जगह बनाना है. यह क़दम उन्हें यह बताने का प्रयास है कि गुजरात नरसंहार के आरोपी को जदयू ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार न करके बहुत बड़ा काम किया है. मकसद तयशुदा है कि जदयू मुसलमानों के वोट ठीक उसी तरह एकमुश्त अपने नाम करना चाहता है, जिस तरह एक जमाने में लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा रोककर और उन्हें गिरफ्तार करके लालू यादव मुसलमानों के रातोरात हितैषी बन गए थे. ऐसे में गंभीर सवाल यह है कि क्या नीतीश का यह फ़ैसला उन्हें उतना ही लाभ दिला पाएगा, जितना लालू यादव ने उठाया था?

यह प्रश्न जितना गंभीर है, इसका जवाब भी उतना ही जोखिम भरा है, क्योंकि 1990 और 2013 के बीच 23 वर्षों के फासले ने देश में दो नई पीढ़ियां दी हैं, जो अब मतदाता की हैसियत से अंतिम फ़ैसला करने का हक रखती हैं. साथ ही इन 23 सालों में बदले राजनीतिक रुझान को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता. 1990 में देश में एक खास तरह का उन्माद था, यानी राम मंदिर आंदोलन का उन्माद. उससे पहले 1989 में बिहार के भागलपुर के भयानक दंगे मुसलमानों का दिल जबर्दस्त तरीके से जख्मी कर चुके थे. उक्त दंगे कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए थे. ऐसे में लालू प्रसाद यादव एक मात्र विकल्प के रूप में मुसलमानों के सामने थे. इन बातों के अलावा, उन दिनों मुसलमानों में पसमांदा राजनीति की कोई पहचान ही नहीं थी, यानी मुसलमान मात्र एक इकाई के रूप में राजनीतिक पहचान रखते थे, लेकिन अब, यानी 2013 में चीजें बदल गई हैं, क्योंकि पसमांदा राजनीति अब अपनी पहचान बना चुकी है. पसमांदा नेतृत्व अपनी सियासी हिस्सेदारी के बतौर एक मजबूत खेमे के रूप में सामने है. वहीं नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से उसी पार्टी के साथ सत्ता में भागीदारी करते आ रहे हैं, जिसे वह अचानक सांप्रदायिक और नरेंद्र मोदी को अस्वीकार्य बता रहे हैं. जहां तक अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों की बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद अब भी एक ताकत के रूप में बिहार में मौजूद हैं. उन्होंने अपनी ताकत पिछले दिनों महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव में दिखा भी दी है. गांधीवादी चिंतक रजी अहमद कहते हैं कि मुसलमानों की मौजूदा पीढ़ी अब उस तरह फ़ैसला नहीं लेगी, जैसा उसने 1990 में लिया था. मतलब साफ़ है कि एक तरफ़ पसमांदा मुसलमान अपनी राजनीतिक पहचान बनाकर अपने हित साधना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों के दायरे से बाहर निकलना चाहती है. हां, यह सच है कि सेक्युलरिज्म की दावेदार अनेक पार्टियां मुसलमानों को अपनी तरफ़ खींचने के प्रयास में हैं, तो ऐसे में जदयू के मोदी तीर की कामयाबी का फलसफा जोखिम भरा होना स्वाभाविक ही है.

ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के प्रमुख एवं जदयू के पूर्व सांसद डॉ. एम एजाज अली कहते हैं कि नीतीश कुमार ने 17 सालों तक सांप को दूध पिलाया है. अब चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि वह नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है. नीतीश ने जिस वर्ग (अगड़ी जाति का एक वर्ग) को आगे बढ़ाया है, वही उनका विरोधी हो चुका है और वही वर्ग भ्रष्टाचार में लिप्त है. फारबिसगंज में मुसलमानों पर गोलियां चलवाने में भाजपा नेता का हाथ था, यह बात सब लोग जानते हैं, लेकिन बदनाम नीतीश सरकार हुई. मतलब साफ़ है कि पाप भाजपा ने किया और बदनामी नीतीश कुमार की हुई. अब वह सामना करें इन चुनौतियों का. ग़ौरतलब है कि यह वही एजाज अली हैं, जिन्होंने जदयू सांसद की हैसियत से 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी के राजगीर चिंतन शिविर में नेतृत्व पर दबाव डाला था कि वह भाजपा से नाता तोड़ ले, लेकिन तब उनके बयान को नीतीश कुमार ने बगावत के रूप में लिया था. नतीजतन, एजाज अली को जदयू छोड़ना पड़ा, लेकिन आज उनकी बात सच साबित हुई और लगभग चार सालों के बाद जदयू ने भाजपा का दामन छोड़ दिया.

बावजूद इसके, एजाज अली भाजपा–जदयू गठबंधन टूटने को एक सकारात्मक क़दम मानते हैं. वह कहते हैं कि दरअसल, कांग्रेस और भाजपा देश पर टू पार्टी सिस्टम थोपना चाहती हैं. वे चाहती हैं कि क्षेत्रीय दलों का सफाया हो जाए. अगर उनकी साजिश सफल हो गई, तो यह दलितों, पिछड़ों (पसमांदा मुसलमानों) एवं अल्पसंख्यकों के हितों के ख़िलाफ़ होगा. इस लिहाज से नीतीश ने नरेंद्र मोदी के गुब्बारे में छेद कर दिया है. अब ममता, चंद्रबाबू नायडू एवं मुलायम सिंह जैसे नेताओं को इस विषय पर सोचना चाहिए. एजाज कहते हैं कि मुसलमानों को नीतीश का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां राज्यों का भला नहीं चाहतीं. हालांकि एजाज भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि राज्य के मुसलमान किस हद तक जदयू के साथ जाएंगे. साथ ही वह यह भी जोड़ना नहीं भूलते कि उनका जदयू नेतृत्व से कोई लेना–देना नहीं है और न ही उन्होंने या जदयू नेतृत्व ने एक–दूसरे से कोई बातचीत की है.

अब जबकि नरेंद्र मोदी के नाम पर जदयू भाजपा से अलग हो चुका है, तो यह निश्चित है कि नीतीश सरकार निकट भविष्य में ऐसे फ़ैसले ज़रूर लेगी, जो मुसलमानों को लुभाने वाले हों. उक्त फ़ैसले राजनीतिक भी हो सकते हैं और नीतिगत भी, क्योंकि अब तक नीतीश अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को यह जताते रहे हैं कि कई फ़ैसले गठबंधन के कारण नहीं लिए जा सके. जदयू कार्यकर्ता एवं ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज की बिहार इकाई के अध्यक्ष ताजुद्दीन मंसूरी कहते हैं कि अब जबकि भाजपा के 11 मंत्री अपना पद छोड़ चुके हैं और कई निगमों–बोर्डों के पद खाली हैं, ऐसे में नीतीश को पसमांदा मुसलमानों को आगे लाकर उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी देनी चाहिए. ताजुद्दीन मंसूरी की राजनीतिक पद देने वाली बात अपनी जगह है, लेकिन जब मुसलमानों द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश के समर्थन की बात आती है, तो वह काफी सतर्क होकर कहते हैं कि राजद अपनी असफलता के सर्वाधिक निचले स्तर पर है और उसके मात्र चार सांसद हैं. वह और ज़्यादा क्या असफल होगा, बल्कि उसकी सीटें बढ़ेंगी ही. ताजुद्दीन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि राजद की सीटें बढ़ेंगी, तो आख़िर किसकी क़ीमत पर? जाहिर है, वह जदयू भी हो सकता है और भाजपा भी.

पारंपरिक रूप से मुसलमानों का समर्थन पाने वाला राष्ट्रीय जनता दल इस मामले में कोई स्पष्ट बयान देने से बच रहा है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जदयू का भाजपा से अलग होना उसके लिए भी चिंता एवं चुनौती की बात है. राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद इस घटनाक्रम पर लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके किसी वक्तव्य में यह बात सामने नहीं आई है कि इससे राजद को नुक़सान होगा. वह इतना ज़रूर कहते हैं कि मोदी को अचानक सांप्रदायिक बताकर अलग होना नीतीश कुमार का नाटक है और वह ऐसा सिर्फ़ मुस्लिम वोटों के लिए कर रहे हैं. लालू प्रसाद कहते हैं कि गुजरात दंगों के बाद नीतीश केंद्र सरकार में मंत्री की कुर्सी पर चिपके रहे, लेकिन अचानक आज वह नरेंद्र मोदी को धर्मनिरपेक्षता के लिए ख़तरा बता रहे हैं और यह सरासर नाटक है. वैसे, लालू यह भी कहते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी में उन्हें फिर भी सेक्युलर चेहरा दिखता है, जबकि आडवाणी तो और ज़्यादा सांप्रदायिक हैं, क्योंकि उन्होंने ही बाबरी मस्जिद ध्वस्त कराने का काम किया था. भले ही लालू इस बात पर खुलकर न बोलें कि नीतीश को मुसलमानों का समर्थन मिलेगा या नहीं, लेकिन यह तो तय है कि नीतीश के इस क़दम से अगर कोई दल सबसे ज़्यादा चिंतित है, तो वह राष्ट्रीय जनता दल ही है. मोदी मामले पर जदयू का भाजपा से अलग होने का परिणाम इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को उठाती है. अगर वह हिंदुत्व के मुद्दे की तरफ़ बढ़ेगी, तो स्वाभाविक तौर पर वोटों का ध्रुवीकरण भी उसी आधार पर ही होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सेक्युलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म की तैयारी

जदयू सांसद अली अनवर के नेतृत्व में बीते एक जुलाई को पसमांदा जागो-देश बचाओ सम्मेलन का आयोजन करके यह साबित करने की कोशिश की गई कि देश के लिए बाकी सारे मुद्दे बेमानी हैं. अली अनवर जदयू सांसद के साथ-साथ पसमांदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने अब्दुल कयूम अंसारी एवं शहीद अब्दुल हमीद की जयंती पर जो मुद्दे उठाए, उनसे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले चुनावों में भ्रष्टाचार एवं महंगाई जैसे मुद्दे पीछे छूटेंगे और धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे ही हावी रहेंगे. सम्मेलन में अली अनवर ने कहा कि अब्दुल कयूम अंसारी ने देश के बंटवारे का विरोध किया था, क्योंकि वह जानते थे कि धर्म आधारित देश का विभाजन ख़तरनाक है. जब धर्म के नाम पर मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की, तो वह देश तीन दशकों में ही टूट गया और बांग्लादेश के रूप में उसके दो टुकड़े हो गए. उन्होंने कहा कि फिर इस देश को धर्म आधारित राज्य बनाने की साजिश शुरू हो गई है. यह देश को तोड़ने और छिन्न-भिन्न करने की साजिश है. ऐसे में हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे. अली अनवर का आशय यह था कि धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना समय की मांग है. इस सम्मेलन में नीतीश कुमार को भी आना था, लेकिन जिस दिन यह कार्यक्रम था, उस दिन, यानी सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार आयोजित होता है, जिसमें हज़ारों फरियादी एकत्र होते हैं. इसलिए नीतीश इसमें शरीक तो नहीं हो पाए, पर पसमांदा महाज के इस आयोजन के पीछे नीतीश की सियासी स्वीकृति ही काम कर रही थी. मतलब साफ़ है कि नीतीश भले ही इसमें शामिल नहीं हो सके, लेकिन वह ज़रूर चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे गरमाए जाएं, ताकि मुसलमानों को लालू यादव से अलग किया जा सके. ख़बर तो यह भी आ रही है कि जदयू से जुड़े दूसरे मुस्लिम संगठन भी आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिनका मकसद साफ़ तौर पर मुसलमानों में यह संदेश देना होगा कि नरेंद्र मोदी जैसे विवादित छवि वाले नेताओं को समाज विभाजन करने वाली शक्ति घोषित किया जाए. जैसे-जैसे मोदी के विरोध की आवाज़ मुस्लिम समुदाय में मजबूत होगी, वैसे-वैसे जदयू उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा. इससे एक तरफ़ उसे मुसलमानों में जनाधार बढ़ाने में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ़ उसकी वह रणनीति भी कामयाब होगी कि राजद समर्थक मुसलमानों को अपनी तरफ़ आकर्षित करके उसे कमजोर कर दिया जाए. ■

ओमप्रकाश सिंह अकेले नहीं हैं, बल्कि राज्य में सपा सरकार बनने के साथ ही ऐसा माहौल शुरू हो गया था. कहीं बेवजह अंधाधुंध फायरिंग, मारपीट, अवैध वसूली और दीगर सियासी पार्टियों के नेताओं के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणियों की घटनाओं ने बीते दो सालों के अंदर कई बार लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वाकई, सत्ता का नशा किसी को किस क़दर बेलगाम कर देता है.

राजस्थान

कांग्रेस से ख़फ़ा हैं मेवाती

समस्याएं ही समस्याएं हैं

मेउ मुसलमानों की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है. ऐसे में उनका कांग्रेस से मोह भंग होता जा रहा है.

ए यू आसिफ़

लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस विरोधी लहर दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और अब पूरे राज्य में फैल चुकी है. जयपुर स्थित माइनॉरिटी एजुकेशनल ऐंड वेलफेयर सोसायटी के तत्वावधान में जयपुर एवं बीकानेर के बाद बीते 7 जुलाई को मेवात में आयोजित मेवात की समस्याएं विषयक सेमिनार से ऐसा ही प्रतीत होता है. सेमिनार में आए लगभग सभी वक्ताओं को यही शिकायत रही कि मुसलमानों ने तो कांग्रेस पर हमेशा भरोसा किया, लेकिन उनकी समस्याएं फिर भी जस की तस ही रहीं और नतीजतन, आज भी वे शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से देश के अन्य वर्गों से बहुत पिछड़े हैं. सेमिनार में राज्य सरकार से मांग की गई कि वह मुसलमानों की स्थिति सुधारने के प्रति अपेक्षित गंभीरता बरते और उन्हें लाचार न समझे, अन्यथा अगले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में उसे कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. सोसायटी के चेयरमैन एडवोकेट असग़र अली ने जयपुर के गोलपाड़ा स्थित ग्रीन पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मेवाती आबादी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. यहां अगर तकनीकी, प्रोफेशनल एवं मैनेजमेंट की शिक्षा सरकारी स्तर पर शुरू की जाए, तो न केवल आम आदमी को रोज़गार के अवसर मिलेंगे, बल्कि साथ ही समाज में फैल रही कुरीतियों पर भी रोक लग सकेगी. उन्होंने मेवात क्षेत्र में वक्फ़ संपत्तियों की बंदरबांट पर अफसोस जताते हुए कहा कि आज लोग शवों को अपने ही खेत में दफ़नाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि मेवात में क़ब्रिस्तान बहुत छोटे हैं और पूरी तरह क़ब्रों से भर चुके हैं. उनका कहना था कि मुस्लिम आबादी घनी है, नए क़ब्रिस्तान बन नहीं पा रहे हैं और कई क़ब्रिस्तानों पर लोगों ने क़ब्ज़े भी कर रखे हैं.

सेमिनार के प्रबंधक मुर्शिद अहमद ने सरकार से मांग की कि वह व्यापार को बढ़ावा दे, ताकि लोगों को रोज़गार के अवसर मिलें और साथ ही बंजर पड़ी ज़मीनों का उचित इस्तेमाल किया जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार भू-माफियाओं पर रोक लगाए और मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उनका भविष्य संवारें. मेवात एक ऐसा क्षेत्र है, जिसने देश को पहला शिक्षामंत्री दिया, लेकिन इसके बावजूद यहां आज तक कोई विकास नहीं हुआ. उन्होंने सरकार को कोसा, मेवात की स्थिति काफी दयनीय है, जिससे यहां के मुसलमान चिंतित हैं. यहां का पानी खारा होने की वजह से लोगों को पीने का पानी ख़रीदना पड़ता है और यह सब सरकार द्वारा लागू ग़लत नीतियों के कारण ही हो रहा है. अगर सत्तारूढ़ कांग्रेस इस मामले पर ध्यान नहीं देगी, तो आने वाले समय में उसे इसका ख़ामियाज़ा भी भुगतना पड़ सकता है. नगर निगम के पूर्व ज़िला परिषद सदस्य इदरीस भाई, नब्बू ख़ां, सामाजिक कार्यकर्ता हनीफ़ ख़ां, मुफ्ती इस्लामुद्दीन, इक़बाल भाई मास्टर, मुफ्ती अब्दुल शकूर, एडवोकेट मोहम्मद सलीम, उमैद ख़ां (डीडवाना) और क़ारी इलियास ने मुसलमानों की समस्याओं के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराया. सेमिनार में जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक एवं नागपुर के प्रतिनिधियों ने शिरकत की.

सेमिनार में यह आवाज़ बुलंद की गई कि मेवात जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की जनता जाग उठी है और अगर उसकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वह किसी तीसरे विकल्प के बारे में सोच सकती है, या हो सकता कि विवश होकर वह भाजपा की ओर अपना रुख़ कर ले. लिहाज़ा यह स्थिति कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है. मेवातियों के लोकप्रिय नेता मोहम्मद क़ासिम मेवाती चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि वह और उनका परिवार पारंपरिक रूप से कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन गोपालगढ़ कांड ने उन्हें हिलाकर रख दिया है और तब वह कांग्रेस को अलविदा कहते हुए किरोड़ी लाल मीणा की नेशनल पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गए. क़ासिम मेवाती का कहना है कि कांग्रेस अगर यह समझती है कि राजस्थान में दो पार्टियों के हावी रहने की स्थिति में उसका भविष्य सुरक्षित है, तो यह उसका भ्रम ही है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के सक्रिय हो जाने से राज्य में परिस्थितियां बदल रही हैं. उनके साथ सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, बल्कि आदिवासी, जाट एवं मीणा भी जुड़ रहे हैं. वह कहते हैं कि गुर्जरों के नेता किरोड़ी लाल बैंसला, जिन्होंने 2008 में वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को हिला दिया था, से भी बातचीत चल रही है. अगर वह उभरती हुई तीसरी राजनीतिक शक्ति के साथ आ जाते हैं, तो न केवल कांग्रेस और भाजपा विरोधी विकल्प तैयार होगा, बल्कि आंदोलन में नई जान आ जाएगी. क़ासिम मेवाती का कहना है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है, वरना गोपालगढ़ समस्या अब तक हल हो चुकी होती, क्योंकि वहां क़ब्रिस्तान की हदबंदी कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था. वह कहते हैं कि मुसलमानों ने कांग्रेस का हमेशा साथ दिया, लेकिन उन्हें हमेशा निराशा ही हाथ आई.

राजस्थान वक्फ़ बोर्ड के प्रभारी जुबैर अलवरी का कहना है कि कांग्रेस हो या भाजपा, किसी के राज में सरकारी योजनाएं उचित ढंग से लागू नहीं हो पाती हैं. कांग्रेस के शासन में जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ. जब बच्चे को दूध नहीं मिलता है, तो वह रोता है और आख़िर में अपने माता-पिता से नाराज हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर जनता को कुछ नहीं मिलेगा, तो यह स्वाभाविक है कि उसका कांग्रेस से मोहभंग हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो भेदभाव अपनाते हैं और बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे कल्याणकारी कार्य नहीं हो पाते. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जयपुर में ईटीवी उर्दू द्वारा आयोजित सेमिनार में चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने जिस बेबाकी से मुसलमानों की असल समस्याओं को सबके सामने रखा, वह प्रेरणादायक है. अलवरी हैरान होते हुए कहते हैं कि इसके बाद भी राजनीतिक दल संवेदनहीन बने हुए हैं. अब समय आ गया है कि जनता इन राजनीतिक पार्टियों के भ्रमजाल से आज़ाद होकर संवैधानिक रूप से अपना प्रतिनिधि स्वयं चुने.

अलवर ज़िले में वक्फ़ कमेटी के चेयरमैन क़ारी मोहम्मद आसिफ़ साहून ने कहा कि सरकार तो सही है, लेकिन उसके नुमाइंदे सही नहीं हैं, इसीलिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं. वह कहते हैं कि कॉरपोरेशन की ओर से अल्पसंख्यकों को क़र्ज़ देने की घोषणा की गई थी, लेकिन वह पात्र लोगों के पास पहुंचा ही नहीं. दो करोड़ रुपये की राशि कर्ज़ के रूप में आवंटित हुई, जबकि स्टांप ड्यूटी से सरकार को लगभग ढाई करोड़ रुपये मिल गए. वह कहते हैं कि यह जनता के साथ एक भद्दा मज़ाक है, सरकार ने धोखा किया. इसीलिए जनता का कांग्रेस के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है और मुसलमान भी कांग्रेस से दूर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि वक्फ़ संपत्तियां एवं धार्मिक स्थल ख़तरे में हैं. अगर सरकार ने इस ओर ध्यान न दिया, तो गोपालगढ़ से भी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. मेवात की समस्याओं को लेकर हुए इस सेमिनार और महत्वपूर्ण मेउ प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाओं से यह बात खुलकर सामने आती है कि एक ऐसी आबादी आज तक पिछड़ी हुई है, जिसने आज़ादी मिलने के बाद भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच हुए समझौते आबादी स्थानांतरण के तहत पाकिस्तान जाने से इंकार कर दिया था और फिर उसने 19 दिसंबर, 1947 को गांधी जी की मेवात यात्रा के दौरान उनका समर्थन भी हासिल किया था. गांधी जी ने उस समय भावुक होकर यहां तक कह दिया था, मैं स्वयं ऐसे मुसलमानों के साथ मरना पसंद करूंगा. ग़ौरतलब है कि मेउ मुसलमानों ने अपने देश प्रेम के चलते पाकिस्तान जाने से इंकार कर दिया था. आज़ादी मिलने से पहले गांधी जी ने 14 सितंबर, 1946 को बिहार के चंपारण में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, अगर मेउ मुसलमानों जैसा हौसला भारत के अन्य लोगों में भी हो जाए, तो मैं 24 घंटे में देश को आज़ाद करा लूंगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

अज़गर अली

मुर्शिद अहमद

करीम मो. आरिफ़ साहुन

क़ासिम मेवाती

जुबैर अहमद अलवरी

उत्तर प्रदेश

बेलगाम और बदज़ुबान

जनप्रतिनिधि

पिछले दो सालों के दौरान अखिलेश सरकार को जितनी चुनौतियां बाहर से नहीं मिलीं, उससे कहीं ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं, मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों ने पेश कर दीं. अपने शर्मनाक बयानों और कारनामों से वे राज्य सरकार की साख धूल में मिलाने पर आमादा हैं.

महेंद्र अवधेश

बीते 27 जून को कानपुर के श्याम नगर इलाके में प्रदेश की महिला एवं समाज कल्याण राज्यमंत्री अरुणा कोरी के पति एवं सुरक्षाकर्मियों ने क्षेत्रीय पार्षद निर्देश सिंह एवं उनके भाई चंदन सिंह को पीट डाला, कपड़े फाड़ दिए. वजह सिर्फ़ इतनी थी कि मंत्री की फ्लीट निकल रही थी और पार्षद की कार रास्ते में खड़ी थी. मंत्री पति ने सरेआम अराजकता फैलाते हुए एस्कार्ट की मदद से दोनों को जमकर पीटा. पार्षद ने थाने में तहरीर भी दी, चूंकि मामला मंत्री का था, इसलिए थानेदार ने जांच कराने की बात कहकर उन्हें टरका दिया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की. इसी तरह बीते 13 जून को पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती पर अभद्र टिप्पणी करके समाजवादी पार्टी को शर्मसार कर दिया. गाजीपुर के जमनिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ओमप्रकाश सिंह ने न सिर्फ़ मायावती के रंग-रूप का मजाक उड़ाया, बल्कि उनके शासनकाल की तुलना उन्होंने तैमूरलंग, चंगेज खां एवं अहमद शाह अब्दाली के साथ भी कर डाली. ओमप्रकाश सिंह अकेले नहीं हैं, बल्कि राज्य में सपा सरकार बनने के साथ ही ऐसा माहौल शुरू हो गया था. कहीं बेवजह अंधाधुंध फायरिंग, मारपीट, अवैध वसूली और दीगर सियासी पार्टियों के नेताओं के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणियों की घटनाओं ने बीते दो सालों के अंदर कई बार लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वाकई, सत्ता का नशा किसी को किस क़दर बेलगाम कर देता है.

ग़ौरतलब है कि बीते वर्ष 5 जून को मुरादाबाद में बीडीसी की बैठक के दौरान ब्लॉक प्रमुख राजेश यादव से कहासुनी हो जाने पर समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफ़ान के भाई हाजी उस्मान एवं उनके समर्थकों ने गोलीबारी कर दी थी, जिसमें कई लोग जख्मी हुए थे. उससे पहले 12 मई को फरीदाबाद के एक सपा विधायक यातायात पुलिस द्वारा कारों के शीशे से काली फिल्म हटाने एवं नंबर प्लेट दुरुस्त कराने के लिए चलाए गए अभियान से भड़क गए थे और उन्होंने समर्थकों समेत हंगामा खड़ा कर दिया था. उससे पहले 4 मई को कानपुर में सपा विधायक मुनींद्र शुक्ला के रिश्तेदारों ने निजी बस चालकों-कंडक्टरों को केवल इसलिए पीट दिया था, क्योंकि वे उनकी अवैध वसूली का खुलेआम विरोध कर रहे थे. इसी तरह बदायूं ज़िले में महेश कुमार नामक शख्स की शिकायत पर सपा विधायक आबिद रज़ा के विरुद्ध मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुक़दमा दर्ज कराया गया. महेश को आबिद रज़ा ने अपने कार्यालय बुलाया और उसकी ज़मीन अपने नाम करने के लिए कहा. इंकार करने पर विधायक ने उसे अपने समर्थकों से न केवल पिटवाया, बल्कि जबरन सादे काग़ज़ों पर हस्ताक्षर भी करा लिए और मुंह खोलने पर जान से मार देने की धमकी भी दी. इससे पहले देवरिया के विधायक शाकिर अली ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर घोड़े की सवारी की और साथ ही उसे उचित भी ठहराया. उनके इस कृत्य के चलते रेल प्रशासन एवं आम यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली को जब राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो स्वागत जुलूस के दौरान जोश में होश खोकर वह समर्थकों के साथ खुद भी फायरिंग करने लगे. अखिलेश यादव की नवगठित सरकार के इस मंत्री को असलहा लहराते और गोलियां चलाते जिसने भी देखा, उसने अपना माथा पीट लिया. सीतापुर के सेउता विधानसभा क्षेत्र से विजयश्री हासिल करने वाले महेंद्र कुमार सिंह उर्फ झीनू बाबू ने तो सारी हदें ही पार कर डालीं. उन्होंने उन लोगों के घरों में आग लगवा दी, जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिए थे. झांसी में सपा कार्यकर्ताओं ने मीडियाकर्मियों को बंधक बनाया. संभल में सपाइयों की जीत के जश्न ने एक 7 वर्षीय बच्ची की जान ले ली. उन्नाव में सपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई मनोज सेंगर ने एक पत्रकार को केवल इसलिए पिटवा डाला था, क्योंकि वह उनके ख़िलाफ़ ख़बरें लिखता था. उन्नाव के एक अन्य सपा विधायक उदयराज ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में असलहों का प्रदर्शन करते हुए जमकर उत्पात मचाया और चेतावनी भी दी कि अब उनकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. मंशा साफ़ है, उक्त विधायक को ठेकेदारों से अपने हिस्से की दरकार थी.

महबूब अली

ओम प्रकाश सिंह

अपने दल की सरकार बनते ही सांसद, विधायक, पार्षद एवं प्रधान, यहां तक कि वार्ड स्तर के संगठन पदाधिकारी भी खुलेआम मनमानी पर उतर आते हैं. पुलिस-प्रशासन की मजबूरी बन जाती है कि वह आंख मूंदे रहे, क्योंकि नौकरी बचानी है और खुद भी खाना-कमाना है. सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना पहला संदेश देते हुए भरोसा दिलाया था कि अराजकता किसी भी क़ीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वाला चाहे जो भी हो, उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी. समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी. बावजूद इसके, सपा कार्यकर्ताओं, विधायकों एवं मंत्रियों के नित नए कारनामे सामने आ रहे हैं. दरअसल, इस तरह की घटनाएं किसी भी सरकार के सारे किए-धरे पर पानी फेर देती हैं.

सरकार की नीतियां लाख स्पष्ट रहें, नीयत साफ़ रहे, वह आम जन की भलाई के लिए कुछ करने की ठाने और उस दिशा में क़दम भी बढ़ा ले, लेकिन अगर इस बीच पार्टी कार्यकर्ता, विधायक अथवा मंत्री ही मनमानी पर उतर आएं, तो किसी भी सरकार के सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं. नुक़सान ऐसा करने वालों का नहीं, बल्कि सरकार और उसके मुखिया का होता है, क्योंकि छवि और उसके मुखिया की बिगड़ती है. अखिलेश यादव सरकार के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं. प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ समाजवादी पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताया था, लेकिन वह भरोसा इस पार्टी ने चूर-चूर कर दिया. अब लोकसभा चुनाव भी सिर पर हैं. मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश के प्रति आम जनता का विश्वास किस स्तर तक मज़बूत हुआ है, यह लोकसभा के चुनाव परिणामों से तय होगा. ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से ले और दोषी लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे. पार्टी कार्यकर्ता, विधायक एवं मंत्री जनता के बीच सरकार के चेहरे और उसके प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनका एक भी ग़लत क़दम समूची सरकार के लिए शर्मिंदगी की वजह बन सकता है. इसलिए उन्हें यह हिदायत दी जानी बहुत ज़रूरी है कि वे अपना आचरण सुधारें और संयम बरतें, अन्यथा जनता एक दिन उन्हें उसी तरह अर्श से फर्श पर ला पटकेगी, जिस तरह उसने विधानसभा चुनाव में कइयों को धराशायी कर दिया था. अफ़सोस की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होते हुए देखने के बाद भी पार्टी नेताओं और सरकार के दावे लगातार जारी हैं कि राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि तस्वीर इसके ठीक उलट है. आप कह सकते हैं कि शर्म उन्हें फिर भी नहीं आती....■

mahendra.awdhesh@gmail.com

मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही बड़ी संख्या में लोगों ने अन्ना हज़ारे का जोरदार स्वागत किया. रीवा के बाद अन्ना हज़ारे 6 जुलाई को रामपुर, चुरहट एवं सीधी पहुंचे. जनतंत्र यात्रा के दूसरे दिन भी अन्ना हज़ारे ने अपना आक्रामक रुख बरकरार रखते हुए कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक जैसी हैं. देश में अब केवल सत्ता बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे : अन्ना

अन्ना हज़ारे की जनतंत्र यात्रा का चौथा चरण बीते 5 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा से शुरू हुआ, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें धोखा दिया है. अन्ना ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि यदि मानसून सत्र में जन लोकपाल बिल संसद में पास नहीं किया गया, तो वह अक्टूबर में एक बार फिर से रामलीला मैदान में आमरण अनशन पर बैठेंगे.

मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही बड़ी संख्या में लोगों ने अन्ना हज़ारे का जोरदार स्वागत किया. रीवा के बाद अन्ना हज़ारे 6 जुलाई को रामपुर, चुरहट एवं सीधी पहुंचे. जनतंत्र यात्रा के दूसरे दिन भी अन्ना हज़ारे ने अपना आक्रामक रुख बरकरार रखते हुए कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक जैसी हैं. देश में अब केवल सत्ता बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है. 7 जुलाई को अन्ना बियोहारी और कटनी गए. कटनी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है. सरकार लोकपाल के अपने वादे से मुकर गई है और इसीलिए उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

8 जुलाई को वह जबलपुर और सिवनी पहुंचे. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जनतंत्र यात्रा पर निकले अन्ना हज़ारे ने 9 जुलाई को चिंदवाड़ा, मुलताई और बैतूल में लोगों को संबोधित किया. चिंदवाड़ा में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देशवासियों को लोक लुभावन वादों के जरिए गुमराह कर रही है और वह जन लोकपाल पर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता है कि मजबूत जन लोकपाल आने से देश के अधिकांश नेता सलाखों के पीछे होंगे. मुल्ताई में अन्ना हज़ारे को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए. अन्ना ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह किसानों को संगठित करके एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे. उनका मानना है कि पहले लोकपाल ज़रूरी है और उसके बाद किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया जाएगा. अन्ना ने कहा कि किसानों एवं ग्रामसभा की सहमति के बिना किसानों की एक इंच ज़मीन भी अधिग्रहीत नहीं की जानी चाहिए. चिंदवाड़ा और मुल्ताई के बाद अन्ना ने बैतूल में जनता को संबोधित किया. हमेशा की तरह यहां भी बड़ी संख्या में लोग अन्ना को देखने और सुनने के लिए पहुंचे. अन्ना ने कहा कि वह संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर ही लोगों के बीच जा रहे हैं. उनका पहला लक्ष्य लोकपाल बिल संसद से पारित कराना है.

10 जुलाई को अन्ना हज़ारे ने इटारसी और होशंगाबाद में लोगों को संबोधित किया. उन्होंने केंद्र सरकार को उसके पक्षपात पूर्ण और ढुलमुल रवैए के लिए खरी–खोटी सुनाई. 11 जुलाई को अन्ना भोपाल पहुंचे. भोपाल में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई को लेकर गंभीर नहीं है. सरकार ने मजबूत लोकपाल को लेकर देश को धोखा दिया है. 12 जुलाई को अन्ना रायसेन और सागर पहुंचे. यहां भी उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

देश से बढ़कर कुछ भी नहीं

भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राजनीतिक दलों का आपसी विरोध सिर्फ़ चुनाव मैदान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अक्सर राष्ट्र के विकास में भी बाधाएं उत्पन्न करता नज़र आ जाता है. कैसे? पढ़िए यह बेबाक विश्लेषण.

चुनाव को लेकर चारों ओर चर्चा गर्म है. हालांकि चुनाव मई 2014 में होना तय है, लेकिन दो कारण ऐसे हैं, जो यह बता रहे हैं कि चुनाव नवंबर में होंगे. पहला, खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश लाकर उसे पारित कराना, जिसके लिए संसद का सत्र बुलाना पड़ा. हालांकि इसकी अभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी. दूसरा, संसद का मानसून सत्र आम तौर पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है, जो कि अभी तक नहीं हो सका है. कांग्रेसी खेमे में यह चर्चा है कि मानसून सत्र देर से सही, लेकिन अगस्त में ज़रूर बुलाया जाए. एक छोटे सत्र के बाद उसे स्थगित करके नवंबर में चुनाव कराने के लिए संसद भंग कर दी जाए. वैसे, इस बात में दम है, क्योंकि समय से कुछ महीने पूर्व चुनाव कराना सत्ताधारी कांग्रेस का विशेषाधिकार भी है. हालांकि बड़ा सवाल यह उठता भी है कि इस चुनाव से क्या होने वाला है?

केंद्र में कांग्रेस सत्तासीन है. उसे विभिन्न पार्टियों के साथ मिलकर साझा सरकार चलाने का नौ वर्षों का अनुभव भी है. भाजपा का नंबर इसके बाद आता है. भाजपा विपक्ष में है और इसके पास कुछ सहयोगी दल भी हैं. इसके बाद क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो विभिन्न राज्यों से हैं और अपने दम पर कार्य कर रही हैं. भारतीय राजनीति को जिस वास्तविक समस्या का इन दिनों सामना करना पड़ रहा है, वह यूएस एवं यूके से दरअसल, भिन्न है, क्योंकि उन देशों में सभी पार्टियां राजनीति में एक ही लक्ष्य लेकर चलती हैं. लेकिन यहां की वास्तविक समस्या यह है कि भाजपा एक पार्टी है और आरएसएस उसका माई-बाप है और दोनों ही संविधान में वर्णित भारत के लक्ष्यों को जनता से साझा नहीं करते. ये इस बात में विश्वास नहीं करते कि हमारे संविधान में जो अंश दूसरे देशों से लिए गए हैं, वे सही हैं. कुछ कारणों से ये इस बात को कहने में डरते भी हैं कि इस संविधान के अंतर्गत ये चुनाव लड़ना चाहते हैं. तो क्या ये हिंदू भारत चाहते हैं? ये इस बात में विश्वास करते हैं कि पाकिस्तान की नींव धार्मिकता पर रखी गई है, इसलिए शेष भारत हिंदुस्तान है और यह धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है. इसके लिए इन्होंने एक ऐसे आदमी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का चेयरमैन बनाया, जो हिंदुत्व का बहुत ही चर्चित चेहरा है. लेकिन वास्तव में, वह शख्स हज़ारों मुसलमानों की हत्या कराने का दोषी रहा है.

सबसे हास्यास्पद बात यह है कि भाजपा अभी तक यह सोचती रही है कि इस तरह के कट्टर राष्ट्रवाद की स्थिति पैदा करके वह पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है. वह यह भी दलील देती है कि ढेर सारे युवा उसे वोट देते हैं और उसे ही देंगे. मैं नहीं जानता कि वह यह गणित किस आधार पर लगाती है? वह शहरी युवाओं के बारे में बात करती है, जो इंटरनेट एवं ट्विटर का प्रयोग करते हैं या उन युवाओं की, जो गांवों में रहते हैं और बेरोज़गार हैं? भाजपा के पास उन्हें रोज़गार देने के लिए कोई ब्लू प्रिंट भी नहीं है. सिर्फ़ हिंदू एवं मुसलमानों में कट्टर राष्ट्रवाद फैलाने से वोट मिल सकता है, यह एक बिंदु हो सकता है. राम मंदिर निर्माण जैसे भावनात्मक मुद्दे फिर से आपकी मदद कर सकते हैं, यह भी एक बिंदु हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरे देश को अपना भरपूर समर्थन देना चाहते हैं, तो आपको अपना नज़रिया बदलना ही होगा.

अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां चुनाव में एक-दूसरे के विरोध में जी-जान से लड़ती हैं, लेकिन देश को लेकर सभी के अंदर एक जैसी भावनाएं होती हैं. उनके अंदर इस तरह की सनक नहीं होती. यूके में कंजरवेटिव, लेबर और अब लिबरल पार्टियां भी चुनाव में एक-दूसरे का जबरदस्त प्रतिरोध करती हैं, लेकिन देश के लिए उनका नज़रिया समान होता है. सच तो यह है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है, वह देश को विकास के रास्ते पर ले चलने का प्रयास करती है. भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छह वर्षों तक सत्ता में रही. उसने देश को पूर्ववर्ती सरकारों की तरह ही नेतृत्व दिया और कुछ भी बदलाव नहीं किया, लेकिन आज यह स्थिति नहीं है. आज वह संप्रदायवाद की ओर बढ़ रही है. यह देश के लिए ख़तरनाक है. यह देश को निराशा की तरफ़ धकेलने की तरह है. यह क़दम एक ऐसी अस्थिरता की तरफ़ ले जाने वाला होगा, जो देश के लिए घातक है.

लोग क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ़ देखते हैं, ताकि चुनाव के बाद वे एक साथ आकर भाजपा को दूर रख सकें, लेकिन इतना करना ही पर्याप्त नहीं है. क्षेत्रीय पार्टियों के नेता एक-दूसरे से मिलना, साथ बैठना तक पसंद नहीं करते. यहां तक कि वे इसके लिए भी बैठकें नहीं करते कि चुनाव के बाद उनका एक ही उद्देश्य है. भाजपा यह उम्मीद पाले बैठे रहती है कि उनमें से कुछ उसके साथ आ जाएंगे. यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सत्ता में कौन आता है. लोकतंत्र में हर पांच साल पर सरकार को तो बदलना ही है, इसलिए इसकी समस्या नहीं है. मूल प्रश्न यह है कि लोगों के पास आज दो ही विकल्प हैं, भ्रष्ट कांग्रेस और सांप्रदायिक भाजपा. इन दोनों ने ही देश को भयभीत कर दिया है. कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जिसकी कल्पना खुद कांग्रेस भी नहीं कर सकती. भाजपा अपनी चुनाव प्रचार अभियान समिति के नए चेयरमैन के नेतृत्व में सांप्रदायिकता को सनक के नए स्तर तक ले जा चुकी है, जो किसी भी तरह से सभ्य आचरण के ख़िलाफ़ है और जो यह सवाल भी खड़ा करता है कि आख़िर भाजपा पिछले 15 वर्षों से कैसे कार्य करती रही. सभी लोगों की नज़रें क्षेत्रीय नेताओं पर टिकी हुई हैं. वे नेता इस बात को ज़रूर समझ रहे हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई है. मुलायम सिंह, मायावती, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक एवं जयललिता जैसे नेताओं ने इस बात को अब समझ लिया है कि उन्हें पश्चिमी राज्यों की तुलना में ज़्यादा लाभ कभी भी नहीं मिल सकता.

संयोगवश कांग्रेस और भाजपा की आर्थिक नीतियां समान हैं. दोनों ही पार्टियां कॉरपोरेट सेक्टर के पक्ष में हैं. दोनों ही अमेरिकी नीतियों की समर्थन करती हैं, यानी वे अमीरों का समर्थन करती हैं. कांग्रेस और सोनिया गांधी, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं, मनरेगा एवं खाद्य सुरक्षा बिल द्वारा सामाजिक एजेंडे को लागू करने का दबाव डाल रहे हैं. हालांकि पैसों के अभाव के चलते इन योजनाओं को लागू करने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि सरकार के लिए यह संभव ही नहीं है कि वह इन योजनाओं के लिए अनुदान दे. सभी लोगों की नज़रें तीसरे मोर्चे पर टिकी हैं और यही उचित भी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सबसे हास्यास्पद बात यह है कि भाजपा अभी तक यह सोचती रही है कि इस तरह के कट्टर राष्ट्रवाद की स्थिति पैदा करके वह पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है. वह यह भी दलील देती है कि ढेर सारे युवा उसे वोट देते हैं और उसे ही देंगे.

विदेशी भगाओ-स्वदेशी अपनाओ की नीति पर अमल हो

ठाकुर दास बंग

होसकता है कि सरकार क़ानूनों के तहत जबर्दस्ती अनाज ले जाए, लेकिन क्या 55 साल पूर्व बारडोली में ब्रिटिश सरकार ग्रामीणों की एकता के सामने लगान वसूल करने में सफल हो गई थी? वह सत्याग्रह तो क़रीब 100 गांवों तक ही सीमित था, लेकिन आगामी कल का यह सत्याग्रह जब लाखों गांवों में एक साथ होगा, तो सरकार की पाशविक शक्ति कितने लाख लोगों को जेल में डालेगी और बंदूक, टैंक आदि द्वारा कितने लोगों की जान लेगी, यह भी एक सवाल है. आख़िर किसी भी सरकार को लोकतंत्र में पांच साल बाद मतदान के समय जनता के सामने वोट मांगने के लिए जाना ही पड़ता है और यदि आंदोलन थोड़े समय के लिए दबा भी दिया गया, तो भी इससे व्यापक जनजागरण होगा. उसके फलस्वरूप ऐसे ही लोग सत्ता में भेजे जाएंगे, जो ग्रामीण समाज की इस वाजिब मांग को स्वीकार करें. इसलिए या तो प्रारंभ में ही या फिर आंदोलन चलने के कुछ दिनों बाद शासन एवं अर्थव्यवस्था झुकेगी या मतपेटी द्वारा उसे बदल कर न्याय प्राप्त करने का विचार ग्रामीणों के मन में आएगा.

आंदोलन के आह्वान के बाद भी अगर किसान अपना माल बेचने के लिए ले जाएं, तो उन्हें समझा कर, हाथ जोड़कर, अनुनय-विनय करके, उनके सामने सैकड़ों की संख्या में लेटकर और इसी प्रकार के अन्य शांतिपूर्ण उपायों से उन्हें इस दुष्कर्म से रोका जा सकता है. साथ ही साथ जिस कारण से उन्हें नकद रकम की ज़रूरत हो, वह उचित हो, तो गांववासी ऐसे संकट में आए व्यक्ति को कर्ज के रूप में थोड़ी-बहुत सहायता भी कर सकते हैं. ऐसे आंदोलन की तिथि की घोषणा होने पर, जब तक आंदोलन चले, तब तक शादियां आगे धकेली जा सकती हैं, गमी (दु:ख) के प्रसंग अत्यंत कम खर्च में निभाए जा सकते हैं. आंदोलन का अनुशासन तोड़कर यदि कोई माल बेचने जाए, तो उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जा सकता है. जो राजनीतिक नेता, विधायक, मंत्री इस आंदोलन का समर्थन न करें या इस बारे में चुप रहें, या सरकार में होने के बावजूद क्रियान्वयन में टालमटोल करें, उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों-सभाओं का बहिष्कार भी किया जा सकता है. ऐसे लोगों को किसी आयोजन, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने या ऐसे प्रसंगों पर भाषण देने के लिए बुलाया जाए. अगर आंदोलन के समय उनके कार्यक्रमों या सभाओं का बहिष्कार न भी किया जाए, तो उनसे यह ज़रूर पूछा जाए कि आप हमें सड़क, पाठशाला, अस्पताल आदि खिलौने देकर भ्रम में डालने की बजाय हमारे माल का वाजिब दाम मिले, यह हक हमें क्यों नहीं देते हैं? जो नीतियां हमारे ख़िलाफ़ हैं, उन्हें बंद क्यों नहीं करते? इस प्रकार आंदोलन को समर्थन दिलाने वाले विविध कार्यक्रम सोचे जा सकते हैं. देश के सारे गांवों में रात के आठ या नौ बजे घंटा-नाद हो सकता है. इस आंदोलन के दौरान लाखों लोग हज़ारों गांवों में एक-एक दिन के क्रमिक उपवास पर भी बैठ सकते हैं. ऐसे अनेक कार्यक्रम लोगों को सूझेंगे और उनका अवलंबन किया जाएगा. बहिष्कार-आंदोलन के संदर्भ में टेरीलीन-टेरीकॉट आदि वस्त्रों की होली जलाना, कोर्ट-कचहरियों का बहिष्कार, सरकार द्वारा दी गई पदवियां एवं अलंकरण लौटाना, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ताम्रपत्र लौटाना आदि अनेक उपाय आंदोलन में तेजी लाने के लिए किए जाएं. माल का उचित दाम आंकने एवं तय करने के लिए कृषि मूल्य आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व और ग्रामसभा की भागीदारी आदि मुद्दे मुख्य मांग की पूर्ति के लिए जोड़े जा सकते हैं.

असहयोग, बहिष्कार और आवश्यकतानुसार सविनय क़ानून-भंग के नए-नए रास्ते आंदोलन करते-करते लोगों को सूझेंगे और उन पर अमल होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जनता को कुछ कष्टों से होकर ज़रूर गुजरना होगा. उक्त कष्ट कम हों और आंदोलन जल्दी सफल हो, इसलिए इस वाजिब मांग की सहायता के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी चलाया जाएगा. वैकल्पिक स्थायी अर्थव्यवस्था भी इनसे निर्मित होगी, यानी शहर से प्राप्त होने वाली आवश्यक वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का उत्पादन गांवों में ही उचित तकनीक के आधार पर शुरू किया जाए. जैसे-कपड़ा, गुड़, खांडसारी, जूते एवं चप्पल, साबुन, कंपोस्ट खाद इत्यादि. उक्त चीजें गांवों में आसानी से बन सकती हैं और शहर की प्रतियोगिता में टिक सकती हैं. तमिलनाडु के कई जिलों में शहर में बना हुआ टाटा का हमाम या लीवर ब्रदर्स का सनलाइट साबुन मंडियों में क़रीब-क़रीब बिकता नहीं है और ग्रामोद्योगी साबुन अपने गुणों के आधार पर धड़ल्ले से बिक रहा है.

पता चला कि तमिलनाडु की नहाने एवं कपड़े धोने के साबुन की एक चौथाई मांग आज ग्रामोद्योग पूरा कर रहा है. यह प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है. जो बात साबुन के बारे में है, वही बात कम-अधिक अन्य ऊपर बताई गई वस्तुओं के बारे में कही जा सकती है. किसी गांव में कोई एक चीज कच्चे माल के अभाव में न बने, तो अन्य गांवों में बनी हुई वस्तु भी हम व्यवहार में लाएंगे, ऐसा स्वदेशी का संकल्प लोगों में जगाना होगा. इस आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले शहर के भाई-बहन भी ग्रामीण वस्तुओं को व्यवहार में लाने का व्रत लेंगे और नगर में बनी तत्सम वस्तु का बहिष्कार करेंगे. आज खादी का व्यापक वातावरण न होने से और चूंकि नई पीढ़ी ने गांधी या गांधी की खादी को देखा नहीं है, इसलिए शायद टेरीलीन-टेरीकॉट जैसे कृत्रिम रेशे से बने कपड़ों का बहिष्कार प्रारंभ करना पड़े. इससे गांव की लक्ष्मी गांव में ही बने रहने में मदद मिलेगी और शोषण भी घटेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

आंदोलन के आह्वान के बाद भी अगर किसान अपना माल बेचने के लिए ले जाएं, तो उन्हें समझा कर, हाथ जोड़कर, अनुनय-विनय करके, उनके सामने सैकड़ों की संख्या में लेटकर और इसी प्रकार के अन्य शांतिपूर्ण उपायों से उन्हें इस दुष्कर्म से रोका जा सकता है. साथ ही साथ जिस कारण से उन्हें नकद रकम की ज़रूरत हो, वह उचित हो, तो गांववासी ऐसे संकट में आए व्यक्ति को कर्ज के रूप में थोड़ी-बहुत सहायता भी कर सकते हैं.

पाठकों की दुनिया

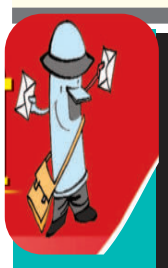

मुर्दा सरकार की मरी हुई सोच

सचमुच चौथी दुनिया समाचारपत्र के विचार एवं लेख इस निर्जीव दुनिया से हटकर हैं. इस समाचारपत्र के कुछ लेख इतने सार्थक हैं कि उन्हें सहेज कर रखना ज़रूरी हो जाता है. आलेख-एक बार फिर कांग्रेस ने गांधी को मारा, काफी अच्छा लगा. बापू की धरोहरें नीलाम तो कर ही दी थीं सरकार ने, लेकिन एक बार फिर जनता की लाज बिकते-बिकते बच गई, क्योंकि बापू को फिर एक बार किसी भारतीय ने बचा लिया. जी हां, बापू को बचाया ही गया है. बापू भले ही जीवित नहीं हैं, लेकिन उनकी यादों के रूप में उनकी चीजें हमारे बीच मौजूद हैं, जो हमेशा उनके होने का आभास दिलाती हैं. यह कांग्रेस है, जिसे इन अमूल्य धरोहरों से कोई मतलब नहीं. आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कांग्रेस इन अमूल्य चीजों के साथ कोई न्याय क्यों नहीं करती? वह अगर इन्हें सहेज-संभाल कर नहीं रख सकती, तो बेचने के पीछे क्यों पड़ी रहती है? कैसी सरकार है यह, जिसे देश की नींव से ही कोई मतलब नहीं है? दरअसल, इस सरकार को देश का पैसा भ्रष्टाचार, लूट एवं घोटालों की भेंट चढ़ाने के अलावा, और किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है.

-अशोक, *मधुबनी, बिहार.*

काश! सरकार ऐसा सोचती

जब तोप मुकाबिल हो के अंतर्गत प्रकाशित-उत्तराखंड की मदद हर भारतीय का कर्तव्य है, पढ़ा. काफी अच्छा लगा. मैं लेखक की राय से शत-प्रतिशत सहमत हूं. अब तक मेरा मानना था कि संपादकों का सरोकार सिर्फ़ बड़े लोगों तक ही होता है, लेकिन संतोष भारतीय ने जिस तरह से उत्तराखंड त्रासदी में तबाह हुए लोगों की मदद के लिए हर भारतीय को हाथ बंटाने का संदेश दिया है, वह काबिल-ए-तारीफ है. आज के दौर में किसी को दूसरे की समस्या से कोई लेना-देना नहीं है. ऐसे में, यह संदेश उत्तराखंड के लोगों के लिए हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है. इस लेख से सरकार की उदासीनता के बारे में साफ़ पता चलता है. सरकार एवं उसके महकमों के रवैये से यह साफ़ झलकता है कि उन्हें इस घटना को लेकर तनिक भी दु:ख नहीं है, क्योंकि वे अभी भी लूट-खसोट में लगे हुए हैं. लानत है ऐसी सरकार पर, जो इस त्रासदी से उबरने के लिए आवंटित पैसों में भी भ्रष्टाचार के नए रास्ते तलाशने लगी है.

-सलोनी, *सासाराम, बिहार.*

राजनेताओं की उपेक्षा ज़रूरी

दरअसल, उत्तरदायित्व का बोध नहीं है देश के नेताओं में. किसी भी व्यक्ति में यह भाव नहीं दिखता कि उसका भी कोई उत्तरदायित्व है. कहीं भी कुछ होता है, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम वहां, उस भीड़ का हिस्सा न बनें. दूसरी तरफ़, हमारे राजनेताओं को भी लड़ने से फुर्सत नहीं है. सच तो यह है कि वे अपने-अपने दांव-पेंच बिठाने में ही लगे रहते हैं. हमें लगता है कि हमें राजनीतिज्ञों का सम्मान अब नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी उपेक्षा करनी चाहिए. न जाओ, न भीड़भाड़ करो, न स्वागत समारोह करो, बंद करो यह सब कुछ. जरा राजनीतिज्ञों को उपेक्षा झेलने दो. देश के लोगों को और ज़्यादा सजग होना पड़ेगा. इतना ज़्यादा सजग होना पड़ेगा कि राजनीतिज्ञ ही क्या, कोई भी देश को धोखा न दे सके. देश का प्रत्येक नागरिक सजग रहे, थोड़ा जागे, वरना यह शोषण जारी रहेगा. यदि हम नहीं जागेंगे, तो इस शोषण का फिर कोई अंत नहीं हो सकता. सदियों से इस देश ने धोखा खाया है. अब समय आ गया है नींद टूटने का. जागो और राजनेताओं से कहो कि अब और नहीं सहेंगे जुल्म ओ सितम.

वास्तविकता से दूर हैं हमारे नेता

इस बात में काफी हद तक सच्चाई है कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता, लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है. देश की 70 फ़ीसद आबादी कृषि पर निर्भर है. जाहिर सी बात है कि खेती अच्छी होने से ही किसानों की आमदनी भी अच्छी होती है. अगर आप हमारे शहर झुमरी तिलैया की बात करें, तो यहां की आधी अर्थव्यवस्था पेड़ों से ही संचालित होती है. दरअसल, जो लोग वातानुकूलित कमरों में बैठकर देश के विकास से संबंधित नीतियां बनाते हैं, वे इस वास्तविकता से कोसों दूर हैं. उनके लिए सच यह है कि सब्जी बाज़ार भी वातानुकूलित मॉल का एक हिस्सा है. दु:ख तो इस बात का है कि ऐसे लोग ही हमारे देश की दशा और दिशा तय करते हैं.

-विकास कुमार पाटनी, *झुमरी तिलैया, झारखंड.*

आपदा पर सियासत

मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से न केवल उत्तराखंड के निवासी, बल्कि पूरी दुनिया के लोग बेहद खफा हैं. वहां फंसे लोगों के साथ अभी भी राजनीति हो रही है.

उत्तराखंड में आई इस प्रलय से पूरा देश सकते में है. पीड़ितों को राहत पहुंचाने के नाम पर गली-मोहल्लों, चौराहों एवं सड़कों पर एनजीओ और राजनीतिक दलों की दुकानें सजी हुई हैं. उक्त सारे लोग पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो राहत सामग्री पीड़ितों के लिए भेजी जा रही है, वह उन तक पहुंच भी रही है या नहीं?

-अर्घ्यप्रदीप, *दिल्ली*

सांप-सीढ़ी का खेल

सांप-सीढ़ी का खेल, कोई पास कोई फेल
सुन सुन सुन, राहुल भैया सुन
अब और सपने तु न बुन
राजनीति सांप-सीढ़ी का है खेल
कोई इसमें होता है पास
तो कोई होता है फेल
सुन सुन सुन, राहुल भैया सुन
यू पी माफिक
दूसरे प्रदेशों में भी
तुम हो जाओगे फेल
सुन सुन सुन, राहुल भैया सुन.

-घनश्याम बेलानी, कटनी, मध्य प्रदेश.

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

चीन पर भारत का रुख लचीला क्यों

जब तोप मुक़ाबिल हो

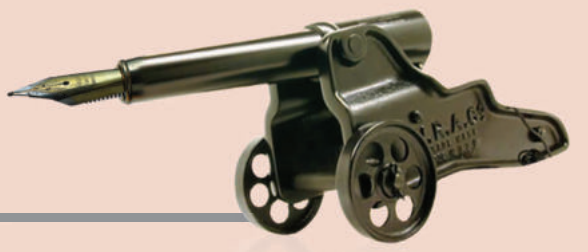

हमारे देश के पिछले कुछ सेनाध्यक्षों ने बार–बार सरकार को चेताया था कि हमारे लिए वास्तविक ख़तरा पाकिस्तान नहीं, बल्कि चीन है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सरकार के नीति निर्धारकों एवं सरकार चलाने वाले प्रमुख लोगों को चीन ने किन्हीं कारणों से अपने प्रभाव में कर लिया है, क्योंकि चीन से ख़तरे का वास्तविक रूप पिछले चार महीने से हमारे सामने आ रहा है.

भारत–चीन सीमा के कई जगहों पर महीनों से चीन कब्जा किए बैठा है. कहीं पर उसने चौकियां बनाई हैं और कहीं पर सिर्फ़ टेंट लगा रखे हैं. भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री एवं प्रधानमंत्री की बातों को चीन कोई महत्व ही नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत सरकार की धमकी, धमकी नहीं है, सिर्फ़ एक दिखावा है. भारत सरकार का कोई भी मंत्री चीन को साफ़ शब्दों में चेतावनी ही नहीं दे रहा. भारतीय सेना, जो पाकिस्तान के सामने दहाड़ती दिखाई देती है, चीनी सेना के सामने उसकी हालत ऐसी लगती है, जैसे बिल्ली के सामने चूहा खड़ा है.

इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनकी तह में भारत की जनता को जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जानबूझ कर इन कारणों का निर्माण किया है. भारत की जनता को इस तथ्य को समझना चाहिए कि पिछले सालों में जानबूझ कर भारतीय बाज़ार को चीनी सामान के लिए खोल दिया गया. चीन का सामान अब हमारे जीवन का अंग बन गया है. यह अकारण नहीं हुआ है. ज़रूर भारत सरकार के अधिकारियों एवं मंत्रियों को चीन ने विदेशों में कुछ न कुछ मदद पहुंचाई होगी, वरना पूरा भारतीय बाज़ार, जिनमें लघु उद्योग एवं बड़े उद्योग भी शामिल हैं, चीन के कब्जे में चला गया है और भारतीय निर्माता धीरे–धीरे बाज़ार से बाहर हो गए हैं. इस समस्या पर किसी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया. चीन द्वारा भारतीय बाज़ार को खोखला किया जाना, कभी भी भारतीय संसद, भारत सरकार और भारत के राजनीतिक दलों की चिंता का विषय नहीं बना. आज इनके कारणों की तलाश शायद कोई न करें, लेकिन कल इतिहास ऐसे लोगों को माफ बिल्कुल नहीं करेगा, जिन्होंने भारतीय बाज़ार को बर्बाद करने में चीनी हितों का साथ दिया है.

जो सबसे ख़तरनाक काम भारत सरकार ने किया है, वह है हमारे संचार क्षेत्र में चीन का सारा सामान लगा देना. भारत सरकार के संचार क्षेत्र में 90 प्रतिशत सामान चीन का बना हुआ लगा है और इसीलिए हमारी कोई भी बातचीत बीजिंग में बैठे या बीजिंग द्वारा स्थापित किए गए भारतीय जासूसी केंद्रों के पास सीधे पहुंच रही है. हमारी सारी जानकारियां, चाहे वे रक्षा संबंधी हों, राजनीति संबंधी हों, व्यापार संबंधी हों, या फिर सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, वे सब भारत की जनता या भारतीय मीडिया तक पहुंचने से पहले ही चीन के पास पहुंच जाती हैं. हमारे सारे सर्वर, हमारा पूरा संचार क्षेत्र और उसमें लगी हुई एक–एक चीज चीन निर्मित है. इसलिए चीन जिस दिन चाहे, हमारी संचार व्यवस्था ठप्प कर सकता है. हमारी तकनीक का पूरा दखल चीन के पास है. इस फ़ैसले को करने में जिन सरकारों ने रोल प्ले किया, या जिन सरकारी अधिकारियों के साथ मंत्री शामिल हुए हैं, उनके लिए फौरन अदालत के दरवाजे खोलने चाहिए और उन पर सार्वजनिक मुकदमा भी चलाना चाहिए.

अब एक और ख़तरनाक स्थिति पैदा हो गई है. भारत के आकाश में चीनी सेटेलाइट घूम रहा है और उस चीनी सेटेलाइट को किराए पर लेने का काम भारत के एक प्रमुख उद्योगपति ने किया है. जब चाइनीज सेटेलाइट श्रीलंका द्वारा लिया जा रहा था, तब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसका कड़ा विरोध किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि हमारी सारी सुरक्षा संबंधी जासूसी इस सेटेलाइट के जरिये होगी और चीन के पास सारी जानकारियां पहुंच जाएंगी, लेकिन अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के विरोध के बावजूद, भारतीय आकाश पर भारत के एक प्रमुख उद्योगपति ने चीनी सेटेलाइट किराए पर ले लिया है. यह उद्योगपति सरकारें चलाने और सरकारी अधिकारियों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए विख्यात है. सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर भारत सरकार ने किस तरह इस सेटेलाइट के उपयोग की अनुमति दी, यह अपने आप में न केवल रहस्य का विषय है, बल्कि खोज का भी विषय है. वे कौन मंत्री या प्रधानमंत्री सीधे इस अनुमति में शामिल हैं, जिन्होंने देश के हितों के ख़िलाफ़ सौदा किया?

इसीलिए आज भारत,चीन को न तो चेतावनी दे पा रहा है और न ही उससे अपनी ज़मीन खाली करा पा रहा है. चीन अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और यही सही समय है, जब चीन अमेरिकी प्रभुत्व को ललकार सकता है. अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चीन को उस पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है. उसे अमेरिका को सबक सिखाने के लिए सिर्फ़ भारत को सबक सिखाना या भारत पर हमला करना जरूरी है. अगर वह भारत पर हमला करता है और भारत अपना उत्तर–पूर्व चीन के हाथों गंवा देता है, तो दुनिया में अमेरिका सबसे कमजोर माना जाएगा और चीन नंबर एक की ताकत के रूप में पहचाना जाएगा. हमारे उत्तर–पूर्व में न तो सैनिक तैयारी है और न राजनीतिक तैयारी. उत्तर–पूर्व में हमने क्या बनाया है, यह गूगल अर्थ में देखकर कोई भी जान सकता है. हमारी सेना की तैयारी भी वहां पूरी नहीं है. यह भी दुनिया की सैनिक पत्रिकाओं में अक्सर छपता रहता है.

पिछले सेनाध्यक्ष ने भारत के प्रधानमंत्री को लगभग 6 या 7 खत लिखे थे, जिनमें सेना की तैयारियों के बारे में प्रधानमंत्री को सीधे जानकारी दी गई थी. सीधे इसलिए दी गई थी, क्योंकि हमारा बाबू तंत्र या हमारी ब्यूरोक्रेसी सेना की ज़रूरतों पर कुंडली मारकर बैठ जाती है और यहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार और कमीशन का सिलसिला. जो ख़बर रक्षा मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि पिछले सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपने पत्र में लिखा है कि अगर हमारी चीन या पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, तो हमारे पास 3 से लेकर 6 दिन तक का गोला–बारूद है, उससे ज़्यादा गोला–बारूद नहीं है.

चीन भारत पर हमला करेगा, यह दीवार पर लिखे सत्य की तरह से हमारी आंखों के आगे है, लेकिन भारत सरकार क्यों इस तथ्य पर आंख बंद किए हुए है, पता नहीं. भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम दूसरी पार्टियां इस सत्य को पहचान नहीं पा रही हैं. तीन महीने पहले सिर्फ़ मुलायम सिंह यादव ने इस सत्य को रेखांकित किया और उन्होंने खुलकर कहा कि भारतीय सेना चीन के सामने कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है. मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं और जाहिर है कि उन्हें हमारी सेना की स्थितियों के बारे में कुछ न कुछ ज़्यादा ज़रूर पता होगा.

इस सत्य का प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि इस बात की जांच की गई कि यह पत्र कहां से लीक हुआ. हम यह मानते हैं कि सेना ने अपनी स्थिति गोला–बारूद के मामले में सुधार ली होगी और हमारे पास अब महीनों लड़ने के लायक गोला–बारूद अवश्य होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है, इसकी स्पर्धा शुरू होने वाली है. और इस प्रतिस्पर्धा का सबसे कड़ा प्रतियोगी हमारा पड़ोसी चीन है, जिसे अमेरिका पर अपना वर्चस्व दिखाना है और उस वर्चस्व को दिखाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला कर, हिंदुस्तान के जरिए अमेरिका पर प्रभुत्व जमाना, उसके लिए सबसे आसान होगा. यह ठीक वैसा ही क़दम होगा, जैसा भारत ने 1971 में बांग्लादेश के विभाजन के समय उठाया था, तब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान में हमारी सेना खुलकर नहीं लड़ पा रही थी. ऐसे में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला करने की योजना बनाई और लाहौर पर हमला किया गया. लाहौर पर भारतीय हमले ने पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान में कुमक भेजने का मौक़ा नहीं दिया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में आज़ाद हुआ. पाकिस्तान अपने सिपाहियों को हिंदुस्तान के हाथों कैद कराकर पश्चिमी मोर्चे पर भी हार गया. अब ठीक वही रणनीति चीन अपनाने जा रहा है और वह उसमें सफल होता भी दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय सेना भीगी बिल्ली की तरह सीमा पर बैठी हुई है.

चीन भारत पर हमला करेगा, यह दीवार पर लिखे सत्य की तरह हमारी आंखों के आगे है, लेकिन भारत सरकार क्यों इस तथ्य पर आंख बंद किए हुए है, पता नहीं. भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम दूसरी पार्टियां इस सत्य को पहचान नहीं पा रही हैं. तीन महीने पहले सिर्फ़ मुलायम सिंह यादव ने इस सत्य को रेखांकित किया और उन्होंने खुलकर कहा कि भारतीय सेना चीन के सामने कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है. मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं और जाहिर है कि उन्हें हमारी सेना की स्थितियों के बारे में कुछ न कुछ ज़्यादा ज़रूर पता होगा. इसलिए उनके उस बयान की रोशनी में भारत सरकार को देश के साथ इतना बड़ा धोखा करने से बचना चाहिए. इस बात की जांच सांसदों के निष्पक्ष दल को सौंपी जानी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि कैसे हमारे आकाश में चीनी सेटेलाइट पहुंच गया, कैसे उसे परमीशन मिल गई और किस तरीके से हमारा पूरा संचार क्षेत्र, जो हमारा मर्म स्थल है, चीनियों के कब्जे में चला गया? इसके बारे में सत्य क्या है, देश के सामने आना चाहिए.

हम भारत की सेना को सबसे ताकतवर एवं बहादुर मानते हैं, लेकिन सेना के जवान अपनी जान देते चले जाएं और उनके हाथ में न अच्छे हथियार हों, न गोला बारूद हो, न टेक्निकल सपोर्ट हो और सिर्फ़ 120 करोड़ लोगों की छाती गोलियां खाते–खाते शांत होती चली जाए, तो इससे बड़ा देशद्रोह का काम और क्या हो सकता है. हम भारत की जनता से सिर्फ़ अपील कर सकते हैं कि वह अपनी आंखें खोले, भारत सरकार पर दबाव बनाए और यह जानने की कोशिश भी करे कि आख़िर ये सारे देशद्रोह के काम हुए कैसे और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? और जो ज़िम्मेदार है, उस पर क़ानून का फंदा पड़ना चाहिए. अन्यथा, हम सचमुच चीन और अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई में घुन बनकर पिस जाएंगे. ■

editor@chauthiduniya.com

भाग–6

संविधान में राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है

डॉ. बी आर अंबेडकर

बंधुत्व एकता की सीढ़ी है

पिछले अंक में आपने 26 जनवरी, 1950 को भारत के प्रजातांत्रिक देश बन जाने के बारे में पढ़ा. इस समापन किस्त में आपसी भाईचारे, बंधुत्व एवं एकता की चर्चा है, जो किसी भी देश और समाज के विकास के लिए परम आवश्यक है.

प्रजातंत्र के लिए दूसरी बात यह ज़रूरी है कि इसमें भाईचारे का सिद्धांत पूरी तरह से स्वीकार किया जाए. अगर भारत के लोग स्वयं को एक मानते हैं, तो भाईचारे का मतलब होता है कि सभी भारतीयों में बंधुत्व की भावना का विकास हो. हालांकि यह इतना आसान नहीं है. यह कितना मुश्किल है, क्या इसके बारे में हमने कभी सोचा है? क्या कभी जेम्स ब्राइस का लेख पढ़कर किसी ने इस पर सोचा? जेम्स ब्राइस ने अमेरिकन कॉमनवेल्थ पत्रिका में संयुक्त राज्य अमेरिका पर लिखे गए अपने लेख में इस बारे में बताया है. उस कहानी को मैं फिर से यहां बता रहा हूं...

कुछ वर्षों पहले अमेरिकी प्रोटेस्टेंट चर्च ने अपनी 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन में चर्च में होने वाली पूजा का तरीका ही बदल दिया. दरअसल, लोगों के मन में यह चाह थी कि प्रार्थना के वाक्य छोटे हों और उनमें राष्ट्र के प्रति एकता का भाव हो. इसे देखते हुए इंग्लैंड ने बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रस्ताव रखा. वे थे, ओ लॉर्ड, ब्लेस आवर नेशन. इसके स्वीकार होने के बाद दूसरे दिन फिर यह वाक्य विचार के लिए लाया गया, जहां ढेर सारी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलीं. लोगों ने इस वाक्य में राष्ट्र को लेकर और अधिक संगठित दिखने की मांग की. अत: यह वाक्य बदल दिया गया. अब नया वाक्य था, ओ लॉर्ड, ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स.

उस समय अमेरिका में थोड़ी–बहुत एकता ही देखने को मिलती थी, क्योंकि उन दिनों अमेरिकी खुद को एक राष्ट्र के रूप में नहीं समझते थे. अगर अमेरिका के लोगों में एक राष्ट्र की भावना नहीं आएगी, तो अंदाजा लगाइए कि एक राष्ट्र वाली इस एकता को भारत के लिए समझना कितना कठिन होगा. मुझे वे दिन अच्छी तरह याद हैं, जब राजनीति की समझ रखने वाले उन भारतीयों ने, जिन्हें हम भारत के लोग कहते हैं, इन बिंदुओं पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी. मेरी राय में हमें एक राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, लेकिन हम भ्रम पाल बैठे हैं. आख़िर कैसे लोग एक देश में विभिन्न जातियों में बंटकर रहते हैं और इसके बावजूद वे उसे राष्ट्र कहते हैं. हाल में मैंने इस चीज को महसूस किया कि अगर सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर देखा जाए, तो अभी तक हम लोग एक राष्ट्र नहीं हैं.

हम कैसे एक राष्ट्र बनें, इस बारे में सोचने के साथ ही गंभीरता से एक राष्ट्र बनने के तरीकों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस लक्ष्य का मतलब समझ पाएंगे. हालांकि यह लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही कठिन है. खास तौर पर अमेरिका की तुलना में बहुत ही कठिन है. अमेरिका में जातिवाद नहीं है, जबकि भारत में जातिवाद की समस्या विकराल है. जातिवाद राष्ट्रवाद के लिए बाधक है. इससे सामाजिक जीवन में पृथकतावाद हावी हो जाता है, जो कि राष्ट्रवाद के ख़िलाफ़ है. जातिवाद की राजनीति से जलन और एक–दूसरे से अलगाव की भावना पैदा होती है. अगर हमारे अंदर सचमुच एक राष्ट्र बनने की चाहत है, तो यह भी तय मानिए कि एक दिन हम अपनी सारी समस्याओं पर विजय पा लेंगे. भाईचारे की भावना की बात करें, तो इस सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्र के बिना इसकी संकल्पना नहीं की जा सकती. भाईचारे या बंधुत्व की भावना के बगैर समानता और स्वतंत्रता की जड़ें गहरी हो ही नहीं सकतीं.

इन बातों से मैं सरोकार रखता हूं, हालांकि कुछ लोगों का इससे कोई लेना–देना नहीं है. इस बात को कोई चुनौती नहीं दे सकता कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक ताकतों का काफी लंबे समय से आधिपत्य रहा है और कुछ लोग सिर्फ़ बोझ ढो रहे हैं. बड़े या कुछ लोगों का यह एकाधिकार उन लोगों के साथ अच्छा होने से नहीं रोक सकता, जो सिर्फ़ बोझ ढोने के लिए अभिशप्त हैं. यह निचला तबका सरकार के इन रवैयों से थक चुका है. वह खुद का शासन चाहता है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मत पर इन पद–दलित लोगों के बीच किसी तरह का वर्ग संघर्ष नहीं होगा. यह किसी घर के बंटवारे के समान होगा, जिसका अंत किसी दिन एक बड़ी तबाही के रूप में होगा. अब्राहम लिंकन ने ठीक ही कहा है कि अपना घर बहुत दिनों तक बंटवारे के साथ नहीं चल सकता. इसलिए जल्द ही ऐसे लोगों के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत होगी, जहां वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को महसूस कर सकें, कुछ लोगों के साथ अच्छा हो सके, देश के लिए अच्छा किया जा सके, इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ध्यान दिया जा सके और इसके प्रजातांत्रिक ढांचे के साथ अच्छा किया जा सके. जीवन के किसी भी रूप में यह सब सिर्फ़ समानता और भाईचारे या बंधुत्व की स्थापना द्वारा ही संभव है. इन बातों पर मैं जोर देना चाहूंगा, क्योंकि बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है.

मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि हमें ऐसा घर मिले, जो थका हुआ और सुस्त हो. इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्रता से खुशी मिलती है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है, उसमें ज़िम्मेदारी भी दी गई है. स्वतंत्रता के बाद अगर कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसके लिए अंग्रेजों को गलत नहीं ठहरा सकते हैं. आज अगर कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ़ हम दोषी हैं. अगर कुछ गलत हो रहा है, तो यह हमारे लिए ही ख़तरनाक है. समय बदल रहा है. लोगों में नई–नई विचारधाराएं पनप रही हैं. सरकार के रवैये के कारण वे थके हुए महसूस कर रहे हैं. वे इसके लिए तैयार हैं कि सरकार लोगों के लिए है और यह उन स्थानों से भिन्न है, जहां लोगों की सरकार है और लोगों द्वारा सरकार है, अर्थात् जहां सरकार में लोगों की भागीदारी है. अगर हम संविधान को संरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें उन सिद्धांतों को स्थापित करना होगा, जिनमें लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों द्वारा सरकार को मान्यता दी गई है.

हमें उन सिद्धांतों की स्थापना के लिए ध्यान देना चाहिए, न कि इसके प्रति उदासीन रवैया अपनाना चाहिए. लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों द्वारा सरकार की यह भावना लेकर चलने से ही हम एक सही मार्ग का निर्माण कर सकते हैं, जो सभी के लिए अच्छा होगा. यह एकमात्र रास्ता है देश सेवा का. मेरी नज़र में इससे बढ़िया रास्ता कोई और हो ही नहीं सकता. ■

(समाप्त)

अगर अमेरिका के लोगों में एक राष्ट्र की भावना नहीं आएगी, तो अंदाजा लगाइए कि एक राष्ट्र वाली इस एकता को भारत के लिए समझना कितना कठिन होगा. मुझे वे दिन अच्छी तरह याद हैं, जब राजनीति की समझ रखने वाले उन भारतीयों ने, जिन्हें हम भारत के लोग कहते हैं, इन बिंदुओं पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी. मेरी राय में हमें एक राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, लेकिन हम भ्रम पाल बैठे हैं.

क्या है विधान मंडल के विशेषाधिकार का हनन

चौथी दुनिया ब्यूरो

इस बार हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में. कैसे और कब फंसता है संसदीय विशेषाधिकार का पेंच? सबसे पहले एक उदाहरण से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं. अमेरिका से एटमी डील के दौरान यूपीए सरकार को जब सदन में विश्वास मत हासिल करना था, उसके कुछ घंटे पहले सदन में भारत के संसदीय इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना हुई. भाजपा के तीन सांसदों ने सदन में नोटों की गड्डियां लहराते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि ये नोट उन्हें विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत के रूप में मिले हैं. इसे एक मीडिया चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अपने कैमरे में कैद करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को सौंप दिया था. बाद में कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों एवं लोगों ने जब सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करके वीडियो टेप्स सार्वजनिक करने की मांग की, तो लोकसभा ने उन टेप्स को सार्वजनिक करने से मना कर दिया.

लोकसभा ने बताया कि वीडियो टेप्स अभी संसदीय समिति के पास हैं और जांच की प्रक्रिया चल रही है. इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह सूचना दिए जाने से धारा–8 (1)(सी) का उल्लंघन होता है. इस धारा में बताया गया है कि ऐसी सूचना, जिसके सार्वजनिक किए जाने से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विशेषाधिकार का हनन होता हो, उसे सूचना के अधिकार के तहत दिए जाने से रोका जा सकता है. ऐसा ही एक मामला और है, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासनिक विभाग से मुख्यमंत्री राहत कोष में मुंबई ट्रेन धमाकों के बाद प्राप्त अनुदानों के ख़र्चों का ब्योरा मांगा था. हालांकि सूचना देने से यह कहकर मना कर दिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष एक निजी ट्रस्ट है और सूचना अधिकार क़ानून के दायरे में नहीं आता, जबकि शैलेष का मानना था कि राहत कोष एक पब्लिक बॉडी है और आयकर छूट का लाभ उठाती है. मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है, इसलिए यह सूचना दिए जाने से विधान मंडल के विशेषाधिकारों का हनन नहीं होता है.

एक मासिक पत्रिका से जुड़े रमेश तिवारी ने उत्तर प्रदेश के स्पीकर एवं स्टेट असेंबली के सचिव को एक आवेदन देकर यह जानना चाहा था कि क्या कोई लेजिसलेटर स्वयं कोई सरकारी ठेका ले सकता है और यदि ऐसा ठेका लिया गया है, तो क्या ऐसे सदस्य की असेंबली से सदस्यता रद्द की जा सकती है? असेंबली से रमेश को जब कोई जवाब नहीं मिला, तो मामले को वह उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष ले गए. आयोग के तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एम ए ख़ान ने स्पीकर एवं सचिव को सूचना अधिकार क़ानून के तहत नोटिस जारी कर दिया. नोटिस पाते ही सबसे पहले तो रमेश का आवेदन ख़ारिज कर दिया गया और उसके बाद असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके माध्यम से सूचना आयोग को चेतावनी दी गई कि उसका इस मामले में कोई लेना–देना नहीं है और इस तरह की सूचना मांगने और आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने से विधान मंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है. यही नहीं, आयोग को आगे से ऐसे मामलों में सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई.

राहुल विभूषण ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और तीन सांसदों के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि मांगी थी. दरअसल, एक पेट्रोल पंप को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण बंद कर दिया गया था. इस पेट्रोल पंप को दोबारा खुलवाने के लिए तीन सांसदों ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा था. राहुल ने इस पत्र के जवाब की प्रतिलिपि मांगी थी, जिसे यह कहकर देने से मना कर दिया गया कि इसे दिए जाने से संसद के विशेषाधिकारों का हनन होता है. आयोग में सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त ने माना कि सांसद द्वारा लिखे गए पत्र का संसद या संसदीय कार्रवाई से किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है और यह सूचना सार्वजनिक किए जाने से संसद के किसी विशेषाधिकार का हनन नहीं होता है. आयुक्त ने मांगी गई सूचना 15 दिनों के भीतर आवेदक को देने का आदेश दिया. कुल मिलाकर देखें, तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा ही नहीं होता है.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप
(राशन दुकान और राशन की मात्रा से संबंधित जानकारी)

सेवा में, **दिनांक....**
लोक सूचना अधिकारी
ज़िला खाद्य आपूर्ति अधिकारी
पता –

विषय :–सूचना का अधिकार क़ानून–2005 के तहत आवेदन.

महोदय, मैं....(नाम)...(गांव का नाम) का निवासी हूं. मेरी राशनकार्ड संख्या....और राशन दुकान संख्या....है. कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं:–

1. मेरे राशनकार्ड पर प्रत्येक महीने जारी किए गए राशन, किरोसिन तेल इत्यादि की मात्रा, जो आपके रजिस्टर में दर्ज है, का पूर्ण विवरण निम्न सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:–

क. महीना.

ख. जारी किए गए राशन और किरोसिन तेल की मात्रा.

ग. तारीख़, जिस दिन राशन और किरोसिन बांटना था.

2. उक्त राशन दुकान से संबंधित पिछले छह माह के निम्नलिखित ब्योरों की एक सत्यापित फोटोकॉपी उपलब्ध कराएं:–

क. मास्टर कार्ड रजिस्टर.

ख. प्रतिदिन की बिक्री का रजिस्टर.

ग. डेली स्टॉक रजिस्टर.

घ. मासिक स्टॉक रजिस्टर.

च. असेसमेंट बुक

छ. कैश मेमो

3. अभी तक उक्त राशन दुकानदार के ख़िलाफ़ कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं? उन पर किस तरह कार्रवाई की गई है? उक्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण दें.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में दस रुपये जमा कर रही/रहा हूं.

भवदीय

नाम.....

हस्ताक्षर.....

पता.....

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा. अपनी चिंता ज़्यादा लोगों से व्यक्त न करें. स्वास्थ्य, विशेषकर उदर एवं नेत्र का ध्यान रखें. विरोधियों से सावधान रहें. उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

वृष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
स्वयं को विचलित होने से बचाएं. उतावलेपन में आकर कोई निर्णय न लें. पारिवारिक विवाद में उलझने की ज़रूरत नहीं है. क़ानूनी मामलों से बचकर चलें. विलासिता से संबंधित कोई वस्तु ख़रीदेंगे. दान–धर्म में रुचि बढ़ेगी. आशा से ज़्यादा सफलता मिलेगी.

मिथुन (21 मार्च से 20 अप्रैल)
अचानक आने वाली कठिनाइयों का आप डटकर सामना करेंगे. स्थान परिवर्तन का योग है, आप यात्रा करने के लिए तैयार रहें. पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव रहेगा. क़ानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय सावधान रहें. वाहन सावधानी से चलाएं. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

कर्क (21 मार्च से 20 अप्रैल)
आपकी कलात्मक एवं आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी. कोई भी नया उधार देने से बचें और पुराना उधार वापस लेने का प्रयास करें. भाषा–शैली पर नियंत्रण रखें. जीवन में जो भी कठिनाई आएगी, उसका आप डटकर सामना करेंगे. दांपत्य जीवन में ख़टास न आने दें. स्वस्थ्य मध्यम रहेगा.

सिंह (21 मार्च से 20 अप्रैल)
यह आपके लिए सामान्य सप्ताह है. परिवार में उमंग एवं उत्साह का वातावरण बना रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लापरवाही न करें. आर्थिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे. जोख़िम वाले बाज़ार में सावधानी से निवेश करें. व्यापारी नए व्यवसाय के विषय में सोचेंगे.

कन्या (21 मार्च से 20 अप्रैल)
सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और आपका उत्साह भी बढ़ेगा. सुख–शांति का अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान में सावधानी बरतें. नौकरीपेशा एवं व्यवसायी, दोनों आम तौर पर खुश रहेंगे. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा. विद्यार्थी सफलता प्राप्त करेंगे.

तुला (21 मार्च से 20 अप्रैल)
सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आय के स्रोत बढ़ेंगे. प्रतिष्ठित एवं संपन्न लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे और आप लाभांवित भी होंगे. कुछ अच्छे कार्य होने के योग हैं. किसी संपत्ति या वाहन आदि का क्रय संभव है. माता– पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

वृश्चिक (21 मार्च से 20 अप्रैल)
छिपे शत्रु परेशान करने की चेष्टा करेंगे. ख़र्च बढ़ेगा और आप तनाव में रहेंगे. कोई पूर्व लंबित कार्य भी बनेगा. बेकार की यात्रा से बचें. पत्नी एवं संतान का स्वास्थ्य चिंता का कारण बनेगा. क्रोध करने से बचें, अन्यथा नुक़सान हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कोई शुभ समाचार मिलेगा.

धनु (21 मार्च से 20 अप्रैल)
अपने निवास पर कुछ नए कार्य पूर्ण करने की चेष्टा करेंगे. योजना के अनुरूप चलने से लाभ होगा. कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी संबंध में कोई कटुता न आए. विद्यार्थियों का प्रदर्शन उत्तम रहेगा. दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव करेंगे. ख़र्चों पर नियंत्रण रखें.

मकर (21 मार्च से 20 अप्रैल)
मेहनत आपकी सफलता का मूलमंत्र बनेगी. स्वभाव बहुत नम्र एवं व्यवहारिक रखेंगे, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अचानक यात्रा से बचें.

कुंभ (21 मार्च से 20 अप्रैल)
विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यर्थ की चिंता, जोख़िम एवं सट्टे से बचें. दुश्मन या विरोधी आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, आप डटकर मुकाबला करें. शुरुआती दौर में आप बनते कार्यों में रुकावट महसूस कर सकते हैं, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मीन (21 मार्च से 20 अप्रैल)
पैसों के लेन–देन में सतर्कता रखें, अन्यथा बात मान–सम्मान तक पहुंचेगी. किसी पुराने रोग की वजह से चिंता होगी. वाहन ख़रीदने के योग हैं. पैसों की कमी महसूस करेंगे. विदेश से संबंधित कोई अच्छी ख़बर मिलेगी.

मनमोहन के असम पर बाढ़ की मार

मनमोहन सिंह ख़ुद को असम का बेटा मानते हैं, लेकिन असम में बाढ़ से निपटने के लिए न तो आज तक कोई दीर्घकालीन योजनाएं बन सकी हैं और न ही प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई व्यवस्था है. लोग खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन पीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए पीएम नहीं बने हैं, वे तो अमीरों के लिए पीएम बने हैं!

एस. बिजेन सिंह

असम इन दिनों बाढ़ की चपेट में है. ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर ख़तरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, इसलिए उसमें सभी तरह की नावों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. क़रीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. राज्य के नौ ज़िलों, धेमाजी, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, करीमगंज, लखीमपुर, मोरिगांव, शिवसागर एवं तिनसुकिया में क़रीब 75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. 5,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है. अनाज के साथ–साथ साग–सब्जी भी बाढ़ की शिकार हो गई है. छोटे–बड़े 30,000 से ज़्यादा जानवर बाढ़ के पानी में बह गए हैं. मोरिगांव जिले के जेंगपुरी इलाके में एक 12 वर्षीय किशोर की मौत हो जाने की ख़बर है. लमदिंग–बडरपुर रेलवे डिवीजन बाढ़ से प्रभावित होने के कारण वहां सामान लाना–ले जाना संभव नहीं है. इसलिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सही समय पर न होने से उनकी क़ीमतें आसमान छू रही हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इन ज़िलों में धारा 144 लागू कर दी गई है.

असम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है और वह स्वयं को असम का बेटा मानते हैं. देश में कहीं बाढ़, तो कहीं सूखा, तो कहीं भयंकर आपदा से लोग परेशान हैं, लेकिन सच पूछिए तो इससे सरकार और सरकार के नुमाइंदे प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि प्रधानमंत्री को यह समझना चाहिए कि सिर्फ हवाई सर्वे कर लेने से प्रभावित लोगों की पीड़ा दूर नहीं हो सकती. प्रधानमंत्री खुद आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, लेकिन उत्तराखंड की आपदा हो या असम में बाढ़ की मार, यानी हर स्तर पर यह सरकार कुछ नहीं कर पाई. आपदा और आपदा के बाद की बदइंतजामी लोगों ने अपनी आंखों से देखी. लोगों ने यह भी देखा कि सरकार और सरकार के उच्चस्थ पदों पर बैठे लोग कैसे घटनास्थल पर जाकर लाशों के साथ राजनीति करते रहे. सरकार घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य तेज करने, खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति, आपदा के बाद लाशों के सड़ने के कारण महामारी न फैले, इसे रोकने के बदले हर जगह भाषणबाजी और बयानबाजी से ही काम चलाती रही. ऐसे सरकार के होने और न होने से क्या फायदा. आखिर मनमोहन सिंह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें असम की चिंता है. वह किस हक के साथ कह सकते हैं कि वह असम के बेटे हैं?

असम में हर साल बाढ़ से करोड़ों रुपये का नुक़सान होता है, लेकिन राज्य एवं केंद्र सरकार ने आज तक कोई ठोस क़दम नहीं उठाए. बाढ़ से निपटने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना भी नहीं बन सकी. राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई राहत न मिलने के कारण बाढ़ पीड़ित खुले आसमान के नीचे दिन काट रहे हैं. बाढ़ में अपना घर–गृहस्थी गंवाने वाले लोग भोजन, पेयजल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से भी परेशान हैं.

पड़ोसी राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नगालैंड में भी मूसलाधार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. यदि समय रहते ठोस क़दम न उठाए गए, तो शहरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर सकता है. गुवाहाटी में बाढ़ का पानी प्रवेश भी कर गया है. सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति धेमाजी की है. जोरहाट के निमातीघाट एवं गोलाघाट के नुमलीगढ़ में ब्रह्मपुत्र और धनश्री नदी का पानी ख़तरे के निशान से ऊपर बह रहा है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे 150 से अधिक परिवार घर छोड़कर चले गए हैं. बाढ़ की चपेट में आए 9 ज़िलों के 16 राजस्व क्षेत्रों के लोग काफी प्रभावित हुए हैं. कई इलाकों में सड़कों, पुलों एवं तटबंधों को काफी क्षति पहुंची है. इसके चलते राज्य के कई संपर्क मार्ग बंद पड़े हैं.

केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने शोणितपुर, लखीमपुर, गोलाघाट एवं बरपेटा में रेड अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इन ज़िलों में अगले कुछ दिनों तक 488 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बीते 3 जुलाई को खानापाड़ा स्थित अपने सरकारी आवास पर एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें जल संसाधन मंत्री राजीव लोचन पेगु, मुख्य सचिव पी पी वर्मा समेत जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वित्त, लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे. बैठक में राज्य में बाढ़ और भू–कटाव की स्थिति पर भी चर्चा की गई. ग़ौरतलब है कि निमातीघाट, मोरिगांव, लखीमपुर, ढेकुवाखाना एवं बरपेटा की बेकी नदी में भू–कटाव लगातार जारी है. धेमाजी के ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (आपदा प्रबंधन) के लुहित गोगोई ने बताया कि ज़िले में पांच राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें 850 लोगों को आश्रय दिया गया है.

उधर, गोलाघाट ज़िले में काजीरंगा नेशनल पार्क के पास एक हाथी एवं एक हिरण के भी मारे जाने की ख़बर है. एक सींग के लिए प्रसिद्ध अपर असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और लोवर असम की पोविटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बाढ़ की चपेट में है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 430 स्क्वॉयर किलोमीटर इलाके में फैले काजीरंगा नेशनल पार्क का 70 प्रतिशत और 38.80 स्क्वॉयर किलोमीटर इलाके में फैली पोविटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बाढ़ की चपेट में है. यहां के वन्यजीव ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं. ये दोनों पार्क पिछले कई सालों से बाढ़ की मार झेल रहे हैं. 1988, 1998, 2004 एवं 2008 में भी यहां भीषण बाढ़ आ चुकी है, जिनमें कई लोगों की जानें चली गईं और काफी लोग बेघर हो गए थे. बाढ़ के चलते काजीरंगा नेशनल पार्क में 1988 में 1203 और 1998 में 652 जानवरों की मौत हो चुकी है. ■

sbijensngh@gmail.com

ज़रा हट के

दुनिया का सबसे सस्ता ऑटो

ऑटो किसी भी शहर की लाइफ लाइन होता है. इसे ही ध्यान में रखते हुए आईईसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मेकैनिकल इंजीनियरिंग के पांच छात्रों ने एक ऐसा ऑटो तैयार किया है, जो दुनिया का सबसे सस्ता ऑटो है. इस खूबसूरत ऑटो को इन छात्रों ने ब्लू पॉड कहा है. इस ऑटो को ढाई महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है और खर्च सिर्फ 55 हजार रुपये. इसके माइलेज में 25 से 28 फीसद तक का सुधार किया गया है. यह ऑटो 70 किलामीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है. इस प्रोटोटाइप ऑटो की सीटें बहुत ही आरामदायक हैं और इसमें तीन सवारियां बहुत ही आराम से बैठ सकती हैं. यह ऑटो इतना खूबसूरत है कि इसे हर कोई घर में भी रख सकता है. इन छात्रों ने बताया कि इस ऑटो में दुर्घटना की चांस भी बहुत कम है, क्योंकि इसमें आगे लगी चीजें दुर्घटना के वक्त टूट जाएंगी और ऑटो में बैठे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा. ■

हुस्नी मुबारक के शासनकाल तक मिस्र की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब रही और उसमें रोज़गार के अवसर न के बराबर थे. मिस्र की विदेश नीति पर अमेरिका एवं इजराइल हावी थे और मावर रफ़ाह के सुरंगी रास्ते इजराइल के इशारों पर ही खोले एवं बंद किए जाते थे, जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब मुर्सी ने 2012 में सत्ता संभाली, तो उन्होंने महसूस किया कि मिस्र की कमज़ोर अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आंतरिक एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ सुधारों की आवश्यकता है.

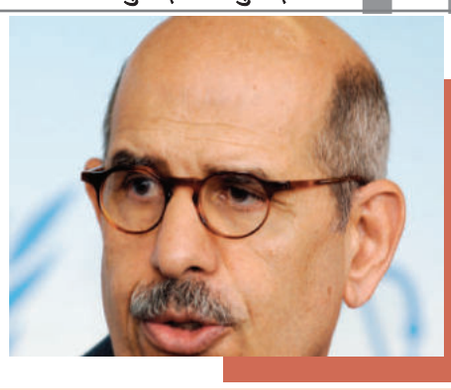

वसीम अहमद

गृहयुद्ध की कगार पर मिस्र

राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना ज़रूरी

हालात साफ़ इशारा कर रहे हैं कि मिस्र में कभी भी गृहयुद्ध छिड़ सकता है. राष्ट्रपति मुर्सी को अपदस्थ किए जाने के बाद स्थितियां जिस तरह से बिगड़ी हैं, वह काफी चिंतनीय है. इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे आवश्यक क़दम उठाए जाएं, जिनसे देश में अमन-चैन कायम रहे.

चौथी दुनिया ने पिछले अंक में मिस्र के हालात पर टिप्पणी की थी और मोहम्मद मुर्सी के ख़िलाफ़ साजिश रचने वालों में मोहम्मद अलबरादई, अमरो मूसा एवं हमदीन सबाही की ओर इशारा करके भविष्यवाणी की थी कि वे 2011 में अपनी राजनीतिक हार का बदला मुर्सी से ले रहे हैं, ताकि मुर्सी को अपदस्थ करने के बाद उन्हें सत्ता पर क़ाबिज़ होने का मौक़ा मिल जाए. चौथी दुनिया की बात सच साबित हुई है और यही तीनों चेहरे कुछ अन्य लोगों को विश्वास में लेकर सत्ता में अपना पसंदीदा पद हासिल करने के लिए खींचतान कर रहे हैं और इसमें सेना एक प्रमुख केंद्र बनी हुई है. सेना न केवल मुर्सी समर्थकों के विरुद्ध बल प्रयोग कर रही है, बल्कि रिपब्लिकन गार्ड हाउस के सामने धरना दे रहे कार्यकर्ताओं और मस्जिद में प्रात:काल की नमाज पढ़ रहे नमाजियों को भी निशाना बना रही है. बावजूद इसके, मुर्सी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि उनके समर्थकों की संख्या दिन-प्रतिदिन और बढ़ रही है. दूसरी तरफ़ विरोधियों में फूट पड़ने लगी है. ऐसे में अगर शीघ्र ही कोई उचित निर्णय न लिया गया या निर्वाचित सरकार वापस न लाई गई, तो आशंका इस बात की है कि देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी.

इस समय मिस्र बेहद गंभीर एवं चिंताजनक हालात से दो-चार है, क्योंकि सेना और मुर्सी समर्थकों के बीच ज़बरदस्त भिड़ंत हो रही है. सेना एवं मुर्सी विरोधी तत्वों ने जो रवैया अपनाया है, उसके चलते देश गृहयुद्ध की ओर अग्रसर है. सेना यह समझ रही है कि 1954 की तरह इख्वानियों को कुचल कर मुर्सी की लोकप्रियता ख़त्म की जा सकती है, लेकिन शायद वह ग़लत सोच रही है. इख्वानी अब पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि वे बहुत सशक्त हो चुके हैं और उनका नेटवर्क धीरे-धीरे समस्त मध्य-पूर्व का मॉडल बनता जा रहा है. इख्वानी विचारधारा के समर्थक कई खाड़ी देशों में विपक्ष का रोल निभा रहे हैं. ऐसी स्थिति में अगर मिस्र की सेना इख्वानियों को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश करती है, तो उसके दुष्प्रभाव पूरे देश को अपनी चपेट में ले सकते हैं. इसलिए सेना को समझना होगा कि वह देश को गृहयुद्ध से बचाए और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे.

मिस्र में सैन्य शासन का लंबा इतिहास रहा है. यही वजह है कि 1952 से लेकर 2011 तक विभिन्न सैन्य शासक यहां छाए रहे और एक लंबे दौर के बाद इस देश को एक निर्वाचित सरकार मिली थी. वरना, पहले जनरल मोहम्मद नजीब, फिर कर्नल जमाल अब्दुल नासिर (जिन्होंने शाही सत्ता के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी), अनवर सादात (जो सैन्य रूढ़िवादिता के समर्थक रहे) और हुस्नी मुबारक (जो सेना का सहारा लेकर सत्ता पर काबिज़ हुए) आदि ने मिस्र की जनता की भावनाओं को रौंदते हुए शासन किया. लेकिन अब, जबकि देश की बागडोर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में दी गई थी, तो सेना प्रमुख अब्दुल फताह अलसीसी को उसका सम्मान करना चाहिए था.

किसी भी देश में सेना की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से सीमा की सुरक्षा होती है, लेकिन मिस्र की सेना सीमा सुरक्षा से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दे रही है कि सत्ता किसके हाथ में हो, देश का शासक कौन हो और इख्वानियों को सत्ता से दूर रहने पर किस तरह विवश किया जाए. इस पूरे परिदृश्य में सेना की भूमिका संदिग्ध है. जिस प्रकार एक निर्वाचित शासक को अपदस्थ करके सरकार गठित की गई है और सत्ता ऐसे लोगों को सौंपी जा रही है, जिनका जनता से कोई सीधा संपर्क नहीं है, ऐसे में यह बात साफ़ है कि सेना के पीछे कोई न कोई ऐसी ताक़त ज़रूर है, जिसके इशारे पर मिस्र में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है. अब सवाल यह उठता है कि आख़िर वे कौन सी ताक़तें हैं, जो मुर्सी से सिर्फ ख़फ़ा ही नहीं थीं, बल्कि उनका तख्ता भी पलटना चाहती थीं? आइए, डालते हैं एक नज़र उन ताक़तों पर, जो मुर्सी को नापसंद करती थीं और जिनके संरक्षण में मिस्र में ये गंभीर एवं चिंताजनक हालात पैदा हुए.

हुस्नी मुबारक के शासनकाल तक मिस्र की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब रही और उसमें रोज़गार के अवसर न के बराबर थे. मिस्र की विदेश नीति पर अमेरिका एवं इजराइल हावी थे और मावर रफ़ाह के सुरंगी रास्ते इजराइल के इशारों पर ही खोले एवं बंद किए जाते थे, जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब मुर्सी ने 2012 में सत्ता संभाली, तो उन्होंने महसूस किया कि मिस्र की कमज़ोर अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आंतरिक एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ सुधारों की आवश्यकता है. इसलिए उन्होंने विदेश नीति में परिवर्तन करके जहां एक ओर अमेरिका एवं यूरोपीय देशों से रिश्ते मज़बूत किए, वहीं दूसरी ओर चीन एवं रूस को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया, बल्कि अगस्त 2012 में चीन का तीन दिवसीय दौरा करके सबको चौंका दिया. यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद अगस्त 2012 में ईरान के आमंत्रण पर तेहरान में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भी शिरकत की. 1980 के बाद किसी भी मिस्री राष्ट्रपति का ईरान का यह पहला दौरा था. इस दौरे ने जहां एक ओर इजराइल एवं यूरोपीय देशों को चौंका दिया, वहीं खाड़ी देशों में भी बेचैनी पैदा कर दी. विशेष रूप से चीन एवं रूस के प्रति मुर्सी का रवैया सीआईए के लिए आश्चर्यजनक था.

मुर्सी की इस विदेश नीति ने भविष्य में मिस्र के हाव-भाव तय कर दिए थे, जो यूरोपीय देशों, सीआईए और इजराइल को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं था. दूसरी ओर आंतरिक रूप से भी मुर्सी को अपने द्वारा किए गए सुधारों को लेकर आलोचना का शिकार होना पड़ा. सबसे पहले वह स्वयं सेना प्रमुख के निशाने पर थे. वजह थी, अब्दुल फताह ख़लील अलसीसी, जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ आर्मी के चेयरमैन हैं और जिन्हें मुर्सी ने ख़ुद अपने शासनकाल में मोहम्मद हुसैन तनतावी द्वारा इस्तीफ़ा देने के बाद यह पद सौंपा था, उनसे मुर्सी चाहते थे कि सुप्रीम काउंसिल ऑफ आर्मी का अधिकार प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाए. हुस्नी मुबारक ने यह अधिकार काउंसिल को संपूर्ण रूप से दिया था, लेकिन मुर्सी चाहते थे कि यह अधिकार राष्ट्रपति के पास रहे. इसीलिए अलसीसी और मुर्सी में मतभेद थे. दूसरी ओर कुछ कट्टरपंथी संगठनों की अपेक्षा थी कि मुर्सी सत्ता में आने के बाद देश में इस्लामी सरकार गठित करेंगे और हुस्नी मुबारक के शासन में इजराइल समेत यूरोपीय देशों की जड़ें, जो मिस्र में मज़बूत हुई हैं, उन्हें उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन मुर्सी ने सत्ता संभालने के बाद अपना पूरा ध्यान देश की अर्थव्यवस्था बेहतर बनाने की ओर केंद्रित कर लिया और इस्लामी एजेंडा लागू करने में रुचि नहीं ली.

दरअसल, मुर्सी चाहते थे कि सभी को साथ लेकर चलें. लिहाज़ा वे संगठन, जो इस्लामी क़ानून लागू होने की उम्मीद कर रहे थे, उनसे असंतुष्ट रहे. उनमें सलफियों का राजनीतिक संगठन अलनूर सबसे आगे था. वैसे जब अलबरादई को प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया, तो यही अलनूर सेना प्रमुख अलसीसी एवं अंतरिम राष्ट्रपति अदली मंसूर से अंतरिम सरकार बनाने के मामले में अलग हो गया. वहीं जब अलबरादई को प्रधानमंत्री न बनाकर अर्थशास्त्री एवं हुस्नी मुबारक के अपदस्थ होने के बाद अंतरिम सैन्य सरकार में जुलाई से नवंबर 2013 तक देश के वित्त मंत्री रहे हाजिम अलबबलावी को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा हुई, तो ख़बरों के अनुसार, यह दोबारा इस नई तब्दीली में शामिल हो गया. दूसरी ओर अलबरादई को उप राष्ट्रपति बनाने पर अलनूर को अभी तक आपत्ति है. इधर मुर्सी समर्थकों का धरना-प्रदर्शन जारी है. मुर्सी समर्थकों और सेना के बीच भिड़ंत में आधिकारिक रूप से, अब तक 60 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ़ इख्वान समर्थक ही नहीं, बल्कि विरोधियों की ओर से भी मुर्सी एवं इख्वान को समर्थन मिलने लगा है.

मुर्सी को अपदस्थ करने के बाद देश में नई-नई घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन हालात बराबर चिंताजनक बने हुए हैं, जो कि अब अलसीसी के लिए सिरदर्द बन गए हैं. जिन लोगों को सत्ता सौंपने की बात हो रही थी, उन पर सहमति नहीं बन पा रही है. ऐसे में, अगर अलसीसी इख्वानियों को नज़रअंदाज़ करके आगे बढ़ते हैं, तो देश में गृहयुद्ध छिड़ने की प्रबल आशंका है. और अगर वह सत्ता पुन: मुर्सी के हवाले करते हैं, तो उन्हें उन ताकतों को संतुष्ट करना होगा, जिनके इशारे पर देश में यह सब कुछ हुआ. अलसीसी को राष्ट्रहित और जनभावनाओं को सर्वोपरि रखना चाहिए. एक सैनिक का यही कर्तव्य होता है कि वह अपने देश के निर्णय का सम्मान करे. इसलिए अलसीसी को चाहिए कि वह सबसे पहले निर्वाचित राष्ट्रपति मुर्सी को रिहा करें और फिर वार्ता के जरिए समस्या का सही हल निकालें. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई

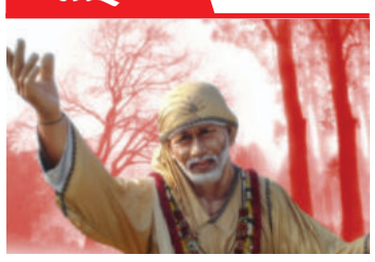

आस्था

दरअसल

> श्री साई बाबा न तो गृहस्थ थे और न वानप्रस्थी. वह तो बाल ब्रह्मचारी थे. उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है. वह तो स्वयं ही भगवान वासुदेव, विश्वपालनकर्ता एवं पारब्रह्म थे. अत: वह भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे.

भिक्षावृत्ति की आवश्यकता

ज्यादातर लोग यही सवाल करते हैं कि साई बाबा यदि इतने श्रेष्ठ पुरुष थे, तो उन्होंने भिक्षावृत्ति को क्यों अपनाया. ऐसे में सवाल यह उठता है कि कौन हैं भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी?

चौथी दुनिया ब्यूरो

संभव है, कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे, तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया. यह प्रश्न दो दृष्टिकोण सामने रखकर हल किया जा सकता है. पहला दृष्टिकोण यह कि भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है. शास्त्रानुसार वे व्यक्ति, जिन्होंने तीन मुख्य आसक्तियों, कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग करके आसक्ति मुक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लिया हो, भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते. अत: उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है.

श्री साई बाबा न तो गृहस्थ थे और न वानप्रस्थी. वह तो बाल ब्रह्मचारी थे. उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है. वह तो स्वयं ही भगवान वासुदेव, विश्वपालनकर्ता एवं पारब्रह्म थे. अत: वह भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे. दूसरा दृष्टिकोण यह कि पंचसूना यानी पांच पाप और उनका प्रायश्चित. सबको ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को पांच प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, कंडणी (पीसना), पेषणी (दलना), उदकुंभी (बर्तन मलना), मार्जनी (मांजना और धोना) और चूली (चूल्हा सुलगाना). इन क्रियाओं के परिणामस्वरूप अनेक कीटाणुओं एवं जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है. उन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने पांच प्रकार के याग (यज्ञ) करने की आज्ञा दी है:–

1. ब्रह्मयज्ञ यानी वेदाध्ययन: ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना.
2. पितृयज्ञ : पूर्वजों को दान.
3. देवयज्ञ : देवताओं को बलि.
4. भूतयज्ञ : प्राणियों को दान.
5. मनुष्य (अतिथि) यज्ञ : मनुष्यों (अतिथियों) को दान. यदि ये कर्म विधिपूर्वक और शास्त्रानुसार किए जाएं, तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है. बाबा द्वार–द्वार जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे, जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का सुअवसर मिल जाता था.

तर्खड कुटुंब (पिता और पुत्र)

श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तर्खड पहले प्रार्थना समाजी जरूर थे, लेकिन वह साथ ही साथ बाबा के परम भक्त भी थे. उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे. एक बार उन्होंने निश्चय किया कि पुत्र एवं उसकी मां ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत नहीं हुआ. दरअसल, उसे यह भय था कि बाबा का पूजन घर में विधिपूर्वक नहीं हो सकेगा, क्योंकि पिता जी प्रार्थना समाजी हैं और इसीलिए यह बहुत संभव है कि वह श्री साई बाबा के पूजनादि का उचित ध्यान न रख सकें. हालांकि पिता द्वारा यह आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि ही होता रहेगा, मां और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया.

दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तर्खड ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और स्नानादि करके पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत होकर बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसे ही आपका पूजन करता रहूंगा, जैसे मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा करके इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना. ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया.

उस दिन की संध्या एवं अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया. सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया. सच तो यह है कि श्री तर्खड ने अपने जीवन में इस प्रकार कभी पूजा नहीं की थी. उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रही है. अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए. दोपहर को घर लौटने पर जब वह भोजन करने के लिए बैठे, तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइए से इस संबंध में प्रश्न किया. रसोइए ने बताया कि आज विस्मृतिवश वह नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं. यह सुनकर वह तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत करके क्षमा याचना करने लगे तथा उनसे उचित पथ प्रदर्शन न करने व पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे. उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्रीचरणों पर रखकर उनसे कहे कि वह इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं. यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तर्खड से कहा, मां, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था. द्वार पर ताला लगा देखा, लेकिन बावजूद इसके मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ (श्री तर्खड) मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं. अत: आज मैं भूखा ही लौट आया हूं. किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु श्री तर्खड का पुत्र, जो समीप ही खड़ा था, सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है, इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया. तर्खड के पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ, उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की. दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले. क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

आस्था

ताराचंडी मंदिर

धार्मिक सद्भाव का प्रतीक

चारों तरफ पहाड़, झरने और जल स्त्रोतों के बीच स्थित ताराचंडी मंदिर का मनोरम वातावरण मन मोह लेता है. यह भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है. अपनी मनोकामनाओं के पूरी होने की लालसा में दूर–दूर से यहां भक्त आते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

ताराचंडी मंदिर

मां ताराचंडी विन्ध्य पर्वत के कैमूर पर्वत श्रृंखला में स्थित है. भारत के अन्य पीठों में इसका स्थान प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में है. इस पीठ के बारे में किंवदंती है कि सती के तीन नेत्रों में से श्री विष्णु के चक्र से खंडित होकर दायां नेत्र यहीं पर गिरा था, जो तारा शक्ति पीठ के नाम से विख्यात हुआ. कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने इस पीठ का नाम तारा रखा था. दरअसल, यहीं पर परशुराम ने सहस्त्रबाहु को पराजित कर मां तारा की उपासना की थी. मां तारा इस शक्तिपीठ में बालिका के रूप में प्रकट हुई थीं और यहीं पर चंड का वध कर चंडी कहलाई थीं. यही स्थान आज सासाराम के नाम से जाना जाता है.

बिहार राज्य के रोहतास जिले में स्थित है यह मंदिर. वस्तुत: यह मंदिर रोहतास जिले के सासाराम शहर में है. सासाराम पहले करूश प्रदेश के नाम से जाना जाता था. यहां का राजा कार्तवीर्यपुत्र सहस्त्रबाहु था. करूश प्रदेश का क्षेत्र कर्मनाशा नदी से लेकर सोनभद्र नदी के बीच का विशाल भूखंड है. यह क्षेत्र मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों और तराइयों से हरा–भरा है. इस मंदिर की एक खास विशेषता है इसका धार्मिक सद्भाव का संदेश. दरअसल, इस मंदिर से सटा एक मस्जिद है, जहां मुसलमान नमाज अदा करते हैं. हिंदू–मुस्लिम भक्तों के साथ पूजा–अर्चना करने के कारण यहां का धार्मिक सद्भाव देखते ही बनता है. इसके अलावा, गुरु तेगबहादुर से जुड़े होने के कारण भी इस मंदिर में सिख धर्म के लोग भी अरदास करने आते हैं. इस धाम पर वर्ष भर में तीन बार उत्सव मनाया जाता है. दोनों नवरात्रों के अलावा, गुरुपूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक पूरे एक माह का यहां विशाल मेला लगता है. साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली जाती है.

भैरव–चंडीकेश्वर महादेव मंदिर

मां ताराचंडी मंदिर के पास ही भैरव–चंडीकेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे सोनवागढ़ शिव मंदिर कहा जाता है. इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. इस मंदिर में सोमवार को काफी भीड़ लगती है. कहा जाता है कि जो भक्त सोमवार को इस मंदिर में दूध और अक्षत चढ़ाते हैं, उन पर भगवान शिव की महिमा जल्द ही बरसती है. इस मंदिर में अन्य भगवान को भी प्रतिष्ठापित किया गया है, जिससे भक्तों को अन्य भगवान के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होता है. मंदिर के आसपास का उपवन और पहाड़ इस मंदिर की सुंदरता में जान फूंक देते हैं. पूरा मंदिर प्रांगण ही शोभायमान है.

मुंडेश्वरी माता का मंदिर

यहां से 60 किलोमीटर पश्चिम में मुंडेश्वरी माता का मंदिर है, जो पहाड़ पर स्थित है. मुंड का वध करने के कारण माता का नाम मुंडेश्वरी पड़ा. आप यहां आने के बाद इस मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं.

परशुराम कुंड

तारा माता के मंदिर के पास ही परशुराम कुंड है, जो मां ताराचंडी के चरणों को पखारता है. श्रद्धालु इसी कुंड में स्नान करके मां की पूजा करते हैं. इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि खाना खाने के बाद इस कुंड का पानी पीते ही तुरंत खाना पच जाता है. यह कुंड अन्य कुंडों से भिन्न है, क्योंकि इस कुंड में बैठने के लिए जगह–जगह पत्थरों के बैठक बने हैं, जिन पर आप बैठकर आसानी से स्नान कर सकते हैं और आपका पैर भी नहीं फिसलेगा. रक्षाबंधन के समय लगभग एक महीने तक यहां लोगों की भारी भीड़ लगती है. कुंड का पूरा वातावरण मनोरम है.

किंवदंतियां अनेक

इस मंदिर को लेकर किंवदंती है कि गौतम बुद्ध ने बोधगया से सारनाथ जाते हुए 21 दिनों तक यहां रहकर मां ताराचंडी की उपासना की थी. इसका उल्लेख मंदिर के गर्भ गृह में स्थित पत्थर पर पाली भाषा में है. इस संबंध में एक और किंवदंती प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि पूरब दिशा में स्थित गोडइला पर्वत पर तारकनाथ नामक स्थान पर ही ताड़का राक्षसी रहती थी, जिसकी लक्ष्मण ने नाक काटी थी.

कहा तो यह भी जाता है कि यहीं ताराचंडी धाम में विश्वामित्र का आश्रम है, जहां उन्होंने राम–लक्ष्मण को दीक्षा दी थी. यहीं पर ताड़का का वध भी हुआ था. यह भी किंवदंती है कि इस स्थान पर गुरु तेगबहादुर ने अपनी पत्नी तथा शिष्यों के साथ ताराचंडी माता का पूजन किया था. आज भी सिख यहां तीन दिन ठहर कर अरदास तथा पूजा करते हैं और गुरु ग्रंथसाहिब का राजभोग, अरदास कर गुरु महाराज को याद करते हैं.

होटल और रेस्टोरेंट

यहां ठहरने के लिए होटल और धर्मशालाएं भी पर्याप्त हैं, जो बहुत ही कम पैसों पर उपलब्ध हैं. आपको ये होटल धर्मशाला और न्यू एरिया कॉलोनी में मिलेंगे. राज्य सरकार का होटल शेरशाह विहार भी यहां आपकी स्वागत के लिए तैयार है. खाने–पीने के लिए यहां उचित होटल, रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं.

कैसे पहुंचें?

देश के प्रमुख शहरों से यहां आप सीधे ट्रेन से पहुंच सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप राज्य बस परिवहन और प्राइवेट सेवा वाली बसों से भी यहां आ सकते हैं. निजी वाहनों से तो आप यहां आ ही सकते हैं. साथ ही शहर में ऑटो की भी बेहतरीन व्यवस्था है. सासाराम के नजदीक जिन शहरों में एयरपोर्ट है, वे हैं वाराणसी, पटना और गया. हवाई जहाज से आप इन शहरों में आकर महज तीन से पांच घंटों में ही मंदिर पहुंच सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

दरअसल

कर्म ही धर्म है

दिलीप कुमार

मतंग ऋषि की बात ही निराली है. कम समय में ही वह प्रसिद्ध हो गए थे. लोग उन्हें जानने लगे थे. पशु–पक्षी, प्रेम किसे कहते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं. दरअसल, वह हमेशा पशु–पक्षियों से मित्रवत् पेश आते थे. कहते हैं कि पशु–पक्षियों के साथ ऋषि का स्नेह देखकर ईश्वर भी उनका सम्मान करते थे. खासकर, गौरैया और कौए से उनका बेहद स्नेह था. उनका इशारा मिलते ही वे दोनों पक्षी उड़ कर मतंग ऋषि के कंधों पर बैठ जाते थे.

यह काफी पहले की बात है. एक दिन शंकर ऋषि मतंग ऋषि की कुटिया के सामने से जा रहे थे. तभी उन्होंने देखा कि मतंग ऋषि कुछ पक्षियों के साथ खेल रहे हैं. पक्षियों को दुलार रहे हैं. उनकी जिज्ञासा जगी. वे मतंग ऋषि के पास आए और बोले, आप इतने बड़े विद्वान हैं, फिर भी आप इन पक्षियों के साथ खेल रहे हैं. इसके बाद शंकर ऋषि ने यह सवाल भी किया कि इससे आपका बहुमूल्य समय नष्ट नहीं होता? सवाल सुन कर मतंग ऋषि मंद–मंद मुस्कुराने लगे. अचानक उन्होंने अपने एक शिष्य को बुला कर कहा कि धनुष लेकर आओ. धनुष सामने था. मतंग ऋषि ने धनुष पर डोरी चढ़ाने के बाद उसे ढीली करके रख दी. ऐसा मतंग ऋषि ने क्यों किया, यह बात शंकर ऋषि को समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने मतंग ऋषि से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया.

मतंग ऋषि ने कहा कि दरअसल, हमारा मन धनुष की तरह है. जिस तरह से धनुष की डोरी बार–बार चढ़ाने से टूट सकता है, ठीक उसी तरह काम न करने से हमारा मन टूट सकता है. पशु–पक्षियों के साथ खेलना भी एक तरह से काम करना है और काम करने से ही मन में एकाग्रता आती है. दरअसल, हम सभी यह जानते हैं कि काम नहीं होने से मन चंचल हो जाता है और इसी दौरान हम गलती कर बैठते हैं. इसलिए मन को बांधने, एकाग्रचित्त करने और शांत करने के लिए हमें हमेशा किसी न किसी रूप में कर्म में लीन रहना चाहिए, क्योंकि इससे मन में हमेशा स्फूर्ति बनी रहती है. मतंग ऋषि का जवाब सुनकर शंकर ऋषि ने हाथ जोड़ कर कहा, अब हम यह समझ पाए कि आपने इतने कम समय में इतनी सफलता कैसे प्राप्त की. इसका मतलब यही है कि कर्म ही धर्म है.

शिक्षा : काम करने से ही शांति मिलती है

व्यक्तित्व

निराला की काव्यकला की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रण–कौशल. चाहे किसी तरह का भाव हो, निराला उन भावों को घुला–मिलाकर ऐसा जीवंत चित्र गढ़ते थे, जिन्हें पढ़ने वाला ही निराला के मर्म तक पहुंच सकता है. निराला के चित्रों में उनका भावबोध ही नहीं, उनका चिंतन भी समाहित रहता है.

कविता

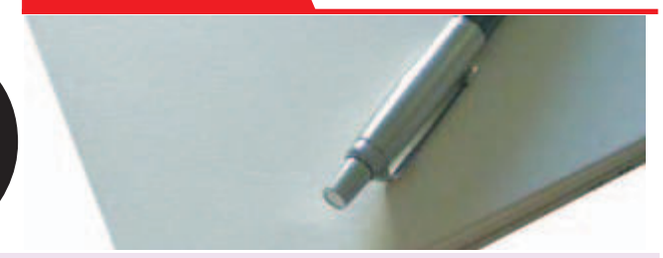

कविता की कठिन राह

कविता के प्रति युवाओं की उदासीनता चिंता का विषय है. समय बदला, समाज बदला और लोगों के सोचने–समझने का तरीका भी बदल गया, लेकिन हमारे कवि जहां के तहां ठहरे रह गए. नतीजतन, हिंदी साहित्य की यह महत्वपूर्ण विधा आज सबसे खराब दौर से गुजर रही है.

अनंत विजय

पिछले दिनों इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कविता पाठ में जाना हुआ, जहां कई कवियों ने अपनी कविताएं सुनाईं. वहीं हमारे एक पुराने कवि मित्र मिल गए. हालांकि हिंदी कविता को लेकर मेरा ज्ञान काफी कम है, लेकिन फिर भी कवि मित्र से समकालीन कविता पर बात शुरू हो गई. वह भी कविता को लेकर खासे निराश दिखे. मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा से साहित्य की प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं में छपते रहे हैं, कविता को लेकर पाठकों की प्रतिक्रियाएं कैसी रहती हैं? उन्होंने बेहद उत्साह से बताया कि देश के कोने–कोने से कविता पर प्रतिक्रियाएं मिलती हैं. सुदूर पूर्वोत्तर से लेकर कभी पटना और गोरखपुर के अलावा, छोटे शहरों एवं कस्बों से भी फोन आते रहते हैं. पहले तो वह कविता पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को लेकर खासे उत्साहित दिखे, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि प्रतिक्रियाएं देने वाले पाठकों की उम्र क्या होती है, तो वह झट से बोल पड़े कि हर उम्र के लोग होते हैं. हालांकि जब बात और आगे बढ़ी, तो मेरे कवि मित्र ने यह स्वीकार किया कि कविता पर प्रतिक्रियाएं देने वाले तकरीबन सभी लोग या तो रिटायर्ड थे, या फिर पचपन साल की उम्र के आसपास के थे. जब मैंने उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया, तो वह चौंके. फिर उन्होंने वहीं खड़े–खड़े एक–दो और कवि मित्रों से इस बाबत बात की, तो पता चला कि उन सबके अनुभव तकरीबन एक जैसे ही थे. सभी के अनुभव में यह एक बात समान रूप से थी कि युवा वर्ग से प्रतिक्रियाएं नहीं मिलती हैं. यह स्थिति हिंदी साहित्य के लिए बेहद चिंता का विषय है. अगर किसी भी भाषा के साहित्य को युवा वर्ग नहीं पढ़ता है, तो इसे लेकर उस भाषा में गंभीर विमर्श के साथ–साथ युवाओं तक पहुंचने के प्रयास भी किए जाने चाहिए. हिंदी में इस वक्त कम से कम पांच सौ कवि एक साथ सक्रिय हैं. अस्सी पार के कवि कुंवर नारायण से लेकर बिल्कुल टटके कवि तक. चार–पांच पीढ़ी की एक साथ सक्रियता चौंकाने वाली है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली है, कविता को लेकर युवा पीढ़ी की उदासीनता.

21वीं सदी के आगाज के साथ उभरे कहानीकारों ने हवा–हवाई और फैशन की कविता लिखनी शुरू कर दी. उनका अनुभव संसार छोटा होता चला गया. सामाजिक सारोकार ख़त्म होते चले गए. रूस के विघटन के बाद भी हिंदी साहित्य अब तक मार्क्सवाद के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया है. विचारधारा की जड़ें हमारे यहां के सृजनात्मक लेखन में इतने गहरे तक हैं कि उन्हें हिलाना एक मुश्किल काम है. आज भी साहित्य की किसी भी विधा में मार्क्स बाबा के नाम के टैग के बगैर आपको गंभीरता से नहीं लिया जाता. यह टैग हिंदी साहित्य के विकास और उसके समय के साथ चलने में सबसे बड़ी बाधा है. विचारधारा के प्रभाव में हुए कविता लेखन ने पाठकों को एक तरह से उबा दिया, क्योंकि हर दूसरी कविता नारेबाजी की तरह होने लगी. दरअसल, विचारधारा के प्रभाव में हुए लेखन से कविता का स्वाद धीरे–धीरे गायब होता चला गया और उसकी जगह नारेबाजी ने ले ली. 21वीं सदी में हमारे समाज में कई बदलाव होने शुरू हुए, जो आज भी लगातार जारी हैं. आप उसे बाज़ारवाद का प्रभाव कहें, वैश्वीकरण का नतीजा कहें, या फिर जो चाहे नाम दे लें, लेकिन समाज के साथ–साथ लोगों की मानसिकता भी बदली. आज की युवा पीढ़ी इतनी स्मार्ट है कि उसे किसी तरह से भी बरगलाया नहीं जा सकता. हिंदी के हमारे ज़्यादातर कवि समय के साथ क़दमताल नहीं कर पाए और इसीलिए लगातार पिछड़ते ही चले गए. इंटरनेट के युग की भाषा अलग है, उसकी मानसिकता अलग है और प्राथमिकताएं भी अलग हैं. इंटरनेट के जमाने में जहां प्यार तक के मायने बदल गए, देह को लेकर वर्जनाएं ख़त्म हो गईं और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले युवा खुद लेने लगे, वहां हमारे कवियों की मानसिकता में कोई खास बदलाव नहीं आ पाया. आज हिंदी के कवियों को उस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है. आज अगर कविता युवाओं से दूर जा रही है, तो उसकी वजह यही सब है. हिंदी के कुछ उत्साही कवियों ने युवाओं को पसंद आने वाली इंटरनेट की भाषा लिखने की कोशिश की, लेकिन वे अतिरेक के शिकार हो गए और संतुलन न बना पाने की वजह से उनका लेखन फूहड़ होता चला गया. हमें इस बात पर गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है कि आज हिंदी में हमारे पास कोई दिनकर, नेपाली, नागार्जुन क्यों नहीं है, जो पाठकों को अपनी ओर खींच सके और उन्हें अपनी कविताएं पढ़वा सके.

युवा पाठकों से कविता के दूर होने के कई संकेत समय-समय पर मिलते रहे हैं. कुछ वजहों की चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूं. दूसरा महत्वपूर्ण संकेत यह है कि हिंदी के कई नामचीन प्रकाशक अब कविता संग्रह छापने से परहेज करने लगे हैं, वहीं कइयों ने तो कविता संग्रह छापना ही बंद कर दिया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि अब कविता संग्रह छपवाने के लिए कवियों को प्रकाशकों की खुशामद करने की हद तक चिरौरी करनी पड़ती है.

युवा पाठकों से कविता के दूर होने के कई संकेत समय–समय पर मिलते रहे हैं. कुछ वजहों की चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूं. दूसरा महत्वपूर्ण संकेत यह है कि हिंदी के कई नामचीन प्रकाशक अब कविता संग्रह छापने से परहेज करने लगे हैं, वहीं कइयों ने तो कविता संग्रह छापना ही बंद कर दिया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि अब कविता संग्रह छपवाने के लिए कवियों को प्रकाशकों की खुशामद करने की हद तक चिरौरी करनी पड़ती है. प्रकाशक कारोबारी होते हैं और वे कोई भी घाटे का सौदा नहीं करना चाहते हैं. कविता की अलोकप्रियता की दूसरी वजह यह है कि हाल के कवियों को नामवर सिंह जैसा कोई आलोचक नहीं मिला. यह हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य है कि नामवर सिंह जैसा कोई आलोचक उसे नहीं मिला, जो अपने दौर के नए से नए कवियों पर नज़र रखे और उनकी कविताओं का नोटिस लेकर पाठक वर्ग तैयार करने में अहम भूमिका निभाए. मैं किसी का नाम लेकर कोई विवाद खड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन यह सर्वविदित तथ्य है कि नामवर सिंह ने कई कवियों एवं कथाकारों को हिंदी में स्थापित किया. यह आलोचक और आलोचना की ताकत थी. नामवर जी अब भी नए से नए लोगों की रचनाओं पर निगाह रखते हैं और उनसे हिंदी साहित्य को परिचित कराते हैं. हिंदी में कई ऐसे आलोचक भी हैं, जो निराला से लेकर मुक्तिबोध तक पहुंचते हैं और फिर लौटकर तुलसीदास तक आ जाते हैं. वैसे आलोचकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे हिंदी के पाठक वर्ग को कविता और कहानी से परिचित कराकर उनकी रुचियों का परिष्कार करेंगे, लेकिन वे नए लेखकों पर गंभीर काम नहीं करते. आलोचकों को लगता है कि वे तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास पर नहीं लिखेंगे, तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाएगा. नामवर जी का उदाहरण उनके सामने है कि किस तरह से संतुलन बनाकर नए लेखकों के साथ खुद को भी स्थापित किया जाता है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

कविता

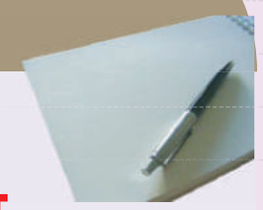

बस तेरे नगमे गाती रहूं

एक गीत सिर्फ उसके लिए
ऐ देश मेरे तू सुबह–सहर मेरे सपनों में बसा रहे
मैं तेरी ही बस बात करूं, तू मेरे ही बस गीत सुने

तेरा चेहरा नूरानी हो, तेरी हर शाम सुहानी हो
मेरे नगमों में गीतों में, बस तेरी एक कहानी हो
मैं तेरी बातें करती हूं, बस तेरे नगमे गाती रहूं

जब दूर कहीं वीराने में, कोई ज़ख्म तुझे मायूस करे
तब तेरी आंख के आंसू, मेरे नगमों में बहने लगे
मैं अपनी कलम की ताकत से, बस तेरा ही वो दर्द कहूं

जब दुश्मन ताक लगाए हो, जब डालों में गिद्ध बसेरा हो
जब सत्ता के दीवानों में, हर शख्स ही एक लुटेरा हो
मैं तेरा दर्द समझ पाउं, मैं तेरे दु:ख की बात करूं

जब अन्ना सा परवाना कोई, अपने हक की बात करे
और सारा देश दीवानों सा, उनके साथ ही चलने लगे
तब मैं भी अन्ना सा गीत लिखूं, और सबके हक की ही बात कहूं

–अनीता वर्मा

किताब मिली

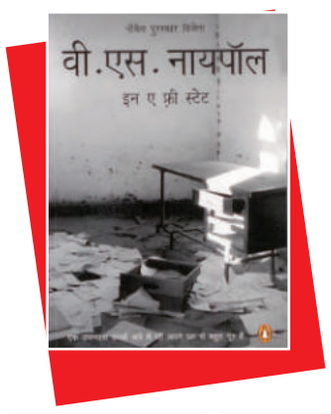

पुस्तक	लेखक
इन ए फ्री स्टेट	वी. एस. नायपॉल
प्रकाशक	**मूल्य**
पेंगुइन बुक्स	250 रुपये

इस उपन्यास के विषय हैं विस्थापन, किसी और की भूमि पर एक अच्छी जगह की इच्छा और इससे संबंधित मनोव्यथाएं.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

व्यक्तित्व

राजीव रंजन

सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

आदर्शों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया

निराला जैसे व्यक्तित्व सिर्फ एक बार पैदा होते हैं. उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में न केवल परिस्थितियों से लोहा लिया, बल्कि अपने आदर्शों और सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया. वह हिन्दी, बांग्ला, अंग्रेज़ी और संस्कृत भाषा में निपुण थे. और क्या थी विशेषता निराला की.

महाप्राण, अपराजेय और सुर्जकुमार जैसे नामों से नवाजे गए निराला भारतीय काव्य के उदीयमान सितारे थे. उनकी कविताएं आज भी काव्य आकाश में गूंजती रहती हैं. वह रूढ़ियों के विरोधी तथा संस्कृति पोषक भी थे. अपने काव्य के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर कठोराघात करने पर अनेक बार उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा. निराला जैसे लोग सिर्फ एक बार ही जन्म लेते हैं. हम यह बात यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि यह उनके काव्य और उनकी सोच में दिखाई देता है. जहां व्यक्ति के आदर्शों और सामाजिक हीनताओं में निरंतर संघर्ष हो, वहां व्यक्ति का मन–मस्तिष्क डोल जाना स्वाभाविक ही है. इस महापुरुष ने समाज के लिए अपना सबकुछ उत्सर्ग कर दिया, लेकिन फिर भी जमाने और समाज ने उसे व्यक्तित्व की अपूर्णता कह कर ठुकरा दिया. भले ही निराला को लोग जीते जी नहीं समझ पाए, लेकिन मृत्यु के बाद आज भी हम उन्हें याद करते हैं. ऐसे थे निराला.

निराला का पूरा काव्य संसार आधुनिक कवियों के लिए वह आईना है, जिसमें आज के कवि अपने काव्य संसार को संवार सकते हैं. आधुनिक कवियों की तरह वह चेहरा देखकर काव्य की रचना नहीं करते थे, बल्कि जो समय और विषय की मांग होती थी, वह अपने काव्य में उतार देते थे. उन्होंने न कभी सत्ता की परवाह की और न ही रसूखदार लोगों की. उन्हें न्याय की परिभाषा भलीभांति मालूम थी, तभी तो उनकी कविताओं में कहीं भी, किसी के साथ अन्याय नहीं दिखता. उन्होंने अपने काव्य में गरीबों, भूखों, परित्यक्ताओं को जगह दी. दरअसल, उनके अंदर बनावटीपन नहीं था. उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जबकि उनका जीवन हमेशा आर्थिक और सामाजिक संघर्षों में गुजरा. कुछ सिरफिरे उनको मानसिक दिवालिएपन का शिकार जरूर मानते हैं, लेकिन ये वैसे लोग हैं, जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं है.

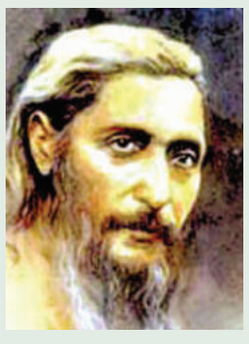

काव्य प्रतिभा

निराला की काव्यकला की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रण–कौशल. चाहे किसी तरह का भाव हो, निराला उन भावों को घुला–मिलाकर ऐसा जीवंत चित्र गढ़ते थे, जिन्हें पढ़ने वाला ही निराला के मर्म तक पहुंच सकता है. निराला के चित्रों में उनका भावबोध ही नहीं, उनका चिंतन भी समाहित रहता है. अक्सर निराला की कविताएं कुछ जटिल हो जाती हैं, जिसे न समझने के नाते विचारक उन पर दुरुहता का आरोप लगाते हैं. निराला पर अध्यात्मवाद और रहस्यवाद जैसी जीवन–विमुख प्रवृत्तियों का भी असर है. इस असर के चलते वह कई बार चमत्कारों से विजय प्राप्त करने और संघर्षों का अंत करने का सपना देखते हैं. उनके प्रयोगों में एक विशेष प्रकार का साहस और सजगता के दर्शन भी होते हैं. यह साहस और सजगता ही निराला को अपने युग के कवियों में अलग और विशिष्ट बनाती है.

बात अगर निराला के गीतों की करें, तो उच्चारण का नया आधार लिए हुए उनके सभी गीतों के छंद और रूप अलग हैं. उनके स्वर, ताल और लय अंग्रेज़ी गीतों से प्रभावित हैं. उनके गीत की मूल भावना श्रृंगारिक है, फिर भी बहुत से गीतों में माधुर्य भाव से आत्मनिवेदन किया गया है. उनके गीतों में जगह–जगह मनोरम प्रकृति–वर्णन तथा उत्कृष्ट देश–प्रेम का चित्रण भी मिलता है.

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

- निराला का जन्म 21 फरवरी, 1896 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था.
- जन्म रविवार को हुआ, इसलिए सुर्जकुमार कहलाए.
- पिता का नाम पंडित रामाश्रय त्रिपाठी था.
- निराला का पैत्रिक गांव गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश है.
- संपूर्ण जीवन आर्थिक संघर्षों में गुजरा.
- निराला की शिक्षा बांग्ला माध्यम से शुरू हुई.
- वह श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और श्री रबीन्द्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे.
- स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने में होती थी.
- संगीत में उनकी विशेष रुचि थी.
- माता–पिता का निधन असमय ही हो गया था.
- पन्द्रह वर्ष की अल्पायु में मनोहरा देवी से विवाह हुआ.
- पत्नी के ज़ोर देने पर ही उन्होंने हिंदी सीखी. इसके बाद अतिशीघ्र ही उन्होंने बांग्ला के बजाय हिन्दी में कविता लिखना शुरू कर दिया.
- उनकी पत्नी की मृत्यु 20 वर्ष की अवस्था में ही हो गई. उनकी पुत्री बहुत कम समय में ही विधवा हो गईं थीं, जिसकी मृत्यु भी तुरंत हो गई.
  चाचा, भाई और भाभी का महामारी में देहांत हो गया.
- 15 अक्टूबर, 1961 को इलाहाबाद में निराला की मृत्यु हो गई.

कृतियां

काव्यसंग्रह : अनामिका, परिमल, गीतिका, द्वितीय अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नये पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा.

उपन्यास : अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा.

कहानी संग्रह : लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, सखी, देवी.

निबंध : रवीन्द्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संग्रह.

पुराण कथा : महाभारत

अनुवाद : आनंद मठ, विष वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपालकुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राजरानी, देवी चौधरानी, युगलांगुल्य, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, भरत में विवेकानंद तथा राजयोग का बांग्ला से हिन्दी में अनुवाद ■

feedback@chauthiduniya.com

> दिल्ली में इसकी एक्स–शोरूम कीमत (राज्य की सब्सिडी मिलने के बाद) 5.96 लाख रुपये रखी गई है. ग्रुप ने बेंगलुरु स्थित कार निर्माता कंपनी रेवा के अधिग्रहण के करीब तीन वर्ष बाद पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है.

कार्बन का नया धमाका

यह 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वॉड-कोर प्रोसेसर, 1 जीबी रैम और एंड्रॉयड 4.2 जेली बीन पर चलता है. इसमें एलईडी फ्लैश और ऑटोफोकस केसाथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

कार्बन टाइटेनियम एस9 लॉन्च हो गया है. ड्यूल सिम वाले इस स्मार्टफोन की कीमत 19,990 रुपये है. इसमें 1280 गुणा 720 रेज्यूलुशन वाला 5.5 ईंच एचडी आईपीएस डिस्प्ले है. यह 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वॉड–कोर प्रोसेसर, 1 जीबी रैम और एंड्रॉयड 4.2 जेली बीन पर चलता है. इसमें एलईडी फ्लैश और ऑटोफोकस के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. इसमें 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज है और 32 जीबी तक का माइक्रोएसडी कार्ड भी यह सपोर्ट करता है. इसमें 2600 एमएच की बैटरी है. पावर–सेवर फीचर्स होने की वजह से बैटरी की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 3जी, वाई–फाई, ब्लूटुथ 4.0 और जीपीएस है. इसमें जी–सेंसर, प्रॉक्सिमिटी और ऐंबियंट लाइट सेंसर हैं. इसके साथ फ्लिप कवर फ्री है.■

3 लाख की कार

> विंसेंट कोबी कहते हैं कि बचत में सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि उसको चलाने पर आने वाली कॉस्ट का पहलू भी जुड़ा है.

दात्सुन जल्द ही अपनी नई कार लॉन्च करने वाली है. कार की थीम इंडोनेशियाई, रूसी और दक्षिण अफ्रीकी थीम से अलग होगी. यह सस्ती कार है. कंपनी कुछ ऐसी वैल्यू पैक्ड कार बनाएगी, जो अमूमन छोटी कारों से बड़ी होगी. ऐसी कारों की छवि इंडियन मार्केट में सेलर्स और बायर्स के बीच पहले से ही बनी हुई है. कंपनी ने इस कार के ऑफिशियल डिजाइन को पहली बार लोगों तक पहुंचाया है. हमने इसे फिनिश्ड प्रोटोटाइप कार बनाने वाली कंपनी निसान के जापानी डिजाइन सेंटर में 15 दिन पहले देखा था. वैसे तो सबसे बड़ा फर्क पैदा करने वाला फैक्टर इसका डिजाइन है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका व्हील बेस दूसरी कारों से लंबा है. चारों पहिए चारों कोने पर होंगे, इसलिए फ्रंट और रियर ओवरहैंग (पहिया से कार के अगले और पिछले हिस्से की दूरी) बहुत कम होगी. इसका मतलब, कार के अंदर काफी जगह होगी, जो इस नए ब्रांड के लिए फर्क पैदा करने वाला दूसरा फैक्टर होगा. दात्सुन की छोटी, लेकिन बहुत

ही अनुभवी टीम ने छोटी कार सेगमेंट के लिए इस शानदार प्रोडक्ट को तैयार करने में बहुत मेहनत की है.

दात्सुन के वरिष्ठ अधिककारी विंसेंट कोबी कहते हैं कि बचत में सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि उसको चलाने पर आने वाली कॉस्ट का पहलू भी जुड़ा है. कोबी जोर देकर कहते हैं कि दात्सुन को हाई ग्रोथ मार्केट्स के उभरते और महत्वाकांक्षी मिडल क्लास के लिए नई नस्ल के ऑटोमोबाइल ब्रैंड के रूप में क्रिएट किया गया है. दरअसल, ऐसे मार्केट में कारों की ऑपरेशनल कॉस्ट को उतनी ही तवज्जो दी जाती है, जितनी उसकी खरीदारी पर और आने वाले खर्च पर ध्यान दिया जाता है.

डिजाइन से साफ लगता है कि दात्सुन की पहली कार हैचबैक होगी. निसान माइक्रा की तरह ही इसमें भी 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन थोड़े अलग जरूर होंगे. इसमें ड्राइवेबिलिटी और टॉर्क पर इस तरह से काम किया जाएगा कि ये फ्यूल एफिशिएंट हों और साथ ही छह पैसेंजर वाली कार को पर्याप्त स्पीड दे सकें. इसमें फ्रंट में बेंच सीट होगी और मिडल में स्प्लिट डाउन, जिसे सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकेगा. इसलिए गियर शिफ्टर और पार्किंग ब्रेक को डैशबोर्ड की तरफ शिफ्ट किया गया है. दात्सुन का कमर्शियल प्रोडक्शन अगले साल के पहले क्वार्टर में शुरू होगा. इसकी कीमत 3 लाख रुपये के आसपास होनी चाहिए. हालांकि अभी इसके डीजल इंजन वर्जन की कोई चर्चा नहीं हुई है.■

एक और महत्वपूर्ण मॉडल

जापानी ऑटो बनाने वाली कंपनी निसान भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) लॉन्च करने की तैयारी में है. इस व्हीकल का नाम है निसान टेरैनो. इस बारे में निसान मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ केनिचिरो योमुरा ने कहा कि टेरैनो के जरिए हमें भारतीय बाजार में बिक्री बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी. योमुरा के मुताबिक, टेरैनो निसान के लिए काफी महत्वपूर्ण मॉडल साबित होगी. ■

शौक से करें वीडियो कान्फ्रेंसिंग

वीडियोकॉन के इस डिवाइस में पांच ईंच की एचडी ओजीएस टचस्क्रीन उपलब्ध कराई जा रही है. यह डिवाइस एंड्रॉयड जैलीबीन 4.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है. ए 55 एचडी में 1.2 गीगा हर्ट्ज की क्षमता वाला क्वाड कोर प्रोसेसर उपलब्ध है. इतना ही नहीं, इसमें आठ मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 3.2 मेगापिक्सल का वेबकैम भी दिया गया है. डिवाइस की रैम एक जीबी की है. साथ ही इसमें चार जीबी की ऑनबोर्ड मेमरी मौजूद है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. यह एक ड्युअल सिम फैबलेट है. बैकअप के लिए इसमें 2000 एमएएच की बैटरी दी गई है. इसमें वाई–फाई और जीपीएस का फीचर भी मौजूद है.■

निसान की बेहतरीन कार

जापान की कार कंपनी निसान मोटर कंपनी ने प्रीमियम हैचबैक माइक्रा केफेसलिफ्ट वर्जन को बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर उतारा है. कीमत 4.8 लाख से 7.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है. नई माइक्रा के साथ ही कंपनी ने वैल्यू पैक बेस रेंज ऐक्टिव लॉन्च किया है. कंपनी ने इसे 3.5 लाख से 4.71 लाख रुपये केबीच चार वेरिएंट में उतारा है. अब इसका 11 वेरिएंट बाजार में है. नई माइक्रा केपेट्रोल वेरिएंट की कीमत 4.80 लाख से 5.43 लाख रुपए केबीच है. वहीं, इसके सीवीटी ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत 6.39 लाख रुपये है. डीजल इंजन वेरिएंट की कीमत है 6 लाख से 7.14 लाख रुपये.

कंपनी ने बताया कि निसान नई ऐक्टिव रेंज के साथ न सिर्फ प्रीमियम बी प्लस सेगमेंट की मारुति सुजुकी स्विफ्ट, होंडा, ब्रीयो, हैचबैक केबायर्स तक पहुंचना चाहती है, बल्कि वह शेव-रले बीट, फोर्ड फिगो, मारुति सुजुकी की वैगन आर जैसे बी सेगमेंट केबायर्स तक भी अपनी पहुंच बनाना चाहती है. कंपनी को उम्मीद है कि नई माइक्रा से वह बायर्स को वैल्यू फॉर मनी डील दे सकेगी. इससे मार्केट में एक बार फिर से निसान को सपोर्ट मिल सकता है.

निसान मोटर इंडिया के प्रेजिडेंट और सीईओ केनिचिरो योमुरा का मानना है कि नई निसान माइक्रा सही समय पर सही प्रोडक्ट है. यह कस्टमर्स को प्रीमियम डिजाइन, परफॉर्मेंस, फीचर्स, सेफ्टी, कम्फर्ट और शानदार अर्बन मोबिलिटी दे पाएगी. हम नई माइक्रा केसाथ ही माइक्रा ऐक्टिव की सेल्स भी अच्छी होगी, यही उम्मीद कर रहे हैं. इसकेयूनीक फीचर्स बायर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे. निसान ने माइक्रा को सबसे पहले भारतीय मॉडल के रूप में पेश किया था. दरअसल, इसे जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था. कंपनी अभी तक 43,000 से अधिक माइक्रा बेच चुकी है. नई माइक्रा के फ्रंट और पीछे के हिस्से को फिर से डिजाइन किया गया है. कार की कुल लंबाई 3825 मिमी होगी, ताकि यूजर्स को अधिक स्पेस मिल सके. माइक्रा निसान ने दावा किया है कि नई माइक्रा ऐक्टिव बेहतर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और कम वजन की वजह से ज्यादा माइलेज (19.49 किलोमीटर प्रति लीटर) देने में सक्षम होगी. माइक्रा ऐक्टिव को डिजाइन और फीचर ऑप्टिमाइजेशन केकारण वाजिब कीमत पर लाया जा सका है. ■

रेवा की इलेक्ट्रिक कार

महिंद्रा ग्रुप ने अपनी पहली बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक रेवा ई–20 लॉन्च कर दी है. दिल्ली में इसकी एक्स–शोरूम कीमत (राज्य की सब्सिडी मिलने के बाद) 5.96 लाख रुपये रखी गई है. ग्रुप ने बेंगलुरु स्थित कार निर्माता कंपनी रेवा के अधिग्रहण के करीब तीन वर्ष बाद पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है. इस मौके पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि इस लॉन्च के साथ ही हमने शहरी पर्यावरण तंत्र के हिसाब से इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है. ग्रुप ने दोपहिया वाहनों में भी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजी लाने की बात कही है. ■

सोएर 5001टी: खाना बनाना हुआ आसान

2000 वाट की उच्च ऊर्जा पर काम करने वाला यह कुकटॉप किसी अन्य पारंपरिक गैस स्टोव की तुलना में ज्यादा तेजी से खाना पकाने में मदद करेगा.

जिन्हें खाना पकाना कठिन कार्य लगता है, उनके रसोई को अब सोएर आसान बना देगा. मौजूदा समय में इंडक्शन कुकर आधुनिक रसोई का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन कभी भी ये इतने स्टाइलिश एवं सुविधाजनक नहीं रहे हैं.

सोएर कंपनी ने इंडक्शन कुकटॉप्स की नई रेंज सोएर आइएन5001टी पेश की है, जो अब व्यस्त गृहिणियों की मदद करेगी. यह अब अच्छा खाना बनाने की शिक्षा देगा. 2000 वाट की उच्च ऊर्जा पर काम करने वाला यह कुकटॉप किसी अन्य पारंपरिक गैस स्टोव की तुलना में ज्यादा तेजी से खाना पकाने में मदद करेगा. निश्चित ही यह कुकिंग को रुचिकर बनाएगा, क्योंकि इस गैजेट में पूरी तरह से पॉलिश्ड क्रिस्टल ग्लासटॉप में हर कमांड आपकी उंगलियों में होगा.

कुकटॉप का त्रुटिहीन फेदर टच सेंसर और चार डिजिट का डिस्प्ले आपको कुकिंग की स्थिति के बारे में जागरूक रखेगा. इसमें आसानी से परिचालित होने वाले प्रि–एडजस्टेड कंट्रोल्स भी हैं, जो कि अस्पष्टता को दूर करते हैं. सोएर का दर्शनीय एवं श्रवणीय अलार्म आपको खाना अधिक पकने से सतर्क रखेगा. इस इंडक्शन में स्वत: बंद होने की विशेषता है, जो बर्तन की अनुपस्थिति में बिजली व्यर्थ नहीं होने देती. यही नहीं, आपके पारंपरिक स्टोव्स की तरह इसमें उष्मा भी व्यर्थ नहीं जाती है. पारंपरिक चूल्हों में खाने के गर्म होने की बजाए रसोई व अन्य सभी चीजें गर्म हो जाती हैं, लेकिन सोएर आइएन 5001 टी के अलग अलग कुकिंग मोड्स एवं आठ प्रोग्राम्स के सेटिंग्स से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और रसोई में आपका समय आनंद के साथ कटेगा. इसकी कीमत है 3,990 रुपये. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

बोपन्ना ने विंबलडन में पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही यह रैंकिंग हासिल की है. उनके करियर की यह सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग भी है. सानिया को छोड़कर लिएंडर पेस, महेश भूपति और सोमदेव देववर्मन की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है.

क्या कोच बदलना ज़रूरी था?

ऑस्ट्रेलिया के माइकल नोब्स फिलहाल भारतीय हॉकी टीम के कोच के रूप में एक महीने के नोटिस पीरियड पर चल रहे हैं. गौरतलब है कि कार्यकाल पूरा किए बगैर निकाले गए नोब्स चौथे विदेशी कोच हैं. हरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय हॉकी में कोचिंग का एक पैटर्न होना चाहिए. हरेंद्र सिंह की ये बातें अनायास नहीं हैं.

पूर्व राष्ट्रीय कोच हरेंद्र सिंह ने कहा है कि बार-बार कोच बदलना समस्या का हल नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि एक खराब शृंखला के बाद कोच या सहयोगी स्टाफ को हटाने से कोई हल नहीं निकलने वाला. दरअसल, भारतीय हॉकी टीम के खराब प्रदर्शन के कारण पिछले दिनों नोब्स को कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हटा दिया गया था. समय से पूर्व किसी कोच को हटाने का यह मामला पहला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी टीम की हार की जवाबदेही कोच पर ही तय की जाती रही है और परिणामस्वरूप कोच को बलि का बकरा बना दिया जाता है. ऑस्ट्रेलिया के माइकल नोब्स फिलहाल भारतीय हॉकी टीम के कोच के रूप में एक महीने के नोटिस पीरियड पर चल रहे हैं. गौरतलब है कि कार्यकाल पूरा किए बगैर निकाले गए नोब्स चौथे विदेशी कोच हैं. हरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय हॉकी में कोचिंग का एक पैटर्न होना चाहिए. हरेंद्र सिंह की ये बातें अनायास नहीं हैं. हम भारतीय हॉकी में यह बात शुरू से ही देखते आए हैं कि जब भी टीम खराब प्रदर्शन करती है, तो सबसे सरल उपाय कोच को बदल देना ही लगता है और ऐसा कर तथाकथित हॉकी के कर्ता-धर्ता सारा ठिकरा कोच के सिर पर फोड़ देते हैं. इस तरह वे न सिर्फ अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं, बल्कि ये साबित भी करने का प्रयास करते हैं कि उन्हें भारतीय हॉकी की काफी चिंता है, वे हाथ पर हाथ धर कर बैठे नहीं रह सकते. हरेंद्र सिंह ने नोब्स की नियुक्ति करने वाली उस समिति को भी आड़े हाथों लिया, जिसके पूर्व कप्तान परगट

सिंह थे. उन्होंने कहा कि कसूर हॉकी इंडिया का नहीं, बल्कि उस समिति का है, जिसने गलत फीडबैक दिया. उन्होंने कहा कि मैं उस समय राष्ट्रीय कोच था, लेकिन उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी. आश्चर्य तो इस बात का है कि उस समय ओल्टमेंस पर तरजीह देकर नोब्स को चुना गया था. उन्होंने कहा कि अब हॉकी इंडिया को चाहिए कि 2016 के रियो डि जनेरियो ओलंपिक तक रोलेंट ओल्टमेंस को टीम की बागडोर सौंप दें. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एम के कौशिक को कोचिंग का अपार अनुभव है, उन्हें राष्ट्रीय कोच बनाया जाए.

भारतीय हॉकी के हाई परफॉर्मेंस मैनेजर रोलेंट ओल्टमेंस को नये कोच की नियुक्ति तक टीम का प्रभार सौंपा गया है. फिलहाल ओल्टमेंस के पास पुरुष टीम की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी. हॉकी इंडिया के महासचिव नरिंदर बत्रा ने बताया कि नोब्स का अनुबंध रद्द कर दिया गया है. बत्रा के अनुसार, नोब्स ने खुद पद छोड़ने का फैसला किया था. नये कोच की नियुक्ति होने में दो से तीन महीने लग जाएंगे.

इस बीच माइकल नोब्स ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें कोच के पद से हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्होंने खुद इस पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है. नोब्स ने इस्तीफा के पीछे अपने खराब स्वास्थ्य को कारण बताया. नोब्स ने बताया कि वह भारतीय हॉकी को बहुत चाहते हैं और इसे किसी तरह से आहत नहीं करना चाहते थे, इसलिए बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण वह इस टीम के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते थे, इसलिए अंततः उन्हें पद छोड़ना पड़ा. ■

बोपन्ना करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर

भारत के रोहन बोपन्ना एटीपी डबल्स रैंकिंग में पांच स्थान की छलांग लगाकर शीर्ष पांच में शामिल हो गए हैं. गौरतलब है कि बोपन्ना ने विंबलडन में पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही यह रैंकिंग हासिल की है. बोपन्ना के करियर की यह सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग भी है. सानिया को छोड़कर लिएंडर पेस, महेश भूपति और सोमदेव देववर्मन की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है. हालांकि सानिया मिर्जा की रैंकिंग में गिरावट आई है. गौरतलब है कि विंबलडन में बोपन्ना और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार रोजर वेसलीन दुनिया की नंबर एक जोड़ी अमेरिका के ब्रायन बंधुओं से हार गए थे, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण बोपन्ना डबल्स रैंकिंग में दसवें से पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं. बोपन्ना के 5380 अंक हैं. पेस 4720 अंकों के साथ नौवें स्थान और भूपति एक स्थान चढ़कर 5225 अंकों के साथ छठे स्थान पर आ गए हैं. महिला डबल्स में सानिया 15वें से 19वें स्थान पर खिसक गई हैं. ■

पंजाब में होगा चौथा विश्व कप कबड्डी टूर्नामेंट

नवंबर माह में होने वाले चौथे विश्व कप कबड्डी टूर्नामेंट की मेजबानी पंजाब करेगा. इस प्रतियोगिता में दुनिया के 25 देश हिस्सा लेंगे. राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इसकी घोषणा की. बादल ने बताया कि पंजाब खेल विभाग ने कबड्डी विश्व कप 2013 के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है. इस टूर्नामेंट में दुनिया के 25 देश हिस्सा लेंगे. बादल ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के दिशा-निर्देशों को भी सख्ती से लागू किया जाएगा. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष खेलों के विकास के लिए 91 करोड़ रुपये का बजट रखा है. ■

वसीम अकरम करेंगे दूसरी शादी

अकरम-शैनेरा अगले साल शादी करेंगे. माना जा रहा है कि दो साल पहले से ही अकरम और शैनेरा डेटिंग कर रहे थे. गौरतलब है कि वसीम अकरम की पहली पत्नी हुमा की 2009 में मौत हो गई थी.

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान वसीम अकरम एक बार फिर शादी करने जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, अकरम ऑस्ट्रेलिया की एक युवती शैनेरा थॉम्पसन के साथ जल्द ही निकाह करेंगे. गौरतलब है कि शैनेरा थॉम्पसन मेलबर्न की पूर्व जनसंपर्क सलाहकार रह चुकी हैं. अकरम-शैनेरा अगले साल शादी करेंगे. माना जा रहा है कि दो साल पहले से ही अकरम और शैनेरा डेटिंग कर रहे थे. गौरतलब है कि वसीम अकरम की पहली पत्नी हुमा की 2009 में मौत हो गई थी. हुमा से अकरम के दो बच्चे हैं.

International Cricket Council

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ताजा रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. इंग्लैंड को तीसरे स्थान पर धकेलते हुए भारत ने दूसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है. आईसीसी द्वारा पिछले दिनों जारी रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम शीर्ष पर है. दक्षिण अफ्रीका के कुल 135 अंक हैं. दूसरे स्थान पर भारत है और वह दक्षिण अफ्रीका से 19 अंक पीछे है. ताजा रैंकिंग में इंग्लैंड तीसरे स्थान पर खिसक गया है. गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीकी टीम ने पिछले 18 महीनों में एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा है. दूसरी श्रृंखलाओं में बेहतर प्रदर्शन न करने के कारण इंग्लैंड रैंकिंग में भारत से एक स्थान नीचे खिसक गया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

ऑलटाइम बेस्ट कप्तान हैं धोनी गांगुली

टीम इंडिया के पूर्व हरफनमौला कप्तान सौरव गांगुली ने माही को वनडे में भारत का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बताया. गांगुली ने कहा कि वनडे में धोनी ही मेरी पसंद हैं. यह बात उन्होंने अपने 41वें जन्मदिन पर कही. उन्होंने कहा कि मैंने धोनी जैसा बल्लेबाजी करने वाला विकेटकीपर नहीं देखा. गांगुली ने कहा कि टेस्ट टीम के कप्तान के बारे में मुझे भले ही सोचना पड़े, लेकिन वनडे में धोनी ही मेरी पसंद हैं. उन्होंने धोनी की तुलना खुद से करने से इंकार कर दिया. गौरतलब है कि गांगुली अब आत्मकथा लिखने के बारे में सोच रहे हैं. ■

धोनी जैसा बल्लेबाजी करने वाला विकेटकीपर नहीं देखा. गांगुली ने कहा कि टेस्ट टीम के कप्तान के बारे में मुझे भले ही सोचना पड़े, लेकिन वनडे में धोनी ही मेरी पसंद हैं.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया
जगमग दुनिया
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467
22 जुलाई–28 जुलाई 2013

सोनू का सपना फिल्म अभिनेता बनने का था और आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सोनू अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं और उनकी चॉकलेटी इमेज भी बरकरार है. बॉलीवुड में सफल होने के लिए और क्या चाहिए?

संजय लीला भंसाली और करण जौहर ने उन्हें अपनी फिल्मों के लिए अप्रोच किया है. गौरतलब है कि ऐश्वर्या की आखिरी फिल्म 2010 में गुजारिश थी. यह संजय लीला भंसाली की फिल्म थी.

जल्द ही पर्दे पर दिखेंगी ऐश्वर्या

ऐश्वर्या राय अब पर्दे पर वापसी करना चाहती हैं, यह खबर तो काफी समय से आ रही है, लेकिन वह जल्द ही कुछ फिल्मों में नजर आएंगी, यह खबर हम दे रहे हैं. दरअसल, वह पूरी तैयारी में हैं. और तो और, उनकी तीन चार फिल्म मेकरों के साथ बातचीत भी चल रही है.

ऐश ने कुछ स्क्रिप्ट्स के लिए अपनी सहमति भी दे दी है, लेकिन वह कुछ फाइनल करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर रही हैं, ताकि उनकी दूसरी पारी शानदार हो. कहा जा रहा है कि ऐश धमाकेदार एंट्री करना चाहती हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद उनके फैंस उन्हें फिल्म में देखेंगे, तो उनकी उम्मीदें पहले से भी ज्यादा होंगी.

खबर है कि संजय लीला भंसाली और करण जौहर ने उन्हें अपनी फिल्मों के लिए अप्रोच किया है. गौरतलब है कि ऐश्वर्या की आखिरी फिल्म 2010 में गुजारिश थी. यह संजय लीला भंसाली की फिल्म थी. इसके बाद 2011 में जब वह मां बनीं, तो उन्होंने लंबा ब्रेक ले लिया, लेकिन अब वह जल्दी ही पर्दे पर वापसी करना चाहती हैं. बेबी के जन्म के बाद उनका वजन काफी बढ़ गया था, लेकिन वह इन दिनों अपने फिगर पर काफी ध्यान दे रही हैं. उन्होंने अपना वेट काफी कम कर लिया है. कान फिल्म फेस्टिवल में भी वह स्लिम और खूबसूरत नजर आईं. अब देखना यह है कि ऐश्वर्या की वापसी कैसी होगी. ■

इंटीमेट सीन से नहीं, गाली से परहेज

निर्देशक अभिषेक चौबे अपनी फिल्म डेढ़ इश्किया को हो सकता है कि उस तरह न बना पाएं, जिस तरह उन्होंने सोचा था. कहा जा रहा है कि उनकी क्रिएटिव सोच के आगे मैडम माधुरी आड़े आ रही हैं. माधुरी ने फिल्म में गाली-गलौज वाली भाषा बोलने से बिल्कुल मना कर दिया है, जबकि इश्किया में विद्या बालन को इससे कोई परहेज नहीं था.

आपको बता दें कि माधुरी इस फिल्म में लीड रोल में हैं. उन्होंने पहले ही इस बारे में अभिषेक को बता दिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि माधुरी ऐसा सच में करेंगी. इस फिल्म में माधुरी का रोल विद्या जैसा नहीं है. माधुरी इसमें बेगम का कैरक्टर प्ले करेंगी. ऐसे में उन्हें विद्या जैसी भाषा बोलने की जरूरत नहीं है. इस फिल्म में माधुरी के अलावा, नसीरुद्दीन शाह भी हैं. कहा यह भी जा रहा है कि माधुरी इस फिल्म में इंटीमेट सीन भी करेंगी, तो माधुरी जी जब आप हॉट सीन्स दे सकती हैं, तो फिर बोलने में क्यों परहेज है. ■

बिग बी की फिल्मों के रीमेक बनेंगे

भले ही चश्मेबद्दूर और हिम्मतवाला जैसी रिमेक फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं किया, लेकिन रीमेक फिल्में बनने का ट्रेंड कम नहीं हुआ है. खबर है कि अब अमिताभ बच्चन की फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता के भी रीमेक बनेंगे. इन्हें जयंतीलाल गाडा प्रोड्यूस कर रहे हैं. अंधा कानून में अमिताभ बच्चन के साथ रजनीकांत थे, जबकि आखिरी रास्ता में अमिताभ के अपोजिट श्रीदेवी और जयप्रदा थीं. आपको बता दें कि गाडा इससे पहले कहानी प्रोड्यूस कर चुके हैं और इन दिनों वह 3डी वर्जन की शोले और ऐक्टर प्रतीक बब्बर के साथ फिल्म इश्क बनाने में बिजी हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि फिलहाल इन फिल्मों के रीमेक को लेकर डील चल रही है. उम्मीद है कि अगले साल इस पर काम शुरू हो जाएगा. अमिताभ बच्चन की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया है. अब देखना यह है कि ये रीमेक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर पाती हैं या नहीं. ■

जन्मदिन पर विशेष

... ऐक्टर नहीं बन सके सोनू

वह ख़ूबसूरती के मिशाल हैं. ख़ूबसूरत आवाज़ ही नहीं, आकर्षक व्यक्तित्व और ख़ूबसूरत मन के भी वह मालिक हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं चर्चित पार्श्व गायक सोनू निगम की. मात्र साढ़े तीन साल की उम्र में सोनू ने गाना शुरू कर दिया था. गायकी उन्हें विरासत में मिली. माता-पिता गायक थे. सोनू निगम के आज देश-विदेश में लाखों-करोड़ों चाहने वाले हैं. आज वह बुलंदियों पर हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं था. एक वक्त ऐसा भी था, जब वह मुंबई की गलियों में खाक छानते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मजबूती से हर मुश्किल का सामना किया और शायद इसीलिए आज वह लाखों-करोड़ों के पसंदीदा गायक हैं.

सोनू 18 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई आए. तब पिता पुत्र दोनों, म्यूज़िक डायरेक्टरों के दफ़्तरों में घंटों प्रतीक्षा करते थे. कई बार तो दफ़्तरों के चपरासी भी उन्हें भगा दिया करते थे. शुरुआती दिनों में वह दिल्ली में बर्थडे पार्टियों और शादियों में गाना गाते थे. समय के साथ उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी. बॉलीवुड में उन्होंने प्लेबैक सिंगर, एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर रेडियो जॉकी जैसे सभी तरह के काम किए. आज वह कामयाब सिंगर हैं. बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि उनका एक और सपना था, बॉलीवुड में एक कामयाब अभिनेता बनने का सपना, लेकिन कहते हैं कि हर ख्वाहिश इंसान की पूरी नहीं होती. सच तो यह है कि अपार कामयाबी के बाद भी उनका यह सपना अधूरा ही रह गया.

अच्छी फिल्म की चाहत आज भी

जी हां, सोनू का सपना फिल्म अभिनेता बनने का था और आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सोनू अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं और उनकी चॉकलेटी इमेज भी बरकरार है. ऐसे में बॉलीवुड में सफल होने के लिए और क्या चाहिए? उनसे पहले भी कई गायकों किशोर कुमार, के एल सहगल, तलत महमूद जैसे लोग अच्छे गायक ही नहीं, अच्छे अभिनेता भी थे. सोनू की भी हमेशा यही तमन्ना रही कि वह कुछेक अच्छी फिल्मों में काम करें और अपनी अभिनय प्रतिभा का भी लोहा मनवाएं. उन्होंने चुनिंदा फिल्में कीं, लेकिन अफसोस वे फ्लॉप रहीं. इस बारे में वह कहते हैं कि उनके पास तक़रीबन 75 फ़िल्मों की स्क्रिप्ट आई थी, लेकिन तब भावुक होकर अपने मित्रों की सलाह पर कुछ फिल्मों के लिए ही उन्होंने हां की. वह कहते हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन उन फ्लॉप फिल्मों के लिए जिम्मेदार अन्य बातें उनके हाथ में नहीं थीं. वह कहते हैं कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने जानी दुश्मन क्यों की. यह फ़िल्म सुपरहिट थी, लेकिन यह बहुत ख़राब फिल्म बनी थी. जब भी कोई यह सवाल करता है, तो मैं उससे कहता हूं कि यही सवाल अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सनी देओल, मनीषा कोइराला, आफ़ताब और इसमें काम करने वाले तमाम बड़े स्टारों से पूछिए. मुझे क्या पता था कि यह फ़िल्म बाद में ऐसी बन जाएगी. ख़राब फिल्म बनने का सबको नुकसान हुआ. हालांकि मुझे थोड़ा ज़्यादा हुआ, क्योंकि वह मेरी पहली फ़िल्म थी, लेकिन वह अपनी एक फ़िल्म लव इन नेपाल को फ्लॉप की श्रेणी में नहीं मानते. वह कहते हैं कि फ़िल्म प्रमोशन शुरू होने के नौ महीने बाद रिलीज़ हुई. फिल्म का प्रमोशन शुरू हुआ जुलाई, 2004 में और रिलीज़ हुई मार्च, 2005 में. यह फिल्म अच्छी बनी थी, लेकिन निर्माता-निर्देशकों ने व्यक्तिगत कारणों से इसे लटका कर रखा. इन खराब अनुभवों के बाद मैंने फिल्म करनी बंद कर दी है. हालांकि सोनू का अभी भी फिल्मों में काम करने का शौक खत्म नहीं हुआ है. वह अच्छी पटकथा पर फिल्म जरूर करना चाहते हैं.

उनके एक मित्र 6 साल से एक फिल्म पर काम कर रहे हैं और इसके लिए सोनू की हां के इंतजार में हैं, लेकिन सोनू की पहली शर्त यही है कि उन्हें निर्माता बढ़िया चाहिए. उनकी दूसरी ख्वाहिश अगले 10-15 सालों में म्यूजिक इंडस्ट्री में कंपनी खोलने की है, ताकि संगीत प्रतिभाओं को आसानी से मौक़ा मिल सके.

साढ़े तीन साल की उम्र में गाना शूरू किया

सोनू के पिता अगम कुमार दिल्ली के एक मशहूर स्टेज सिंगर थे. साढ़े 3 साल की उम्र से वह पिता के साथ स्टेज शो करने लगे. अपने पिता के मार्गदर्शन में सोनू ने अपना करियर आगे बढ़ाया. काफी स्ट्रगल के बाद उन्हें वर्ष 1990 में फिल्म जानम मिला, लेकिन किन्ही कारणों से यह फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी. उन्होंने कई शो में हिस्सा लिया. उन्हें बतौर प्रतियोगी किसी शो में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था, क्योंकि हमेशा वही उस शो के विजेता बनते थे. बाद में उन्हें बतौर जज या गेस्ट बुलाया जाने लगा. उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में टीवी शो सारेगामा होस्ट किया. उन्हें बेहतरीन मौका मिला टी-सीरीज के लिए गाना रिकॉर्ड करने का. इस तरह सोनू निगम को रफ़ी की यादें, से एक नई पहचान मिली. फिल्म सनम बेवफा के गीत अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, के बाद उन्हें अच्छे ऑफर्स आने लगे.

कई भाषाओं में गाया

उन्होंने हर तरह के गाने गाए और अनेक भाषाओं में गाए. कन्नड़, असमी, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, अंग्रेज़ी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम और मराठी में भी उन्होंने गाया.

एलबम दी पॉपुलैरिटी

उनके एलबम ने उन्हें काफी पॉपुलैरिटी दी. उनके एलबम सॉन्स चंदा की डोली..., मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं थी..., दीवाना तेरा..., संदेशे आते हैं..., मेरा रंग दे बसंती चोला..., सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है..., तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कनें चुराए..., तू कब यह मानेगी, तू कब यह जानेगी... और ऐसे ही न जाने कितने गीतों के द्वारा उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बनाई. सोनू ने हिंदी, उड़िया, पंजाबी और कन्नड़ में भी पॉप-एल्बम निकाले. उन्होंने हिंदू एवं इस्लामिक धार्मिक एलबमों के साथ-साथ, मोहम्मद रफ़ी के गानों के एल्बम भी निकाले. उन्होंने अपनी एलबम चंदा की डोली के कई गीत लिखे हैं और कइयों का संगीत निर्देशन भी किया है.

कई सम्मान मिले

सोनू निगम को फिल्म साथिया और कल हो ना हो, के लिए दो बार फिल्म फेयर अवॉर्ड मिला. कल हो न हो, के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवॉर्ड का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला. सोनू निगम को दो बार साउथ के फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर अवॉर्ड मिल चुका है. सोनू ने संगीत के दिवानों के लिए कई बेहतरीन गीत दिए. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

22 जुलाई–28 जुलाई 2013

बिहार–झारखंड

बोधगया बम ब्लास्ट

लापरवाह कौन?

बोधगया बम ब्लास्ट में आतंकियों की मंशा पर इन दिनों तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. बोधगया बम ब्लास्ट और जब्त किए गए बम कम शक्तिशाली माने जा रहे हैं. आख़िर ब्लास्ट के लिए सुबह का समय ही क्यों चुना गया?

सुनील सौरभ

आस्था का केंद्र एवं ज्ञान भूमि पवित्र महाबोधि मंदिर परिसर में नौ सीरियल बम ब्लास्ट की घटना बिहार सरकार तथा बिहार पुलिस की भारी लापरवाही का नतीजा है. इस मामले पर बिहार सरकार और पुलिस के मुखिया अभयानंद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाख सफाई दें, लेकिन वह सुरक्षा में हुई चूक की ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि नौ महीने पूर्व दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े इंडियन मुजाहीद्दीन के दो आतंकवादियों ने यह ख़ुलासा किया था कि महाबोधि मंदिर आतंकियों के निशाने पर है. बावजूद इसके, बिहार सरकार ने इसे

गंभीरता से नहीं लिया और आश्चर्य की बात तो यह है कि सुरक्षा की ज़िम्मेदारी निहत्थे सुरक्षा गार्डों को सौंप दी गई. हालांकि आनन-फानन में महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के मामले पर पुलिस के उच्चाधिकारी बैठकें कर अपने पदाधिकारियों को आदेश निर्देश देकर खानापूर्ति भी करते रहे थे.

दरअसल, 26 जून को ही मगध रेंज के डीआईजी नैयर हसनैन ख़ान ने महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर आपात बैठक की थी. बैठक में यह बात उठी कि महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के लिए जो बात हुई, उसे लागू नहीं किया गया है. सुरक्षा के मद्देनज़र मंदिर के आसपास के इलाक़े को सर्विलांस पर रखना था, मंदिर परिसर के चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना था और लोगों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए इसका एक प्वाइंट भी बोधगया थाने में लगाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि महाबोधि मंदिर में केवल 16 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर महज ख़ानापूरी कर ली गई. महाबोधि मंदिर और बोधगया में आतंकी नहीं घुसे, इसके लिए बोधगया के दोनों एंट्री प्वाइंट्स पर बैरिकेटिंग भी की जानी थी, जो कि अंतत: नहीं की गई. उस समय डीआईजी ने कहा था कि महाबोधि मंदिर की सुरक्षा हम सभी की प्राथमिकता है. इसमें किसी तरह की

(शेष पृष्ठ 18 पर)

किसानों का शोषण कब रुकेगा?

वर्षों से मुंगेर रेल सह सड़क पुल निर्माण योजना अधर में लटकी हुई है. इस योजना के नाम पर न केवल किसानों की उपजाऊ भूमि अधिग्रहण कर ली गई, बल्कि आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके मुआवजे की रक़म को भी आपस में ही बंदरबांट कर लिया गया. कई मुख्यमंत्री आए और चले भी गए, लेकिन किसी ने सही तरह से सुध नहीं ली. क्या है सच्चाई?

शशि सागर

कभी उचित मजदूरी, तो कभी उचित मुआवजा और पुनर्वास को लेकर साहेबपुरकमाल एवं आस-पास के लोग मुंगेर रेल सह सड़क पुल के निर्माण कार्य के विरोध में आवाज़ बुलंद करते रहे हैं. अभी हाल ही में अखिल भारतीय किसान महासभा की विभिन्न मांगों को लेकर आमरन अनशन पर एक बैठक हुई. गौरतलब यह है कि इस अनशन को मजदूरों, किसानों और मेहनतकशों का भरपूर समर्थन मिला. बाद में ज़िला प्रशासन ने अनशनकारियों से 31 जुलाई तक का समय मांगा और साथ ही यह भरोसा भी दिलाया कि इस दौरान उनकी सारी समस्याएं सुलझा ली जाएंगी. गत मई में नीतीश कुमार ने ज़िला परिषद सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में गंगा पर बन रहे मुंगेर-खगड़िया रेल सह सड़क पुल में देरी होने पर नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में रेल मंत्रालय एवं केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा. अगर राशि नहीं मिली, तो राज्य सरकार इसे खुद बनाएगी. वैसे, इस परियोजना में कई पेंच हैं, जिनसे मुख्यमंत्री ख़ुद वाकिफ हैं. बहरहाल, आश्चर्य की बात तो यह है कि अब तक बिहार ने देश को आठ रेल मंत्री दिए हैं, लेकिन किसी भी रेल मंत्री ने यहां के लिए कुछ भी नहीं किया.

यहां कि महत्वाकांक्षी और दयनीय योजना मुंगेर रेल सह सड़क पुल योजना है. यह योजना शुरू से विवादों में है. समय पर यह योजना पूरी तो हुई ही नहीं, बल्कि समय के साथ-साथ विवाद और गहराता गया. गौरतलब है कि मुंगेर और बेगूसराय की जनता इस पुल की मांग वर्षों से करती रही है. मालूम हो कि इसी पुल की वजह से सांसद ब्रह्मानंद मंडल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. दरअसल, हुआ यह कि जनता की मांग और ज़रूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार बिहार सरकार से मुंगेर में बनने वाली पुल का प्रपोजल मांग रही थी. तत्कालीन बिहार सरकार बहुत दिनों तक टालू रवैया अपनाती रही. राज्य सरकार की उदासीनता देख कर मुंगेर से उस समय के सांसद रहे ब्रह्मानंद मंडल अक्टूबर 1994 में आमरण अनशन पर बैठ गए. चौदह दिनों तक चला यह अनशन तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के आश्वासन के बाद टूटा. इस अनशन का परिणाम यह हुआ कि पुल निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार तत्पर हुई, लेकिन ब्रह्मानंद को अपने पद से अंतत: जाना ही पड़ा.

ब्रह्मानंद उन दिनों सीपीआई के एमपी थे और सीपीआई बिहार की तत्कालीन राजद सरकार को समर्थन दे रही थी. पार्टी ने बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए ही मंडल को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जबकि सीपीआई का राज्य अधिवेशन उसी दौरान मुंगेर में हुआ था. पार्टी ने मुंगेर पुल के लिए संघर्ष करने की बात कही थी, लेकिन इस दोहरे रवैए पर सीपीआई के कई नेता आज भी चुप्पी साधे हुए हैं. रेल मंत्री रहते रामविलास पासवान ने न केवल जनता को पुल बनवाने का वादा किया, बल्कि क्षेत्र का हवाई सर्वे (सेटेलाइट सर्वे) भी कराया, लेकिन बात हवा-हवाई निकली. अटल बिहारी बाजपेयी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लाल क़िले से अपने संबोधन के दौरान 921 करोड़ की लागत से बनने वाली मुंगेर सह रेल सड़क पुल की घोषणा की और मार्च 2009 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य भी रखा गया. उसी दिन जम्मू-कश्मीर में भी रेल ब्रिज बनाने की घोषणा की गई थी और पूरा होने का लक्ष्य 2009 ही रखा गया था. जम्मू-कश्मीर के इस ब्रिज का उद्घाटन तो सही समय पर हो गया, लेकिन मुंगेर रेल सह सड़क पुल का निर्माण आज भी अधर में लटक हुआ है.

यहां रेल मंत्री बदलने के साथ ही पुल का एलाइनमेंट भी बदलता रहा, जिसमें जनता के हितों की अनदेखी की गई. सर्वे के बाद रामविलास पासवान ने रेल पुल का एलाइनमेंट साहेबपुरकमाल और उमेश नगर स्टेशन के बीच निर्धारित किया था. पासवान का गृह ज़िला खगड़िया है, इसलिए वे इस योजना में अपने ज़िले को प्रमुखता देना चाहते थे. बाद में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने, तो उन्होंने जनता के अनुरोध पर निर्माण स्थल का दुबारा सर्वे कराया. सर्वे के बाद पुल की दिशा मुंगेर से साहेबपुरकमाल (बेगूसराय) कर दिया गया और रेलवे की ही ज़मीन पर शिलान्यास कर फुल मल्लिक में एलाइनमेंट का निर्धारण किया. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये दिल्ली से ही इसका शिलान्यास किया. उसी समय राजद सरकार के दबंग काबीना मंत्री श्रीनारायण यादव ने एलाइनमेंट का विरोध किया. श्रीनारायण यादव उस समय बलिया विधानसभा से विधायक थे. इसके बाद यादव ने रेल मंत्री के नाम तीन पन्ने का पत्र भी लिखा. पत्र में वे नीतीश की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि आपके इस प्रयास से मुंगेर प्रमंडल में खुशी की लहर दौड़ गई है. मैं अपनी इस भावना को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

» एक नज़र «

अनिल सुलभ का दावा

अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित साहित्योत्सव में डॉ. अनिल सुलभ ने दिल खोल कर अपनी मन की बातें कहीं. उन्होंने कहा कि बिगड़े हुए को बनाना नए निर्माण के मुक़ाबले अधिक कठिन कार्य होता है. वर्षों से सम्मेलन में गंदगी और कीचड़ फैलाई जा रही थी और उसे बाहर से साफ़ किया जाना संभव नहीं था. कीचड़ में उतरने पर उसके कुछ छींटे अपने वस्त्र पर भी पड़ते हैं, लेकिन इसकी चिंता मुझे नहीं थी. सफाई कार्य 90 प्रतिशत हो चुका है, जो थोड़ा शेष बचा है, वह शीघ्र हो जाएगा. अब वह दिन दूर नहीं, जब साहित्य सम्मेलन अपनी खोई हुई गरिमा और लोकप्रियता को प्राप्त कर लेगा. *– शिवानी*

अब प्रदूषण-मुक्त होगा खगड़िया

खगड़िया शहर को सुंदर बनाने के लिए पांच सौ पौधे लगाए जाएंगे. यह निर्णय नगर पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा लिया गया है. समिति के अध्यक्ष शिवराज यादव ने बताया कि फिलहाल शहर में पीपल, नीम, गुलमोहर सहित अन्य फलदार पांच सौ पौधे विभिन्न जगहों पर लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि नगर में पेड़-पौधों की सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम किया जाएगा और इसकी घेराबंदी भी की जाएगी. देखभाल के लिए समय-समय पर प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा.

नगर पंचायत की बैठक

नगर परिषद के बीपीएल लाभार्थियों की सूची एसडीओ को शीघ्र भेजी जाएगी. ये बातें खगड़िया नप अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव ने बैठक के दौरान कहीं. उन्होंने कहा कि शहर में जल जमाव की स्थिति से निपटने का ज़िम्मा सफाई निरीक्षक को सौंपा गया है. वहीं नगर परिषद पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष शिवराज यादव द्वारा 21 लाख 50 हज़ार रुपये की योजना पेश की गई. इस मौक़े पर कार्यपालक पदाधिकारी महेश्वर प्रसाद सिंह, उपसभापति राजकुमार फोगला, वार्ड पार्षद विजय कुमार यादव, उमा भारती, विनय पटेल, रीतिका प्रिया, सोहन चौधरी, सरोजनी देवी सहित अन्य कुछ पार्षद भी मौजूद थे. *– नंदकिशोर शर्मा*

सड़क जाम

अनुमंडल गोगरी के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत देवरी पंचायत के मध्य विद्यालय देवरी के छात्रों ने पूर्व प्रधानाध्यापक कृष्ण मुरारी पर, पोशाक राशि से वंचित करने के कारण विधार्थियों द्वारा महेशखूंट-अगुवानी पथ को जाम कर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की. छात्र रवि कुमार, दीपक कुमार, अमित कुमार, राजीव कुमार सहित दर्जनों छात्रों ने बताया कि जो विद्यार्थी निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हें पोशाक की राशि दी जाती है. पर नियमित रूप से विद्यालय आने वाले छात्रों को सरकारी सहायता से वंचित किया जा रहा है. इस प्रदर्शन में अजय कुमार, रवि कुमार, ललन कुमार, सुमित कुमार, प्रदीप कुमार सहित कई अन्य छात्रों ने भी भाग लिया.

बाल संसद का गठन

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के वार्ड नं.-13 के बुल्लीचंद आदर्श मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक दुनबहादुर दास के नेतृत्व में बाल संसद का गठन किया गया, जिसमें राहुल राज प्रधानमंत्री एवं काजल कुमारी उप प्रधानमंत्री बनीं. इस अवसर पर मनोज कुमार बिहारी, सुनील कुमार सुमन, वेदानंद प्रसाद, राम प्रकाश, प्रमोद कुमार, वंदना कुमारी, प्रतिमा देवी, सरिता कुमारी, रानी कुमारी, दुर्गा कुमारी, दृष्टि प्रज्ञा कुमारी, गीतांजली कुमारी, गुलनाज प्रवीण, जुलेखा खातून, काजल कुमारी, रोहिणी कुमारी सहित दर्जनों छात्र-छात्राएं एवं शिक्षक उपस्थित थे. *– उधव कुमार*

जंक फूड से बचें

ariskon Pharma Pvt.Ltd.

डॉ. रमित गुंजन

पहले और आजकल के समय में लोग तुलना करते हैं और कहते हैं कि बच्चों की हड्डियां मजबूत क्यों नहीं होती इसका जबाव यह है कि पहले बच्चों में विटामिन डी की कमी नहीं होती थी और आज के बच्चों में बिटामीन डी की कमी होती है। पटना के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ रमित गुंजन कहते हैं कि पहले लोगों का घर खुला होता था लेकिन आजकल घरों मे सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। इसके अभाव में शरीर में विटामीन डी की कमी हो जाती है। डॉ. रमित गुंजन बताते हैं कि बच्चे ज्यादातर घर पर कम्प्यूटर या फिर मोबाईल पर खेलते रहते हैं जिसकी वजह से शरीर में धूप नहीं लगती और एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती इस वजह से हमारे शरीर में विटामीन डी की कमी हो जाती है।

बच्चों के भोजन में माताओं को कैल्शियम का ध्यान रखना चाहिए। जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए। बच्चों को अगर बढ़ती उम्र में पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो आगे चलकर उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। श्री गुंजन कहते हैं कि हड्डी सी जुड़ी परेशानी को लेकर मरीजों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पटना में अब उच्च तकनीक पर आधारित अब सारे इलाज उपलब्ध है। ■

ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma
शिवानी

चंपारण का इकलौता आयुर्वेदिक कॉलेज
वजूद बचाने के लिए संघर्ष

इंतेजारुल हक

बिहार सरकार भले ही नए-नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र पर दबाव बनाती है और बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन पूराने मेडिकल कॉलेजों की बेहतरी के लिए उसे कोई चिंता नहीं है. पूर्वी चंपारण ज़िले के मोतिहारी में वर्ष 1955 में स्थापित चंपारण का इकलौता रवींद्र नाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक कॉलेज इसका ताजा उदहारण है. अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा यह महाविद्यालय इन दिनों किसी लुकमान के आने की राह देख रहा है और सुशासन की शिक्षा नीति को मुंह चिढ़ा रहा है. हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब इस विद्यालय में न तो पढ़ाने के लिए शिक्षक बचे हैं और न ही पढ़ने के लिए छात्र. वर्ष 2008 में सीसीआईएम से इस कॉलेज की मान्यता समाप्त हो जाने के बाद से नए सत्र के लिए नामांकन बंद हो गया. कॉलेज की बिगड़ती हालत देख शिक्षक भी अपने को नहीं रोक सके और सामुहिक रूप से त्याग पत्र देकर किसी दूसरे महाविद्यालय में चले गए. वर्तमान में प्राचार्य को मिलाकर क़रीब आधा दर्जन शिक्षक बचे हैं और उन्हीं के कंधे पर कॉलेज की सारी ज़िम्मेदारी है.

आयुर्वेद चिकित्सा की पढ़ाई के मामले में कभी पूरे बिहार में अपना बेहतर पहचान स्थापित करने वाला यह महाविद्यालय अपना वजूद बचाने के लिए इस तरह से संघर्ष करेगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था. जानकार बताते हैं कि वर्ष 2008 में जैसे ही नई शासी समिति आई वैसे ही महाविद्यालय अनेक चुनौतियों से जुझने लगा. शासी समिति की निकम्मी नीति व प्राचार्य की कुर्सी को लेकर लागातार चली गुटबाज़ी भी इस का एक महत्वपूर्ण कारण है. यहां छह वर्षों में आठ बार प्राचार्य बदले और तमाम नियमों व क़ानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं. यहां बता दें कि शासी समिति ने कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक कृष्णमोहन झा को प्राचार्य बनाया और कुछ ही महीनों के बाद फिर पुराने प्राचार्य डॉ. हरिशंकर सिंह ब्रह्मचारी को प्राचार्य बनाया. फिर उनकी कार्यशैली सचिव को पसंद नहीं आई और उन्हें हटाकर डॉ. इंद्रसेन सिंह को प्राचार्य बनाया. बेहतर कार्य करने की क्षमता रखने वाले डॉ. सिंह की भी कार्यशैली शासी समिति ने स्वीकार नहीं की और उन्हें भी कुछ ही महीनों के बाद रास्ता दिखा दिया. फिर कृष्णमोहन झा को प्राचार्य की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. यह ड्रामा लागातार जारी रहा और झा को हटाकर डॉ. विश्वंभर पाठक को प्रभारी प्राचार्य पत्र दिया गया. डॉ. पाठक कॉलेज की व्यवस्था को नहीं सह पाए और फिर डॉ. कृष्णमोहन झा प्राचार्य की कमान संभालने लगे. फिर शासी समिति ने एक नया निर्णय लेते हुए डॉ. हरिशंकर सिंह ब्रह्मचारी को प्राचार्य की कुर्सी पर बैठा दिया, जो अभी वर्तमान में अपनी सेवा दे रहे हैं.

दूसरी तरफ़ कॉलेज के शिक्षक डॉ. प्रो. प्रभाकर शरण, डॉ. प्रो. फिरोज अहमद, डॉ. प्रो. अबु असगर, डॉ. प्रो. अरुण कुमार श्रीवास्तव, डॉ. प्रो. सच्चिदानंद श्रीवास्तव, डॉ. प्रो. संजय कुमार श्रीवास्तव, डॉ. प्रो. विंदेश्वर वर्मा, डॉ. प्रो. अंजु वर्मा, डॉ. प्रो. रामनारायण सिंह, डॉ. प्रो. गणेश सिंह, डॉ. प्रो. अर्जुन सिंह तथा डॉ. प्रो. शिवनारायण सिंह आदि मुजफ्फरपुर स्थित नीतेश्वर महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं. वहीं डॉ. प्रो. ब्रह्मदेव तिवारी, डॉ. प्रो. इस्लाम अंसारी, डॉ. प्रो. नवल किशोर सिंह, प्रो. सत्येंद्र सिंह रांची कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे हैं. पूर्व प्राचार्य बीरगंज स्थित एक मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे हैं. जानकार बताते हैं कि महाविद्यालय के शासी समिति द्वारा एक बार भी ऑडिट नहीं कराई गई जिस कारण बड़े पैमाने पर राशि का बंदरबाट किया गया है. मामले की गहनता से जांच किया जाए तो

अनेक गड़बड़ घोटाले सामने आएंगे. इधर, महाविद्यालय की बदतर हालत के लिए कॉलेज के पूर्व शिक्षक जहां शासी समिति को सीधे दोषी ठहराते हैं. वही शासी समिति के अध्यक्ष प्रेम कुमार इस मामले में खुद को काफ़ी अलग बताते हैं. वे केवल नाम के अध्यक्ष हैं और सारा काम विधायक सह सचिव प्रमोद कुमार व प्राचार्य डॉ. हरिशंकर सिंह ब्रह्मचारी देखते हैं. अध्यक्ष बताते हैं कि सचिव को जो मन में आता है, वही करते हैं और उन्ही के पत्र से प्राचार्य की बहाली होती है और हटाया भी जाता है.

कॉलेज के फंड में कितनी राशि है और इसका उपयोग कहां-कहां हुआ है, वे यह भी नहीं जानते. सबका लेखा-जोखा विधायक के पास है. दूसरी तरफ समिति के सचिव सह नगर विधायक प्रमोद कुमार से उनके मोबाइल नंबर पर उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क साधा गया, लेकिन उनसे बाते नहीं हो सकी. इस बीच प्राचार्य डॉ. ब्रह्मचारी ने भरोसा दिलाया कि महाविद्यालय को शीघ्र मान्यता मिल जाएगी और इस बाबत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. हालांकि सत्ता से भाजपा के अलग होते ही नई शासी समिति बनाने की मांग शुरू हो गई है. इस बीच राजद के जिलाध्यक्ष बच्चा प्रसाद यादव, बब्लू गुप्ता, युवा जिलाध्यक्ष ई. एहतेशाम अहमद, नसीमा खातुन ने कॉलेज बचाव आंदोलन करने की धमकी दी और कहा कि आंदोलन के लिए राजद कार्य योजना तैयार कर रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सिविल सर्जन पर कोई कार्रवाई नहीं

नीरज सिंह

बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया कि डॉ. मंडल के ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए. डॉ. मंडल, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को इस संकल्प के अग्रसारण के एक माह के अंदर अपने बचाव के पक्ष में लिखित दस्तावेज पदाधिकारी एवं अनुशासनिक अधिकारी, पटना, बिहार के समक्ष प्रस्तुत करना है.

नीतीश सरकार को बिहार में जब सत्ता मिली, तो भ्रष्टाचार और भयमुक्त शासन देने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन पूर्णिया सिविल सर्जन रामचरित्र मंडल के ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई के काग़ज़ात पिछले एक वर्ष से सुशासन की फाइलों में ही दबकर रह गई है, लेकिन उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में स्थानीय लोग यह जानना चाहते हैं कि उस सर्जन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई.

गौरतलब है कि पूर्णिया के सिविल सर्जन रामचरित्र मंडल पर करोड़ों की दवा खरीदारी में अनियमितता, अपने चहेते को आउट सोर्सिंग का काम देने, विभागीय नियम के ख़िलाफ़ कार्य करने और फ़र्ज़ी जाति प्रमाण-पत्र पर सिविल सर्जन का पद हथियाने समेत कई तरह के आरोप लगे हैं. इसी आलोक में क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा पूर्णिया प्रमंडल के पत्रांक 149 दिनांक 28/06/2010 758 (9) के आलोक में सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें उल्लेख यह था कि आपके ख़िलाफ़ आरोपों की जांच क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा, पूर्णिया प्रमंडल से कराई गई है. इसमें आरोप प्रमाणित पाया गया है, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया कि डॉ. मंडल के ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए. डॉ. मंडल, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को इस संकल्प के अग्रसारण के एक माह के अंदर अपने बचाव के पक्ष में लिखित दस्तावेज पदाधिकारी एवं अनुशासनिक अधिकारी, पटना, बिहार के समक्ष प्रस्तुत करना है. विभागीय कार्रवाई के संचालन के लिए डॉ. केके सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है. डॉ. मंडल को सुनवाई के लिए संचालन पदाधिकारी के पास स्वयं उपस्थित होना होगा. इस संबंध में पूर्णियां के लोग यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी सिविल सर्जन पर दिनांक 27/06/12 से ही विभागीय कार्रवाई चल रही है, लेकिन आज तक वह पूर्णिया के सिविल सर्जन के पद पर विराजमान हैं, जो सुशासन सरकार की नैतिकता के पोल खोलने के लिए काफ़ी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया रेलवे स्टेशन
बदहाली का ज़िम्मेदार कौन

मनेंद्र कुमार

लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही ज़िले की कई मूलभूत समस्याएं जनता के सामने आ रही हैं. इनमें से एक खगड़िया रेलवे जंक्शन भी है. सूबे में रेलवे को अत्यधिक राजस्व देने वालों में खगड़िया जंक्शन की गिनती भी होती है. यहां मक्का लदान तथा रैक प्वाइंट से करोड़ों की आमदनी होती है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहां कुछ भी नहीं है. इस मुद्दे को लेकर कई बार यहां धरना-प्रदर्शन एवं आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन आश्वासन के बावजूद, कुछ भी नहीं मिला. कई वर्षों से निर्माणाधीन खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेलखंड की लंबाई 44 किमी है, जबकि रेल विभाग द्वारा 2008 में 2 करोड़, 2009 में 2 करोड़, 2010 में 5 करोड़, 2011 में 13 करोड़, 2012 में 15 करोड़ तथा 2013 में 13 करोड़ राशि आवंटित की गई, लेकिन निर्माण कार्य की गति शिथिल है. खगड़िया-मुंगेर गंगा सेतु के लिए 925 करोड़ की योजना बजट में स्वीकृत जरूर हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष यह राशि बढ़ाकर 2300 करोड़ कर दी गई. इतना ही नहीं, इसकी लागत राशि और बढ़ेगी. इस तमाम मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. जहां स्थानीय जनप्रतिनिधि को लोग दोषी मान रहे हैं, वहीं ओवर ब्रिज़ निर्माण को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि अब राज्य सरकार इसके लिए धन राशि मुहैया कराएगी, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा इस ज़िले के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप कांग्रेस सरकार पर भी इन दिनों मढ़ा जा रहा है. कुछ व्यापारियों का कहना है कि क्या कारण है कि नवगछिया, बेगूसराय तथा किशनगंज में राजधानी का ठहराव दिया गया, लेकिन खगड़िया में किसी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं किया गया, जो राजनीतिक साजिश का परिणाम है. वहीं पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के संयोजक सुभाष चंद्र जोशी का कहना है कि मैंने उक्त समस्या को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन तथा मांग पत्र रेलवे बोर्ड को भेजा था, लेकिन अमल नहीं हुआ है. स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस समस्या के प्रति लापरवाह हैं. इसका नतीजा है खगड़िया रेल जंक्शन पर समस्याओं का अंबार है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में सहायक वाणिज्य प्रबंधक हाजीपुर ने तमाम समस्याओं के प्रति टाल-मटोल का जबाव दिया था, जिसमें 5933/34 डिब्रूगढ़ - अमृतसर, 5715/16 किशनगंज- अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस, 15631/32 गुवाहाटी-जोधपुर, राजधानी, दरभंगा-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के ठहराव का प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया गया है, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी ठहराव नहीं हुआ है. वहीं बरौनी-कटिहार दोहरीकरण पूर्ण नहीं होने के कारण कई गाड़ियों का विस्तार नहीं किया जा रहा है. कार्य पूर्ण हो जाने के बाद औचित्य के आधार पर विचार किया जा सकता है, जिसमें रांची/टाटा के लिए नई गाड़ी का प्रस्ताव, बेगूसराय-मोकामा सवारी गाड़ी को खगड़िया और कोलकाता के लिए ट्रेन देने, बरौनी-लखनऊ का विस्तार कटिहार तक करने की मांग पर टाल-मटोल की नीति अपनाई गई है, जबकि खगड़िया जंक्शन पर उक्त गाड़ी का ठहराव अति आवश्यक है. इस मामले में सांसद दिनेश चंद्र यादव का कहना है कि खगड़िया जंक्शन एवं निर्माणाधीन रेल खंड को राशि निर्गत करने में रेल मंत्रालय भेद-भाव करता है, जबकि रेल बजट से पूर्व वैधानिक प्रक्रिया के तहत मामले को संसद में आवाज़ उठाया गया है एवं गाड़ियों के ठहराव को लेकर उनका प्रयास जारी है. वहीं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री फैसल अहमद का कहना है कि खगड़िया के विकास की सांसद को चिंता नहीं है. यदि चिंता होती, तो नवगछिया की तरह खगड़िया रेलवे स्टेशन का भी विकास होता. इन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा आंदोलन करेगी तथा जदयू एवं कांग्रेस ज़िले के साथ भेद-भाव कर रही है. आखिर मुद्दे जो भी हो, लेकिन खगड़िया जंक्शन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. इन तमाम समस्याओं के प्रति आम लोगों में आक्रोश है, जो आगामी लोकसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा बन कर उभरेगा. ■

दिनेश चंद्र यादव

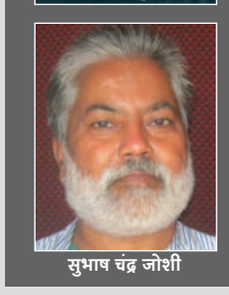

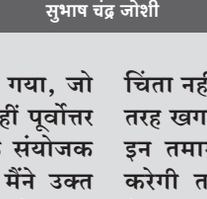

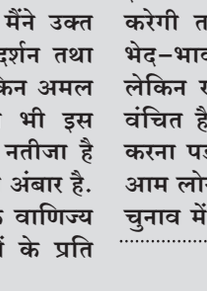

फैजल अहमद

सुभाष चंद्र जोशी

feedback@chauthiduniya.com

सुनील सौरभ

मगध

मुश्किल में जदयू-भाजपा की डगर

क्या राजद को फायदा होगा

भाजपा और राजद का गठबंधन टूटने के कारण फिलहाल क़यास यही लगाया जा रहा है कि मगध में हर हाल में राजद को ही फ़ायदा होने वाला है. और दरअसल, इसी वजह से अन्य दलों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि आख़िर फ़ायदा किस पार्टी को होगा?

भाजपा और जदयू के रिश्ते टूटने के बाद दक्षिण बिहार की राजनीतिक राजधानी गया ज़िले के 10 विधानसभा क्षेत्रों पर व्यापक असर पड़ा है. दरअसल, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर शेष नौ पर एनडीए का क़ब्ज़ा था. उत्तरी बाराचट्टी, टिकारी, ईमामगंज, शेरघाटी पर जदयू का और गुरुआ, बोधगया और वज़ीरगंज विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का क़ब्ज़ा है. सिर्फ़ बेलागंज विधानसभा क्षेत्र पर 1990 से लगातार राजद का क़ब्ज़ा चला आ रहा है. अब जबकि एनडीए टूट चुका है, तो इससे गया ज़िले के भाजपा-जदयू के वर्तमान विधायकों की सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि गठबंधन टूटने से पूरे ज़िले में फिलहाल राजद फायदे में नज़र आ रहा है. ऐसे में अगर अगले विधानसभा चुनाव तक बिहार में राजनीति की वर्तमान स्थिति क़ायम रही, तो भाजपा-जदयू के अधिकांश विधायकों को अपनी सीटें बचानी मुश्किल हो जाएगी.

गौरतलब है कि गठबंधन टूटने से बिहार की जातीय आधारित राजनीति में लालू प्रसाद के राजद को ही फायदा फिलहाल दिख रहा है. और यदि बाद में कांग्रेस का जदयू से गठबंधन होता है, तो ऐसे में भी राजद को ही फायदा होना तय है. बिहार में आधारहीन हो चुके कांग्रेस का किसी भी दल से गठबंधन होता है, तो लाभ कांग्रेस को ही होगा. गया ज़िले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एकाध को छोड़कर सभी पर राजद की स्थिति अच्छी है. मालूम हो कि राजद का सबसे बड़ा वोट बैंक यादव एग्रेसिव वोटिंग के लिए बिहार में प्रसिद्ध है. साथ में लोजपा से गठबंधन के कारण पासवान वोट भी राजद के खाते में ही है. दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों में बंटवारे के बावजूद अधिकांश राजद के खाते में आने की संभावना दिख रही है. और यदि राजपूत वोटों में भी बंटवारा हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गया ज़िले में राजद को अधिक लाभ होगा. इस प्रकार यादव+पासवान+मुस्लिम+राजपूत के वोट का कुछ प्रतिशत बंट जाने के बावजूद यदि वे एकजुट हो गए, तो गया ज़िले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जाएगा. उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजद लोजपा के ज़्यादातर प्रत्याशियों की हार हज़ार से लेकर पांच हज़ार वोटों के अंतर से हुई थी.

यह वोट अधिकांश क्षेत्रों में राजद से अलग हुए कांग्रेस के प्रत्याशियों ने काटे थे. इस बार चूंकि 17 वर्षों तक गांठ बांधकर एक साथ चुनावी मैदान में राजद-लोजपा-कांग्रेस-वामपंथी दलों को शिकस्त देने वाला जद(यू) भाजपा अलग हो चुका है, ऐसे में इससे लाभ राजद को ही मिलेगा. राजद के वोट बैंक के अलावा, क्षेत्र विशेष पर अन्य जातियों के मत भी राजद प्रत्याशियों को जातिगत आधार पर मिल सकते हैं. और यदि यही स्थिति लोकसभा चुनाव में भी रही, तो राजद मज़बूती के साथ उभर सकता है. इन्हीं जातीय समीकरण को देखकर इन दिनों गया ज़िले के अधिकांश जद(यू)-भाजपा के विधायकों के पसीने छूट रहे हैं. जद(यू) के एक वरिष्ठ नेता का तो यहां तक कहना है कि नीतीश कुमार ने अपनी ज़िद में बिहार को राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में ला दिया है. ऐसे में राजनैतिक विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि गठबंधन टूटने से किसी भी हाल में राजद को छोड़कर मगध में किसी भी दल को चुनाव में लाभ नहीं मिलने वाला है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ 17 का शेष

किसानों का शोषण कब रुकेगा?

आपके प्रस्तावित निर्माण में अधिकांश ज़मीन मेरे गांव खरहट की ली जा रही है, जिससे कि खरहट गांव की आवासीय और खेतिहर ज़मीन रेल लाइन और सड़क में चली जाएगी और यह पुल हमारे गांव के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी. आसपास के ग्रामीण बताते हैं कि खरहट और इसके आसपास की अधिकांश ज़मीन नारायण यादव की ही है. कुछ ख़ुद की है और कुछ पर उन्होंने क़ब्ज़ा कर रखा है, लेकिन रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार ने उनके दलीलों पर ध्यान ही नहीं दिया.

जब लालू प्रसाद रेल मंत्री बने, तो श्रीनारायण यादव की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हुई पुल का एलाइनमेंट बदल दिया गया. खरहट तो बच गया, पर आठ-दस गांवों की बहुफसली और आबादी बहुल ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है. हालांकि एलाइनमेंट चेंज होने से इसका विरोध जारी है. रेल मंत्री रहते लालू का काफिला जब बेगूसराय से गुज़र रहा था, तो साहेबपुरकमाल की जनता ने उनके काफिले को रोक लिया और एलाइनमेंट चेंज किए जाने का वह विरोध करने लगी, लेकिन लालू के सामने लोगों की एक न चली. उस समय लालू ने कहा कि एलाइनमेंट चेंज करने का फ़ैसला तकनीकी विशेषज्ञों का है. अब यह सोचने की बात है कि क्या रेल मंत्री के बदलते ही तकनीकी विशेषज्ञों के फ़ैसले भी बदल जाते हैं? यहां के कौशल किशोर सिंह पेशे से अधिवक्ता हैं और शुरुआत से ही रेल मंत्रालय के इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं. पूर्व मध्य रेल से उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत यह जानना चाहा कि आखिर इसके पीछे क्या वजहें हैं कि मुंगेर रेल सह सड़क पुल के लिए रेलवे अपनी ज़मीन को छोड़ कर किसानों एवं दलितों की भूमि का अधिग्रहण कर रही है. इसका जवाब बड़ा ही टालू मिला. पूर्व मध्य रेल कहती है कि पहले वाली एलाइनमेंट पर कर्व अत्यधिक शार्प था, जो इस पुल पर वांछित नहीं है और तकनीकी कारणों से पुल के पहुंच पथ का एलाइनमेंट बदला गया है, पर कौशल किशोर जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि नीतीश के समय के तकनीकी विशेषज्ञों का निर्णय गलत था. इससे ज़्यादा कर्व पर जापान सहित कई देशों में रेलवे स्टेशन बने हैं. गौरतलब है कि कौशल शुरू से ही स्थानीय गरीब-गुरबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. वह कहते हैं कि सिर्फ अपने नेता और उनके गांव को बचाने के लिए लालू जी ने आठ-दस गांवों की बली चढ़ा दी, जबकि पहले वाले एलाइनमेंट के रास्ते में रेलवे की पर्याप्त ज़मीन है. कबीना मंत्री रहे श्रीनारायण यादव ने वे सारे तिकड़म लगाए, जिससे कि उनका गांव और उनकी ज़मीन बच जाए. जब रेल मंत्री रहते नीतीश ने उनकी बात नहीं मानी, तो यादव के लोगों ने निर्माण कार्य में ही अड़चन डालना शुरू कर दिया. यही वजह है कि पुल निर्माण का काम साहेबपुरकमाल से शुरू न होकर मुंगेर से शुरू हुआ. इस निर्माण कार्य में न केवल गरीब-गुरबों की विभागीय

अनदेखी हो रही है, बल्कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने भी मनमानी की है. पुल निर्माण की दिशा बदलने से गंगा की धारा भी परिवर्तित हो गई है. दरअसल, धारा को बैरिकेटिंग कर दिशा बदली गई, ताकि सूखे या कम पानी में पीलर बना सकें. गंगा की मौलिकता से छेड़-छाड़ का नतीजा यह हुआ कि साहेबपुरकमाल की हज़ारों एकड़ भूमि कटाव क्षेत्र में आ गई. मालूम हो कि कभी इस इलाक़े में दर्जनों ईंट भट्ठे हुआ करते थे, जो कि इलाक़े के लोगों के रोज़गार का बेहतर विकल्प था. यहां से ईंट की सप्लाई झारखंड तक होती थी. आज स्थिति यह है कि कटाव और गंगा की धारा के बदलने से यहां का ईंट उद्योग लगभग समाप्त हो चुका है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रेल मंत्री नीतीश के फ़ैसले को बाद के रेल मंत्री लालू ने बदल दिया. नीतीश कुमार हमारी गुहार नहीं सुन रहे हैं. एक ग्रामीण का कहना है कि मंत्री जी (श्रीनारायण यादव) ने जैसा चाहा, वैसा ही हुआ. पुल विलंब से बनेगा, उसका फायदा मंत्री जी को होगा. लोग मुंगेर से आने-जाने के लिए उनके ही स्टीमर का इस्तेमाल करेंगे.

पुल निर्माण में लगी कंपनियां भी मजदूरों का शोषण करने से बाज नहीं आईं. ये कंपनियां पुल निर्माण से अक्टूबर 2011 तक यहां काम करने वाले मजदूरों को रोज़ाना अस्सी रुपये ही मजदूरी देती थीं. बाद में जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया, तो उनकी मजदूरी बढ़ा कर रोज़ाना 144 रुपये कर दी गई. भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर यहां की जनता में काफी आक्रोश है. इस पिछड़े इलाक़े के मजदूरों को केंद्र और राज्य सरकार में अंतर नहीं पता. दरअसल, ये सिर्फ इतना जानते हैं कि जो हो रहा है, वह सरकार कर रही है. सरकार से उन्हें डर भी है. यहां के अशिक्षित लोगों की धारणा यह है कि सरकार से कौन लड़ सकता है, वह जो चाहेगी, वही करेगी. ज़िला सचिव दिवाकर कहते हैं कि हमारे इलाके के लोग अशिक्षित हैं, यही वजह है कि उसे कंपनी और स्थानीय प्रशासन भी ठगती रही है और एलाइनमेंट चेंज होने की वजह से किसानों की बहुफसली ज़मीन जा रही है. यह अधिग्रहण किसान विरोधी है. इसके लिए दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए. दिवाकर साफ शब्दों में कहते हैं कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलेगा, हम परियोजना को पूरा नहीं होने देंगे.

तफ्तीश से यह साफ पता चलता है कि क्षेत्र में पुल निर्माण को लेकर प्रशासनिक भ्रष्टाचार और पैसों की लूट मची हुई है. कई किसान ऐसे हैं, जिनकी ज़मीन तो अधिगृहित कर ली गई है, लेकिन उनके मुआवजे को आपस में ही बंदरबांट कर लिया गया. कई ऐसे मामले भी हैं, जिनमें ज़मीन किसी और की है और मुआवजा किसी और को दे दिया गया है. बहरहाल, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी भूमि अधिग्रहण के मामले में यह कहा है कि छोटे किसानों को ऐसी कार्रवाई से बचाना चाहिए, लेकिन इस मामले में ज़्यादातर छोटे किसान ही प्रताड़ित हो रहे हैं. न केवल उन्हीं के घरों को उजाड़ा जा रहा है, बल्कि बहुफसली ज़मीन को भी बर्बाद किया जा रहा है. इलाक़े के फलदार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी की जा रही है. मुआवजे को लेकर किसानों के साथ दो-हरा रवैया भी अपनाया जा रहा है. जानकार बताते हैं कि सारण रेल परियोजना के लैंड लूजर के आश्रितों को रेलवे ने नौकरी देने का आदेश जारी किया है और यहां के किसानों के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है. यह भी बताते हैं कि इसी स्टेट में नवीनगर में जिन किसानों की ज़मीन ली जा रही है, उन्हें सरकार इक्कीस लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दे रही है.

शुरुआत के दिनों में निर्माण कार्य राष्ट्रीय रेल निगम ही करवा रही थी, लेकिन बाद में यह ज़िम्मेदारी हाजीपुर मंडल को दे दिया गया. यहां निर्माण कार्य में लगी कंपनियों पर भी सवालिया निशान उठता रहा है, चाहे वह विशाल कंस्ट्रकशन हो या गैमन इंडिया. गैमन इंडिया तो कई शहरों में बैन भी है. मालूम हो कि 2009 में दिल्ली मेट्रों की निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद दो साल तक के लिए दिल्ली मेट्रो ने गैमन इंडिया को बैन कर दिया था. 26 पिलर की सहायता से बनने वाली इस पुल का एलाइनमेंट चेंज होने से चार पिलर और बढ़ाया गया, 921 करोड़ की शुरुआती स्वीकृति के बाद इसकी लागत में भी वृद्धि हुई. फिलहाल 700 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो गई है और इसकी लागत बढ़कर 2363 करोड़ हो गई है. रेल विभाग दावा करती है कि पुल 2014 तक बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन ऐसा फिलहाल लगता नहीं है. पूर्व सांसद ब्रह्मानंद कहते हैं कि यहां पैसों की लूट मची हुई है. पुल के लिए मुंगेर प्रमंडल की जनता को अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ 17 का शेष

लापरवाह कौन?

चूक को बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा. और अगर चूक हुई, तो ज़िम्मेदार सेवक पर कार्रवाई होगी. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आतंकी हमले की जो आशंका थी, अंततः वही हुआ. ऐसे में किसे दोषी ठहराया जाए और किस पर कार्रवाई की जाए, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है?

बोधगया के लोग इन बातों से नाराज़ हैं कि जब आम लोगों को मीडिया के माध्यम से ब्लास्ट की जानकारी थी, तो सरकार और ज़िला प्रशासन उस समय क्या कर रही थी, जबकि बोधगया से कुछ ही दूरी पर बिहार सैन्य पुलिस 3 का मुख्यालय और सीआरपीएफ कैंप स्थापित है. ज़िला पुलिस में भी सुरक्षा बलों और पदाधिकारियों की बड़ी फौज है. बोधगया के लोग सिरियल बम ब्लास्ट की घटना से कितने आहत हैं, इसका एहसास राज्य के मुखिया नीतीश कुमार को तब हुआ, जब घटना के बाद 7 जुलाई को वे बोधगया पहुंचे. बोधगया पहुंचने पर नीतीश कुमार को भाजपा के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. कुल 9 ब्लास्टों में महाबोधि मंदिर परिसर में 4, तेरगा बौद्ध मठ में 3, अन्य 2 स्थानों पर हुए सीरियल ब्लास्ट होने और दो विदेशी बौद्ध भिक्षुओं के घायल होने की सूचना पूरी दुनिया में फैली. अब इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका असर बोधगया के लोगों की रोज़ी-रोटी पर भी पड़ेगा.

दरअसल, लोगों को आशंका है कि इस घटना के बाद विदेशी श्रद्धालुओं का आना कम हो सकता है. घटना के बाद बोधगया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने यह दावा भी किया कि बम ब्लास्ट की साजिश में शामिल लोगों को शीघ्र पकड़ लिया जाएगा, लेकिन यहां एक अहम सवाल यह है कि पूर्व खुफिया सूचना के बाद भी महाबोधि मंदिर की सुरक्षा की चूक का ज़िम्मेदार किसे माना जाए? इस विषय पर कोई कुछ भी नहीं कह रहा है. हालांकि

बोधगया बम ब्लास्ट में आतंकियों की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल, बोधगया में जो बम ब्लास्ट किया गया और जो ज़िन्दा बम ज़ब्त किए गए, वे कम शक्तिशाली माने जा रहे हैं. समय भी सुबह का चुना गया, जब मंदिर तथा उसके आसपास भीड़ ज्यादा रहती है. सबसे बड़ी बात यह है कि बोधगया के ऑफ सीजन में यह घटना घटी. सच तो यह है कि पर्यटन सीजन में यह घटना घटी होती, तो जान-माल की क्षति का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता. यहां एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आतंकियों की मंशा सिर्फ दहशत फैलाने की थी? क्या इसमें स्थानीय लोगों की संलिप्तता थी? इन बातों को लेकर भी लोगों में चर्चा है. इस घटना को लेकर बीटीएमसी के एक सदस्य डॉ. अरविंद कुमार सिंह बताते हैं कि महाबोधि मंदिर की सुरक्षा बहुत ही लचर थी. वर्तमान कमिटि ने ही महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को कुछ दुरुस्त किया है. बोधगया बम ब्लास्ट के बाद आने वाले अनेक बौद्ध देशों के पर्यटकों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है, जिससे कि बोधगया के टूर ऐंड ट्रैवल तथा होटल व्यवसाय को भारी नुक़सान हो रहा है. गौरतलब है कि बोधगया में प्रत्येक साल सात लाख से अधिक विदेशी आते हैं. यहां 55 बौद्ध मठ हैं और क़रीब एक दर्जन बौद्ध मठ अभी निर्माणाधीन हैं, जबकि विश्वदाय धरोहर महाबोधि मंदिर प्राचीन काल से ही बौद्धों की आस्था का केंद्र रहा है. बोधगया के पूर्व विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा है कि धमाकों की घटना से राज्य की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हुई है. उन्होंने महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के मामले में राज्य सरकार को ही लापरवाह बताया.

बोधगया में विस्फोट होगा, इसका खुलासा अक्टूबर 2012 में हैदराबाद में आतंकी हमले के बाद पकड़े गए आतंकवादी सईद मक़बूल ने किया था. उस समय पदभार संभाल रहे तत्कालीन एसएसपी विनय कुमार दिल्ली भी गए थे. एसएसपी ने भी तब आतंकवादी मक़बूल से कड़ी पूछताछ की थी. एसएसपी को मक़बूल ने जानकारी दी कि आतंकी हमले के लिए वैसे स्थानों को चिन्हित किया जाता है, जहां दुनिया के तमाम लोगों का ध्यान रहता है. मक़बूल ने ख़ुलासा किया था कि वह ख़ुद बोधगया नहीं गया है, लेकिन बोधगया की चर्चा हुई है. इस ख़ुलासे के बाद गृह मंत्रालय की नींद खुली थी. दिल्ली से लौटने के बाद एसएसपी ने डीजीपी व अन्य अधिकारियों से मुलाक़ात कर उन्हें आतंकी हमले की सूचना से संबंधित जानकारी भी दी थी. अब सरकार सफाई कुछ भी दें, लेकिन पूरा मामला बिहार सरकार तथा सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का ही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

वामपंथियों ने किया सड़क जाम

बगहा पुलिस फायरिंग में मृतक एवं घायल लोगों को न्याय दिलाने के लिए वामपंथी कार्यकर्ताओं नेअनुमंडल गोगरी के महेशखूंट, इसरी चौक, आलम बाजार, महद्दीपुर सहित अन्य जगहों पर सड़क जाम कर ग़रीब लोगों पर पुलिस अत्याचार का विरोध और मजदूर वर्ग के साथ न्याय की मांग की. वामपंथी नेता निलेश कुमार सिन्हा ने बिहार बंद को सफल बताते हुए कहा कि ग़रीब एवं मजदूर वर्गों पर होने वाले अत्याचार वामपंथी कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि अगर दोषी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी पर कार्रवाई नहीं किया गया, तो वामपंथी नेताओं द्वारा विरोध जारी रहेगा. इस अवसर पर बिंदेश्वरी साह, सुरेंद्र साह, वासुदेव विधाता एवं चमकलाल सिंह समेत दर्जनों वामपंथी नेता उपस्थित थे.

जल-जमाव से परेशानी

बारिश आते ही नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के कई जगहों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न होने लगी है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. नगरवासी दीपक कुमार ने बताया कि बारिश होने से नगर पंचायत के वार्ड नं.-19 में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है. इससे स्थानीय लोगों में महामारी का ख़तरा बना रहता है. वहीं सुमन कुमार ने बताया कि कई बार अधिकारियों को आवेदन प्रेषित कर वार्ड नं.-18 स्थित गड्ढे की सफाई करवाने की मांग की गई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है. *– उधव कुमार*

उत्तराखंड पीड़ितों की मदद के लिए संघ की गुहार

उत्तराखंड की विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों की मदद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों शहर में भिक्षाटन किया. सीतामढ़ी ज़िले के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय स्थित कर्पूरी चौक से शुरू भिक्षाटन कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने झोली फैला कर लोगों से पीड़ितों की मदद के लिए गुहार लगाई. ज़िला कार्यवाहक केदार प्रसाद व नगर कार्यवाहक राम शंकर चौधरी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हेमंत गिरी, राज कुमार जोशी, ऋषिकेश चौधरी, संजय कुमार झा, लालबाबू पासवान, नवीन कुमार सिंह, संतोश कुमार, साहिल भटनागर, अभिषेक कुमार व प्रिंस कुमार समेत और और लोग उपस्थित थे. *– गोविंद कुमार*

राजद का परचम लहराएगा

राजद कार्यकर्ता हरि नारायण राय ने पिछले दिनों राजग में आई खटास को होनी क़रार दिया और कहा कि ऐसा बहुत पहले ही होना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ देर जरूर हुई है. उन्होंने कहा कि आने वाला समय राजद के पक्ष में होगा. राय ने कहा कि हमने जनसेवा को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया है. गांव की मेड से लेकर विधान सभा क्षेत्र की हर एक गली तक लोगों के बीच रहे हैं. उन्होंने राजद सुप्रीमो के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से जनसेवा की कमान मिलने की पूरी उम्मीद है. *– विभा*

रिसर्च कोलकाता भेजी गई

प्रतिभाशाली नव प्रवर्तक प्रफुल्ल चंद्र घोष ने एक आविष्कार किया है. इसे पेटेंट करा कर सिस्टम फॉर पोल्यूशन कंट्रोल गार्डेनिंग इनोवेशन को सूचीबद्ध कर प्रकृति एवं जन हितों में प्रोत्साहित करने संबंधित इंडियन पेटेंट कार्यालय के समक्ष प्रमाणित ब्योरे के साथ प्रस्तुत किया गया है. पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या को कम करने वाला यह सिस्टम घरों में सिंक बेसिन द्वारा उत्सर्जित पानी, किचन एवं कचड़ों से संबंधित है, जो कि नल पाइप के पानी प्रवाह से स्वचालित एक सिस्टम है. उक्त सिस्टम को पिछले वर्ष अंचल कार्यालय कोलकाता भेजी गई है.

कोचिंग के सभी छात्र टॉप

पीके इन्स्टीटय़ूट ऑफ साइंस के 20 छात्र मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है. छात्र जगदीप कुमार, अर्पित कश्यप, अभिषेक कुमार और दीपक कुमार ने बताया कि निदेशक पीके झा के सफल मार्ग दर्शन में हमारे लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी, इसलिए हम बोर्ड में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके. वहीं निदेशक पीके झा ने बताया कि पिछले वर्ष ही कोचिंग शुरू किया गया था, जिसमें मात्र 20 छात्र थे. इनमें से सभी ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है. ■ *– नंदकिशोर शर्मा*

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

22 जुलाई–28 जुलाई 2013

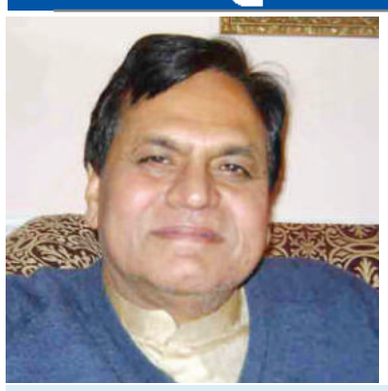

> एनडीए से जदयू के अलग होने को हिंदू–मुस्लिम के आईने में वही लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने में लगे हुए हैं. ऐसे में यह स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि सांप्रदायिकता को रोकना सिर्फ मुसलमानों के वश में नहीं है, बल्कि इसे हिंदू और मुसलमान दोनों मिल कर ही रोक सकते हैं और उसे हरा सकते हैं.

50 हजार गन्ना किसानों को भुगतान नहीं

दोषी कौन, जिला प्रशासन या राज्य सरकार?

किसानों को आज भी उनका वाजिब हक नहीं मिलता. सीतामढ़ी ज़िले के गन्ना किसानों को कम मूल्य पर क़िस्त दर क़िस्त पैसे का भुगतान किया जाता है. यहां क़रीब 50 हज़ार गन्ना किसानों का लगभग 40 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान लंबित है. दोषी कौन है, जिला प्रशासन या राज्य सरकार?

फैला प्रदूषित काला पानी

धरना में शामिल मोर्चा कार्यकर्ता

वाल्मीकि कुमार

भारत–नेपाल सीमा स्थित सीतामढ़ी ज़िले को आज़ादी के बाद से अब तक एक अदद औद्योगिक इकाई नसीब नहीं हो सकी है. यह महज़ एक संयोग ही है कि यहां रीगा सुगर कंपनी की स्थापना हो चुकी थी. दरअसल, यहां मिल की स्थापना की वजह से ही सीतामढ़ी ज़िला समेत आस–पास के ज़िले के किसान भी लाभान्वित होते रहे हैं, लेकिन हाल के दशकों में मिल प्रबंधन एवं किसानों के बीच भुगतान समेत अन्य बिंदुओं पर अक्सर तक़रार होती रही है. हैरानी की बात तो यह है कि किसानों को गन्ना मूल्य के बक़ाया भुगतान को लेकर मिल प्रबंधन के अलावा, ज़िला प्रशासन व राज्य सरकार से लगातार गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी इन्हें भुगतान नहीं किया जाता.

पिछले दिनों ज़िला मुख्यालय डुमरा स्थित समाहरणालय के समक्ष किसानों ने संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया. कार्यक्रम के दौरान मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. आनंद किशोर ने सवाल यह उठाया कि गन्ना के मूल्य निर्धारण में बाजिव लागत की अनदेखी की जा रही है, जबकि पूर्व में उत्तर प्रदेश के मूल्य के हिसाब से निर्धारण किया जाता रहा है. अब हाल यह है कि यहां यूपी से 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल कम मूल्य का निर्धारण किया जा रहा है. और तो और, निर्धारित मूल्य का भुगतान भी बिना आंदोलन के नहीं होता है. इसके अलावा, किसानों को पैसा क़िस्त दर क़िस्त में बांट कर भुगतान किया जाता है. वक़्त पर पैसा नहीं मिलने के कारण किसान अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते. समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण उन्हें अगली फसल उगाने में भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. डॉ. किशोर की मानें, तो मिल क्षेत्र के क़रीब 50 हज़ार गन्ना किसानों का लगभग 40 करोड़ से अधिक भुगतान अब भी लंबित है. मिल प्रबंधन की मनमानी का आ़लम यह है कि 245, 255 एवं 265 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य के निर्धारण के बाद भी किसानों को भुगतान दो सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से, और वह भी टुकड़ों में किया जा रहा है.

दरअसल, भुगतान केवल उसी को किया जा रहा है, जिसका बैंक खाता है. बताया गया है कि मोर्चा की मांग पर ही काउंटर भुगतान शुरू किया गया. गन्ना किसानों की समस्या को लेकर सेवा यात्रा के क्रम में मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष शंकर मंडल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी सौंपा था. मिल प्रबंधन द्वारा इन किसानों पर गन्ने की घटतौली, प्रभेद में हेरा–फेरी और चालान वितरण में अनियमितता समेत अन्य आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले की अब तक न तो जांच हो सकी है और न ही इसमें कोई सुधार की जा सकी है. पिछले पेराई सत्र में मिल प्रबंधन ने तो हद कर दी, क्योंकि किसानों को भुगतान के बदले में चीनी ही लेने को बाध्य कर दिया गया था. मोर्चा ने हरा–भरा मिश्रित उर्वरक के मूल्य में 3 सौ रुपये प्रति वैग मूल्य बढ़ोत्तरी भी वापस लेने की मांग की है. किसानों ने रीगा चीनी मिल की डिस्टलरी इकाई द्वारा जल प्रदूषण फैला कर क्षेत्र में आम लोगों को परेशान किये जाने की बात भी उठाई है. बताया गया है कि डिस्टलरी के प्रदूषण से पुरानी धार मनुश्यमारा नदी के जल ने रीगा से लेकर परसौनी, बेलसंड व रुन्नीसैदपुर प्रखंड के करीब 25 से 30 किलो मीटर के भू–भाग को कालापानी क्षेत्र में तब्दील कर दिया है. ऐसे में, आलम यह है कि अब काला पानी पशुओं के उपयोग के लायक भी नहीं रह गया है. साथ ही हज़ारों एकड़ ज़मीन में कृषि कार्य भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है. इसके बाद भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आंखें नहीं खुल रही हैं. स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक किसी में भी इस समस्या के प्रति गंभीरता दिखाई नही पड़ती. संभव है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ज़िले के किसान अपनी समस्या को पुरज़ोर तरीक़े से उठाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

मॉडल विश्वविद्यालय बनाने की कवायद

कुछ साल पहले तक दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों की हालत काफी खराब थी. यहां न तो एकेडमिक कैलेंडरों का पालन किया जाता था और न ही शैक्षणिक गतिविधियां होती थीं. हालांकि पिछले कुछ वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की स्थिति कुछ ठीक हुई है. अब बात अगर दरभंगा की करें, तो यह नगर मिथिलांचल की सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब यहां के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वीरानी छाई रहती थी. हालांकि हालात अब काफी बदल चुके हैं.

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में इन दिनों छात्रों की काफी गहमा–गहमी देखी जा सकती है. यहां के इस बदलाव के बारे में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. विजय प्रसाद सिंह बताते हैं कि यह परिवर्तन एक दिन का नतीजा नहीं है. उन्होंने कुलपति डॉ. समरेंद्र प्रताप सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शिता का नतीजा है कि आज मिथिला विश्वविद्यालय अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः हासिल करने में कामयाब हुआ है. उनके अनुसार, विश्वविद्यालय समेत सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में पठन–पाठन समेत अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां न केवल सुधरी हैं, बल्कि और वहां एकेडमिक कैलेंडर का सही तरह से पालन भी किया जा रहा है. इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों से लगातार दीक्षांत समारोह भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है. उनके अनुसार, विश्वविद्यालय में कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनका फायदा छात्रों को मिल रहा है. साथ ही डिस्टेंस एजुकेशन, यानी दूरस्थ शिक्षा के मामले में भी यह विश्वविद्यालय बिहार का मॉडल विश्वविद्यालय बन गया है. उनके मुताबिक़, विश्वविद्यालय मुख्यालय के अलावा, पांच कॉलेजों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो रही है. साथ ही विभिन्न विषयों पर कई राष्ट्रीय सेमिनार का सफल आयोजन भी एक बड़ी उपलब्धि है.

डॉ. सिंह के अनुसार, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव भी सरकार के पास भेजा गया है. यह पूछे जाने पर कि विश्वविद्यालय में वर्षों से लंबित छात्रसंघ चुनाव कराने के बारे में उनकी क्या राय है, तो उन्होंने बताया कि अगले साल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तरीय छात्रसंघ चुनाव कराने की योजना है. उनके मुताबिक, छात्रसंघ का चुनाव होने से न केवल सीनेट और सिंडिकेट में छात्र प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, बल्कि इस नई सोच का फायदा भी अततः विश्वविद्यालय को ही मिलेगा. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

मोदी नाम के डायनामाइट को ध्वस्त करना ज़रूरी : अली अनवर

जनता दल युनाइटेड के वरिष्ठ नेता और ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष अली अनवर ने चौथी दुनिया को साक्षात्कार में बताया कि उनकी पार्टी ने भाजपा से नाता तोड़ कर नरेंद्र मोदी नाम के डायनामाइट को ध्वस्त करने का जोखिम उठाया है...

अब जबकि नरेंद्र मोदी प्रकरण के बाद जदयू भाजपा से अलग हो गई है, तो ऐसे में बिहार में मुसलमानों का क्या रुझान होगा?

देखिए, बात न ही मुसलमानों की है और न ही हिंदुओं की. दरअसल, यह मुद्दा इस देश में एक ऐसी शक्ति को रोकने का है, जो भारत को थियोक्रेटिक स्टेट में बदलना चाहती है. एनडीए से जदयू के अलग होने को हिंदू–मुस्लिम के आईने में वही लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने में लगे हुए हैं. ऐसे में यह स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि सांप्रदायिकता को रोकना सिर्फ मुसलमानों के बस में नहीं है, बल्कि इसे हिंदू और मुसलमान दोनों मिल कर ही रोक सकते हैं और उसे हरा सकते हैं. अब, जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तो हमारा स्पष्ट लक्ष्य अगर हिंदू सांप्रदायिकता है, तो मुस्लिम सांप्रदायिकता पर भी हम उसी शक्ति से चोट करने की बात करते हैं, क्योंकि हिंदू महासभा ने भी सांप्रदायिकता को उतना ही पाला है, जितना मुस्लिम लोगों ने उसे बढ़ावा दिया है. ऐसे में सेक्युलर भारत की आत्मा की रक्षा हिंदू–मुस्लिम मिलकर ही करेंगे. जहां तक मोदी जैसे निरंकुश मानसिकता के नेता को भाजपा द्वारा आगे करने की बात है, तो स्वाभाविक तौर पर मुसलमान जदयू के इस फैसले से खुश हैं.

तो क्या मुसलमान अपनी खुशी को अपने वोट के माध्यम से प्रकट करेंगे?

नरेंद्र मोदी को भाजपा आज ठीक इसी रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, जिस तरह से उसने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी को पेश किया था. तब लालू यादव ने उन्हें गिरफ्तार करवाया था. आज की तारीख में नीतीश जी ने मोदी के प्रोजेक्शन के बैलून में जबर्दस्त पलीता लगाने की कोशिश की है. यह बैलून निश्चित तौर पर फुस्स हो जाएगा. ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं कि मुसलमान स्वाभाविक तौर पर सेक्युलरिज्म की रक्षा करने वालों का ही साथ देंगे.

लेकिन सेक्युलरिज्म के अलमबरदार होने का दावा तो राजद, लोजपा, वामपंथी दल और कांग्रेस भी करती हैं, तो क्या मुसलमान उनकी तरफ नहीं जाएंगे ?

सेक्युलरिज्म की रक्षा के मामले में मुसलमान टेक्निकल वोट करेंगे. वे देखेंगे कि निरंकुश, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली और देश को तोड़ने वाली शक्तियों को कौन हरा सकता है. और इन बातों का खयाल रख कर ही वे अपना वोट देंगे, क्योंकि उन पर भी हिंदू भाइयों की तरह ही देश के सेक्युलर कैरेक्टर की रक्षा करने की जिम्मेदारी है.

इसका मतलब यही हुआ कि मुसलमानों के वोट उन तमाम लोगों को मिलेंगे, जो आपके अनुसार सेक्युलरिज्म के मुहाफिज होंगे?

वे देखेंगे कि किस पार्टी का उम्मीदवार सशक्त है. वे बंटेंगे नहीं. अपने वोट को बर्बाद नहीं होने देंगे.

17 सालों तक भाजपा के साथ रह कर सत्तासुख लेना और ऐसे समय में भाजपा से अलग होना, जबकि पूरा देश कांग्रेस के भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों के कारण उससे नाराज है. यह कैसा फैसला है?

नीतीश जी ने बहुत जोखिम भरा फैसला लिया है. उनका यह फैसला शेर की मांद में हाथ डालने जैसा है. यह आदमी शहीद होने का जोखिम उठाने को तैयार है. अगर हम शहीद भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में कभी देने को तैयार नहीं हो सकते, जो बतौर मुख्यमंत्री दंगे और नरसंहार में शामिल हो. दरअसल, मोदी के व्यक्तित्व में डायनामाइट है और वह संघ के स्वाभाविक प्रतिनिधि हैं. जदयू ऐसे डायनामाइट को ध्वस्त करने को तैयार है, क्योंकि ऐसे आदमी को आगे करने का मतलब है इस देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति को जन्म देना. इस देश का जन मानस सेक्युलर डेमोक्रेटिक है. यही हमारे देश का धर्म और हमारा ईमान है. नीतीश जी ने इसकी हिफाजत का बिगुल फूंका है और इसीलिए नतीजा आज यह है कि आज इस देश की राजनीति इसी आधार पर पोलराइज्ड हो गई है. ■

इर्शादुल हक़

feedback@chauthiduniya.com